हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 मार्च, 1991

खण्ड 1, अंक 10

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 14 अगस्त 1991

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(10)1
नियम 45 के अधीनसदन की मेज पर खे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(10)21
विभिन्न विशयों को उठाया जाना	(10)24
ध्यानकर्शण प्रस्ताव–	

विदे ाी प ुधनफार्म, भिवानी में गायों के मरने संबंधी	(10)30
वक्तव्य–	
सहकारिता मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानकर्शण प्रस्ताव संबंधी	(10)31
राज्यपाल के संदे ा	(10)33
समितियों की रिपोर्टस पे ा करना–	
कमेटी और पब्लिक अकाउड्स की 31 वीं ओर 32वी रिपोर्टस	(10)33
कमेटी और सुबोडिनेट लैजिस्ले ान की 22वी रिपोर्ट	(10)33
गैर सरकारी सकल्प (पुनराम्भ)–	
प्रेशित माल पर कर संबंधी	(10)34
श्रीमती सुशमा स्वराज, राज्य सभा सदस्य का स्वागत	(10)58
गैर–सरकारी संकल्प (पुनराम्भ)	(10)58
वाक–आउट	(10)75
गैर सरकारी सकुंल्प (पुनरारम्भ)	(10)75

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 14 मार्च, 1991

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हर मोहिन्दरसिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब सवाल होगे।

Remittance of Loans

233 Sh. RAttan Lal Kataria: Will the Minister for Co operative be pleased to state the total amount of loan remitted by Government under the :Loan Waiving Scheme" in the State the period from June, 1987 to date to-date together with the number covered under the said scheme category-wise?

सहकारिता मंत्री (श्री धीर पाल सिंह): जून 1987 से ता–तारीख तक के समय में 266.05 करोड़ रूपए की रा ि ा के कर्जे ऋण नीति योजना के अधीन ाज्य व भारत सरकार द्वारा माफ किए गए। 1036289 व्यक्ति अलग–अलग के अधीन लाभान्वित हुए।

लाभान्वित व्यक्त्यें को कैटगरीवाईज विवरण देने से इतना लाभ नही जितना कि इसमें समय व श्रम लगेगा क्योंकि ऐसा विवरण बनान में लाख व्यक्तियों के रिकार्ड देखना पड़ंगा जिनमें

काफी संख्या ऐसे व्यक्तियों की है जो कई अन्य ऐसी एजेन्सियों से लाभान्वित हुए हैं जो राज्य सरकार के नही है।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि 266.06 रूपए के कर्जे माफ हुए। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि माफ हुए है। और दूसरी तरफ अम्बाला जिलें में छः किसानों को खाद की कोठरी कर दिया क्योंकि उनसे कर्जा वसूल करना था। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जिनके माफ नही हुए उनसे तो कर्जा वसूल होगा ही। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया: * * * *

Mr. Speaker: This is not supplementary. You are going out of the track. Please take your seat. It is not to be recorded.

डा0 हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री मोदय ने बतायाहै कि 10 लाख 36 हजार 289 लोगों के कर्जे इस स्कीम के तहत माफ हुए है। सरकार की जा कर्जा माफी की स्कीम थी, उसमे ंबताया गया था कि कुछ लेागो ंके ब्याज माफ कि ए गए औश्र कुछ अंसल माफ हुए और कंडी ान यह थी कि जिन लोगों के असल माफ माफ हुए है उनको ब्याज जमा कराना पड़ेगा आथ्र जिनके ब्याज माफ हुए हैं उनको असल जमा कराना पड़ेगा। क्या

मंत्री महोदय बताने की कृपा करकेगे कि इस कंडी ान पर अमल करके ऐक्युअल कितने लोगों केा लाभ हुआ?

श्री धीर पाल सिहः स्पीकर साहब, ऐक्चुअली जिन लोगों को लाभ हुआ है उन्की की संख्या मैने बताई है।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया है क 266.05 करोड़ रूप्ए के कर्ज माफ किए गए। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेगे कि कर्जा माफ करने का क्राईटेरिया क्या था, क्या कोई डेट बाउंड प्रोग्राम था? मेरे कहने कामतलब यह है कि किस क्राइद्वरिया के तहत यह कर्ज माफ किए गए?

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, तीन नीतियों के तहत कर्जे माफ किए गए थे।

श्री सूरज भानः स्पीकर साहब, कर्जे माफी की स्कीम में कुछ लाकूना रहा है। असल में जो ईमानदारी से कर्ज की कि त देना चाहे थे उनका तो कर्जा माफ नही और जिन्होने कर्जा लेकर नही दिया उनके कर्जे माफ हुए हैं क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि जो लोग ईमानदारी से कर्जा देना चाहित थे उनमे ंसे कितने लेागों के कर्जे माफ हुए?

श्री किरपा राम पुनियाः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि सैन्ट्रल कोआप्रेटिव बैक के कितन अमाउन्ट का लौन माफ हुए, लैड डिवैलपमैंट बैक के कितने अमाउन्ट क लोन

माफ हुए और कामि ायल बैंक के कितन अमाउन्ट के लोन माफ हुए तथा गवर्नमैंट आफ इंडिया से कितनी सहायता आई?

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, सहकारी बैक के 94 करोड़ 22 लाख 23 हजार के लोन वर्श 1990–91 में माफ हुए ओर इसका लाभ 2 लख 23 हजार 903 लोगों हो हुआ। हरियाणा सहकारी विकास बैंक के 34 करोड़ 41 लाख 16हजार अमाउन्ट के लोन माफ हुए और 23 हजार 8 सौ 34 लोगों को लाभ हुआ। इस प्रकारसे वर्श 1990–91 में 128 करोड़ 63 लाख 39 हजार रूपए के कर्जे माफ हुए ओर 2 लख 97 हजार 764 लोगों का लाभ हुआ। कामि ायल बैक्स के 95 करोड़ 56 लाख 36 हजार रूपए के कर्जे माफ हुए और 2 लाख 71 हजार 900 आदमियों को लाभ हुआ। स्पीकर साहब, जिस समययह स्कीम हमारे वित्त मंत्री जी ने हाउस मे ंरखी तो उनके क्षेत्र में कुछ किसानों दोस्तो ने दिवालिया घोशित कर दिया और दिवालियापन घोशित करके कोर्ट में अपील दायर कर दी थी। जब इस स्कीम को लागू करने की बात आई तो हमने इसका विरोध भी किया था क्योंकि उस समय हरियाणा प्रदे ज्ञ मे ंएक भी कसान को लाभ होने वाला नही था। कंडी ान यह थी कि सभी बैकों को दस हजार से ज्यादा कर्जा नही होना चाहिए और दो गिरदावरी सूखे से प्रभावित होनी चाहिए। इस तरह की स्कीम थी। मैन ओर चौधरी हुकम सिंह (चीफ मिनिस्टर साहब) ने चौधरी देवी लाल से रिक्वैस्ट करके इस स्कीम में ढील दिलवाई क्योकि असल स्कीम के तहत किसानो को लाभ नही हो रहा था।

श्री किरपा राम पुनियाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि 266.06 करोड़ रूपए के कर्ज ऋण नीति योजना के अधीन राज्य सरकार वे भारत सरकार द्वारा माफ किए गए। मै उनसे यह जानना चाहता हूं कि इससंबंध में भारत सरकार से भी कोई मदद आई या नही?

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मै भी इसी से मिला जुला सैवाल करना चाहता हूं ताकि मंत्री जी दोनों का जवाब इकट्ठा ही दे दें। मेरा प्र न है कि 1987–88 में जब चौधरी देवी लाल जी मुख्य मी थे तो उस वक्त किसानों के कितने कर्जे माफ किए गए ओर उने बाद में केन्द्र सरकार की सहायता से कितने कर्ज माफ किए गए? केन्द्र सरकार ने कितनी सहायता दी है?

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, 128 करोड़ रूप्ए की रा ि ा हमने केन्द्र सरकार से इसके लिए मांगी थी। इसमें से आधा तो केन्द्र सराकर का था ओर बाकी आ आधा पैसा 10 प्रति ात ब्याज पर उसने हरियाणासरार को दिया था। हमने इसका विरोध किया तक यह 10 प्रति ात ब्याज ज्यादा है लेकिन केन्द्र रिलीफ आपने पास से लगाएगी। तब हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से 50 प्रति ात लोन 10 प्रति ात ब्याज पर लेकर किसानों का माफ किया। इस तरह से जो रा ि ा हमें मिलनी चाहिए थी,वह जैसे मैन बतायी 128 करोड़ रूप्ए थी लेकिन हमें लगभग 105 करोड़ रूपया मिला है ओर लगभग 23 करोड़ अभी

मिलना है लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार ने इतना लोन किसानो का माफ कर दिया है।

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में हय बताया कि 1036289 व्यक्तियों को लोन माफ किया गया है। क्या वे बताएंगे कि कुछ डिफाल्टर्ज भी कर्जा माफी की लिस्ट में भामिल थे, जिनका कर्जा माफ किय गया है? इसे अलावा जो आदमी वास्तव में लगातार अपनी किस्ते अदा कर रहे है, क्या ऐसे केंसिज में भी सरकार कर्जा माफ करने पर विचार करेगी? क्या ऐसे ऋणी लोगों के केसिज भी विचारधीन होगे?

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, कर्जा माफी नीति क `तहत यहहै कि कम से कम पिछले तीन सालों कसे पहले का डिफाल्टर होना चाहिए हालांकि इससे हमारे बैकिग सिस्टम पर आघात पहुंचा है। लोगों से पैस न देने की भावना भी जागृत हुई हैं और साथ मे रिकवरी पर भी इसका भरपूर असर पड़ा है।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि 1987 के चुनाव होने के बाद चौधरी देवी लाल जी के वक्त कितने लोगों को कर्जा माफ किया गया और केन्द्र सरकार का उसमें कितना योगदान रहा है?

श्री अध्यक्षः रावत साहब, इसका उत्तर आ गया है।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि 266.05 करोड़ प्ए की रा ि ज्ञ के कर्ज ऋण नीति योजना के अधीन राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा माफ एि गए हैं मै इनसे यह जानना चाहता हूं कि फिगर्ज 1990–91 की है या 1987 से लेकर 1990 तक की है। और कर्जा माफी वाली लिस्ट में कितन बैकवर्ड क्लासिज के अैर कितने हरिजन व दूसरे लोग भाामिल है?

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, वर्श 1987 से लेकर 1990 तक तीन स्कीमों के तहत यह पैसा माफ हुआ है। जो दुसरी सूचना इन्होने मांगी है, इसके लिए यदि माननीय सदस्य अलग से नोटिस देगे तेा हम बता देगे।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्र न यह है कि 1987–88 में जब चौधरी देवी लाल मुख्य मंत्री थे उस वक्त कितना कर्जा माफ हुआ ओर उसके बाद में केन्द्रीय सहायता से कितना कर्जा माफ हुआ? ये दोनों फिग्गर्ज अलग अलग बता दें।

श्री धीरपाल सिंह: स्पीकर साहब, 41 करोड़ 85 लाख 59 हजार का कर्जा माफ हुआ। चार लाख 66 हजार 617 रूपए का कर्जा 1986–87 की स्कीम के तहत हुआ। चौधरी देवी लाल जी की नीति में कामि ियल बैंक भी आते थे लकिन बैकों ने आज्ञा का पालन नही किया इसलिए और कर्जे माफ नही हो सकें?

श्री रघुवीर सिंहः स्पीकरसाहब, मै जानना चाहता हूं कि 266.05 करोड़ रूपए का जो कर्जा माफ हुआ। यह एक फेज में हुआ या दो फेजिज में हुआ?

श्री धीरपाल सिहः स्पीकर साहब, यह तीन फेजिज में हुआ। दो फेजिज इनके पास थे आरे एक फेज मेरे पास।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि जो लोग लगातार तीन साल से डिफाल्टर थेा उनके कर्जे माफ किए गए। मै जानना चाहता हूं कि अगर और डिफाल्टर हो जाएं तो उनका कर्जा भी माफ किया जाएगा?

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैने पहले ही बताया है कि केन्द्रीय सरकार की नीति के तहत ही हमने कर्जे माफ किए हैं

Provision of Adequate Supply of Drinking Water in Tohana and Bhuna

1246 Comrade Harpal Singh: Will the Minister of state for Public Health be pleased to state—

(a) Whether the Government is aware of the fact that there is in adequate supply of drinking water in Tohana and Bhuna tehsil of Tohana Constituency; and

(b) If so, the steps taken or proposed to be taken to ensure adequate supply of drinking water there?

जन–स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री भागी राम):

(क) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र टोहाना के कुछ गांवों और टोहना नगर के कुछ भागों में पीने के पानी की सप्लाई अपर्याप्त है।

(ख) जब वितरण योजनओं की बढ़ोतरी के लिए आव यक पग उठाए जा रहे है।

कामरोड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, क्य मंत्री जी बताएंगे कि इन्होने कौन कौन से और कितने कितने फुट के पग उठाए है? (हंसी)

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मै माननीय हाउस को बताना चाहता हूं कि वाटर सप्लाई के लिए हमारा महकमा तो एक एजेंसी के तौर पर काम करता है। यह डियूटी तो संबंधित म्यूनिसिपल कमेटी की होती हैं यह महकमें को पैसा देते है, जमीन देते है। उसके बाद एजेंसी के तौर पर हमारा महकमा उस पर काम करता है। फिर भी हमने 1987 में एक बूस्टिं स्टे ान की मंजूरी दी, उसे बाद हमने नगरपालिका को कहा कि आप हमं यह स्टे ान बनाने के लिए जमीन दे। बूस्टिम स्टे ान लगाने के लए टैडर खुलने को बाद बूस्टिग स्टे ान बनाने का काम बहुत जल्दी भाुरू कर दिया जाएगा। जब बूस्टिग स्टे ान बन जाएगा उस समय टोहाना में पीने के पानी की कोई दिक्कत नही रहेगी।

कामरेड हरपाल सिहः स्पीकर साहब, 1987 में पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट ने टोहाना में वाटर सप्लाई स्कीम भाुरू की थी।

हालांकि सदियों में पानी की कम जरूरत होती है। लकिन फिरभी उस टाईम पर औरतों ने मेरे दफ्तर के सामन, म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर के सामने अपने घड़े फोड़े क्योकि वहां पर पानी की बहुत कमी है। टोहाना कस्बे मे जो कोठियों के मालिक है, उन्होने अपनी कोठियों में मोटरें लगा रखी है और जिस समय वाटर सप्लाई भुरू होती है उस समय वह अपनी मोटरें चला लेते हैं जिसक कारण पानी का प्रै ान कम हेा जाता है और गरीब बस्तियों तक पीने का पानी नही पहुंच पाता है। मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार भूना कस्बे के गरीब लोगों के लिए भी पीने के पानी का प्रबन्ध करेगी?

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, जहां तक टोहाना कस्बे की बात है, जब वहा पर बूस्टिग स्टे ान बन कर तैयार हो जाएगा तो वहां पर पीने के पानी की कोई दिक्कत नही रहेगी। माननीय सदस्य की यह बात ठीक है कि वहां पर जो कोठियों के मालिक है उनहोने मोटरें लगा रखी है। हमारे महकमें ने उस नलोगों हो यह हिदायत दे रही है कि वे अपनी मोटरों का `न चलाए। इसे अलावा हमने आई0पी0एम0 साहब से यह भी कि जिस समय वाटरसप्लाई का टाईम हो उस समय भाहरों और कस्बों की घरेलू बिजली दो घण्टे के लिए बन्द कर दें ताकि लोग अपनी मोटर न चला सके।

कामरेड हरपाल सिहः स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी बताएंगे कि टोहाना में बूस्टिग स्टे ान बनाने के लिए कितना पैसा अलाट कया गया है ओर वह कब तक बन कर तैयार हो जाएगा?

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, उसके लिए 5 लाख रूपए अलाट किए गए है और उसको बनाने के लिए हमने टैडर काल कर रखे है। वह टैंडर 19 तारीख को खुलेगे, उसके बाद उस पर काम भाुरू हो जाएगा।

J.L.N. Canal

1257 Sh. Kailash Chand Sharma: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) The number of pump houses constructed an stated functioning separately on the J.N.L Canal, Circle No. II, Narnaul during the year 1990; and

(b) The number of pump houses out of those referred to in part (a above, that have been given electricity connection?

श्री गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिह):

(क) वर्श 1990 में निर्मित पम्प घरों की संख्या = भाून्य

वर्श 1990 में विद्युतीकरण के उपरान्त जिन पम्प घरों ने कार्य करना आरम्भ किया

= छः

(ख) छः

श्री कैला ा चन्द भार्माः अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जवाहर ाल नेहरू कैनान सर्कल नारनौल पर कुल कितने पम्प हाउसिग बनाए गए है, जितने बनाए गए है उनमें से कितने पम्प हाउसिज को बिजली का कनैक ान किया जा चुका है। और जो बाकी रहते है, क्या उनको प्रायरिटी दे कर बिजली का कनैक ान दिया जाएगा?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, जवाहर लाल नेहरू कैनाल का सर्कल एक रोहतक में पड़ता है और दूसरा नारनौल में है। इस कैनाल के सैकिण्ड सर्कल पर 68 पप्म हाउसिज बनने थे उनमें से 64 बन चुके है और 64 में से 40 पम्प हाउसिज को बिजली को कनैक ान दिया जा चुका है। जिन 24 पम्प हाउसित को बिजली का कनैक ान नही दिया जा सका, वह धन अभाव के कारण नही दिया जा सका। अब तक बिजली बोर्ड उन पम्प हाउसिज पर 13 करोड़ रूपए खर्च कर चुका हैं ज्यों ही नहरी महकमें के पास पैसा उपलब्ध हो जाएगा, वह पैसा तुरन्त बिजली बोर्ड के पास जमा कर देगा, उसक बाद उन ोश पम्प हाउसिज को बिजली का कनैक ान दे दिया जाएगा।

श्री कैला ा चन्द भार्माः स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जवार लाल नेहरू कैनाल के एरिया में कितनवाटर कोसिजल बनने थे, कितनी बन गए ओर

कितने बाकी रहते है और जो बाकी रहते है उनको कब तक बना दिया जाएगा?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, उक कैनाल के एरिया में 1465 किलोमीअर लम्बे वाटर कोसिज बनने थे जिसमें से 1440 किलोंमीटर लम्बे वाटर कोसिज बन चुके हैं ओर केवल 25 किलोमीटर लम्बे वाटर कोसिज बनने बाकी रहते हैं अर्थ वर्क का काम 1.85 परसेन्ट बाकया है, लाईनिग का 2.017 परसेन्ट बकाया है और दूसरे वर्कस का 10 परसेन्ट काम बकाया है। साथ ही साथ में यह भी बता दूं कि इस नहर पर 4 पम्प हाउसिग बनने बकाया है।

डा0 रघुबीर सिंहः स्पीकरसाहब, जवाहर लाल नेहरू कैनाल का पुअर लाईनिग की वजह से नहर के दोनो तरफ 5–5 और 10–10 एकड़ जमीन के अन्दर वाटर लौगिग और वाटर सीपेज की वजह से से जारों किसान बे जमीन हो गए हैं इसलिए मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पुअर लाईनिग की वज से अब तक कितन औसिसर्ज या एम्पलाई के खिलाफ एक ान लिया गया है? दूसरा मेरा सवाल य है कि क्या इस वाटर लौगिग और वाटरसीपेज की समस्या को खत्म करने के लिए कोठ डिच ड्रेन बनाने की सरकार की स्कीम है, अगर है तेा वह कब तक बन पूर पूरी हो जाएगी?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मेन सवल वैसे तो पम्प हाउसिज से संबंधित है लेकिन चूंकि इनका सवाल किसानों से सबंधित है, इसलिए मै इनको बताना चाहता हूं कि पिछले 5–7 महीने से जब से मरे पाय यह महकमा आया हे, मैने इसके काम ाके दखा अैर यही पया है कि जहां जहां पैरेलल नहर बनाने का काम हुआहै,वहां ऐक्सरीमेंट असफल रहा है। अगर नही की रेजिकग करके या री–माडलिग करके कैपेसिटी बढ़ाते है तो यह समस्या नही हा`सकती थी। उन पर तकरीबन 50 प्रति ात से अधिक ऐक्सीपेरिमेंट असफल रहा है जिसकी वहज से किसानो ंको वटर लोगिग ओरवटर सीपेज होने के कारण फसले बर्बाद हुई हैं जहां तक डिच ड्रै बनाने की बा है, उस बारें में मै इनकी जानकारी के लिए बातना चाहता हूं कि यह स्की जेरे गौर है और इसकों जल्दी ही बनाएंगे ताकि किसानों को कम से कम नुकसान हो।

श्री कैला ा चन्द भार्माः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री होदय से पूछना चाहता हूं कि जो जौरासी–हमीदपुर डैम है, क्या उसकी रेनी–सीजन के दौरान जवाहर लाल नेहरू कैनाल के जरिए भेर जाने की कोई चोजनासरकार के विचाराधीन है?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, अगर फालतु पानी होगा तो जरूर भरेगे अगर नही होता तो नही भरेगे।

Daily Allowance to the Participants of State and National Level Games

1290 Seth Lachhman Dass Bajaj: Will the Minister of state for Education be pleased to state whether there is any proposal under conideration of the Government to increase daily allowance of thos chidren who participate in games/Science exhibitions at the state nd National?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह): जहां तक वि़द्यालय का संबं है, ऐसा कोई प्रस्ताव नही हैं तथापि महाविद्यालयों तथ वि ववि़द्यालयों के विद्यार्थियों के लिए एक प्रस्ताव विभाग तथा कुरूक्षेत्र वि ववि़द्यालय, कुरूक्षेत्र के विचारधीन है।

सेठ लछमन दास बजाजः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात ईक है कि जिलास्तर पर खेलने वाले स्कूलों के खिलाड़ियों को 8 रूपए और राज्रू स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को 15 रूपए दैनिक खुराक भत्ता दिया जााता है?

श्री सुरेन्द्र सिंहः ठीक है।

श्री रतन लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने मेन सवाल के जवाब मं बताया है कि जो स्कूलों के प्रतिभावान खिलाड़ी है।, उनका दैनिक खुराक भत्ता बढ़ाएजाने की कोई योजना नही है, लेकिन कालेज और यूनिवसिटी के खिलाडियों को यह भत्ता बढ़ाए जाने की परपोजल विचारधीन है मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह परपोजल क्या है? साथ ही साथ मै मंत्री

महोदय यह बताने की कृपा भी करे कि जो छात्र खिलाड़ी प्रदे ाों ओर दूसरे दे ाों में हरियाणा का नाम रौ ान करते है, उनको सरकारी नौकरी में सुविधा देने की सरकार की कोई योजना है?

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब इन्होने अपने सवाल में कालेज ओर स्कूल दोनों का जिकर कर दिया है। मै इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सितम्बर, 1990 में स्कूल के खिलाड़ियों को जो दैनिक पहले दिया जाता था, उसमें सं ाोधन कर दिया गया था। जब से ये रेट बढ़े है, तब से ऐसे प्रतिभावना स्कूल के खिलाडियों को जा राज्य स्तर पर खेलते है, उनको 15 रूपए ओर जो राश्ट्रीय स्तर पर खेलते है उनको 30 रूपए प्रति दिन खुराक भत्ता दिया जाता है। महाविद्यालय ओर वि वविद्यालय के खिलाडियों वाला मामला अभी विचारधीन है। जहां तक इनके दूसरे सवाल का संबंध है जो प्रतिभावान खिलाडियों को नौकरियों में सुविधा देने के बारे में है, उसके लिएये अलग से नोटिस दे दे, जवाब दे दिया जाऐगा।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय ि ाक्षा मंत्री जी ने बताया है कि खिलाडियों के लिए 8 रूपए और 15 रूपए प्रतिदिन नार्म के मुताबिक दिए जाते है। भाई सुरेन्द्र सिंह जी ग्रीन बिग्रेड मे ंरहे हैं मै इन से यह जानना चाहूंगा कि ग्रीन ब्रिगेड के लोगों के कितने पैसे दिए जाते है। (हंसी)

श्री रघुबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेगे कि जो खिलाड़ी इन्टरने ाल लैवल पर पटिसिपेट करते है, कया उनको हरियाणा की बसों मै फ्री ट्रैवलिग करने की कोर्ठ स्कीम सरकार के विचारधीन है?

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मै माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे इसक लिए अलग से नोटिस दे।

सेठ लछमनदास बजाजः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आज के युग मे कोई खिलाड़ी 8 रूपए और 15 रूपए के खुराब भत्ते से खेल के मैदान पर अच्छा प्रद र्न करके आगे जा पाएगा।

चौधरी सतबीरसिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, खिलाडियों को नकद भता दिया जाता हैं मै माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अगर नकद भत्ते की जगह खिलाडियों के खाने–पीने का प्रबन्ध करदिया जाए तो क्या यह ज्यादा अच्छा नही होगा?

(इस प्र न का उत्तर नही दिया गया)

श्री रतन लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभ खिलाड़ियों को टी0ए0 दिए जाने की बात कही है। मै आपके माध्यम से इससे यह जानना चाहता हूं कि जो छात्राएं प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जाता है, क्या उसको सुरक्षा के लिएभी कोई पग सरकार उठाती है (विध्न)

Mr. Speaker: Kataria Ji, this is no a relevenat supplementary. You are always off the track. Please take Please taek your seat.

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, कटारियों साहब बेफिक्र रहे इन जसे लोगो से छात्राओं की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जाता है। (हंसी)

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, सवाल में तो दो बाते पूछी गई हैं एक यह कि विद्यार्थी गेम्ज पाटिसिपेट करते है ओर दूसीर यह कि साईस ऐग्जीबि ान्ज में पाटिसिपेट करते है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपर करेगे कि ऐग्जीबि ान वाली क्या योजना है?

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै माननीय साथी को बतानाचाहूंगा कि जो विद्यार्थी साईस ऐग्जीबि ान्ज में पाटिसिपेट करने जते है उनको 8 रूपए प्रतिदिन दिए जाते है।

कामरोड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, खेलों मे और विज्ञान की प्रद र्शनियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए जो सुविधा दी जा रही हे, वह तो ठीक है लेकिन क्या यह तथ्य है कि कई स्कूल ऐसे भ ीहै जिसमें खेलों के मैदान भी नही है आरलेबोरेट्रीज भी नही है परन्तु वहां पर ये विज्ञान की प्रद र्शनियां लगाते है?

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकरसाहब, मै अपने माननीय साथी से यह कहूंगाकि वे इसके लिएसैपरेट नोटिसदे, जवाब दे दिया जायेगा।

Seting up of Industrial units in the state

1233. Sh. Ram Singh Mann: Will the Chif Minister be pleased to state—

(a) The total number of small and Large Scale Industrial Units set up in the State during the period from June, 1987 to-date; and

(b) Wheter any of the industries referred to in part (a) above have been closed? If so, the number thereof together withthe reasons therefor?

मुख्य मंत्रीः (श्री हुकम सिंह):

(क) जून 1987 से जनवरी 1991 तक राज्य में 23712 लघु उद्योग तथा 99 बड़े तथा माध्यम उद्योग स्थापित हुए है।

(ख) हां, श्रीमान जी, 178 लघु औद्योगिक इकाईयो, एक बड़े तथा मध्यम स्तर की इकाई विभिन्न कारणों से बन्द हुई है। वह कारण इकाईवार भिन्न है।

स्पीकर साहब, इकाई बन्द होने के बहुत से कारण होते है। जब किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को कही और ज्यादा सहूलियत मिल, तब वह अपनी इंडस्ट्री बदल लेता है, या कब्जे माल की कमी की वजह से भी इंडस्ट्री बन्द हो जाती है या जो माल बनाया, वह

बिक न पाया, उसकी वजह से भी बन्द हो जाती है या पूंजी की कमी की वजह से भी बन्द हो जाती है। इस तरह से इंडस्ट्रीज बन्द होने के कारण है।

श्री रण सिंहः स्पीकर साहब, क्या आदरणीय मुख्य मंत्री जी के नेाटिस में यह बात है कि नयी औद्योगिक नीति की घोशणा के के तहत इंसैटिव्ज देने के बावजुद भी अन्य राज्यों की तुलना में हमारे प्रदे ज्ञ में लार्ज और मीडिय स्केल के यूनिट्स कम आये है। क्या यह बात उनके नोटिसम ं है कि उद्योगपति इसलिए यहा पर आने के लिए आकर्शित नही हो रहे है क्योकि सत्ताधारी पक्ष के लोगों द्वारा जबरन चन्दे वसूल किए जाते है?

श्री हुक्म सिहः स्पीकर साहब, जितने भी हरियाणा प्रांत में उद्योग आ रहे है मेरे ख्याल से किसी भी दूसरे प्रांत में उतने नही आये है। हमारे पास उद्योग लगाने वलोां को ढेरों ऐप्लीके ान्ज पड़ी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरे प्रदे ाों से लोग हरियाणा में आ रहे है। वे ऐसा समझते है। कि हरियाणा चूंकि पीसफूल है। इसलिए हम वहां पर जाकर उद्योग लगाये।

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री होदय यह जानते है कि फरीदाबार हमारा बहुत बड़ापहला प्राथमिक औ़द्योगिक नगर है उसके काफी अर्से के बाद यू0 पी का नोयडा औद्योगिक नगर बना है। आज नोयडा फरीदाबाद से इतना आगे निकल गया हैं कि फरीदाबाद की और नोयड़ा की कोई तुलना

नही की जास कसती। इसी प्रकारसे एक मिसाल मै आपको देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः आप एग्जैप्ल क्यो देते है, आप सप्लीमैट्री पुल करे।

श्री बनारसी दास गुप्ताः ठीक हैं मै एक बात पूछना चाहता हूं। इसी तरह से धारूहेड़ा के अन्द हमने इंडस्ट्रीयल एस्टेट बनाया। अब भिवानी धारूहेड़ा से कही आग निकल गया है मै मुख्य मंन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसकाक्या कारण है?

श्री हुक्म सिंहः स्पीकर साहब, मै पहले ही अर्ज कर चुका हू। कि उद्योग लगाने वालों की हमार पा ढेरों ऐप्लीके ान्ज पैडिग पड़ी हुई हैं धारूहेड़ा की भी है, बल्लभगढ़ की भी है और फरीदाबाद की ळाी हैं सार दे ज्ञ से लोगों हरियाणा में भागे आ रहे है। इस बारे में हम विचार कर रहे है ताकि उनको औ़द्योगिक प्लाट दिए जा सके।

श्री राम निवास बिलास भार्माः स्पीकर साहब, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने जवाब में लिख है कि 178 लघु औद्योगिक इकाईय, एक बड़ी ओर एक मीडियम स्तर की इकाई विभिन्न कारणों से बन्द हुई है। स्पीकर साहब, फरीदाबाद के पास नोयड़ा है, धारूहेड़ा के पास भिवानी ओर जगाधारी के नजदीक परमाणु है। क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे, कि ही हमारे उद्योग यहां से

उठाकर वहां पर तो नही चले गए है? यदिगये है तेा इसके लिए सरकार ने क्या उपाय किए है ताकि आगे से न जाए? सरकार ने इसके लिए क्या सोचा है, क्या उपाय किए है ताकि ये आगे से जाने रूक जाए।

श्री हुक्म सिंहः स्पीकर साहब, मै पहले ही बताचुका हूं कि 178 छोटे उद्योग एक बड़ा तथा तथा एक मध्यम स्तर का उद्योग विभिन्न कारणों से बन्द हो गया है। मैने आपको एक नही, काफी कारण गिनाए है जिनकी वजस से वे बन्द हो गए। ये सारे के सारे नोयड़ा या दूसरी जगहो ंपर नही चले गये। बहुत से उद्योगपतियों की हमारे हरियाणा में आने के लिए हमारे पास बहुत सी ऐप्लीके ान्ज पैडिग पड़ी है।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने रण सिंह मान के प्र न के उत्तर में बताया है कि हरियाण के न्दर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए बाहर से बहुत ऐप्लीके ांज आ रही हैं क्या मुख्य ंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि जो ऐप्लीके ाज आ रही है, उनकी नि चत संख्या कितनी है?

श्री अध्यक्षः औफ हैड यह बताना पौसीबल नही है।

श्री बनारसी दास गुप्ताः स्पीकर साहब, मैने पहले जो प्र न किया था, उसका उत्तर नही आया इसलिए मै दूसरा प्र न करना चाहता हूं।

श्री हुक्म सिंहः स्पीकर साहब, ये दुबारा पूछ लें। इनके कौन से प्र न का उत्र नही आया।

श्री बनारसी दास गुप्ताः स्पीकर साहब, मैने नोयडा और भिवानी के बारें में पूछा था कि वे आग्र क्यो बढ़ गए? दूसरा सवाल यह ळै कि सौभाग्य से उद्योग विभाग मुख्य मंत्री जी के पास है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि क्या कभी उनहोने हरियाणा के उद्यमियों की कोई बैठक बुलाकर, उनको वि वास में लेकर छोड़कर क्यों जा रहे है? स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि बहुत सी ऐप्लीके ांज आ रही है और इसका कारण यह है कि पंजाब में हालात खराब है। आसाम में भी हालत खराब है और वे लोग अपनी स्टेट में आकर यहां पर इंडस्ट्री लगाना चाहते है.....

श्री अध्यक्षः आप सवाल पूछिए भाशण न दे।

श्री बनारसी दास गुप्ताः क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि उन्होने कभी हरियाणा के उद्योगपतियों की बैठक बुलाकर उनकी कठिनाइयों के कारणों को जानने की कोि ा ा की जिसकी वजह से वे हरियाणा छोड़कर जा रहे है?

श्री हुक्म सिंहः स्पीकर साह, अनेक मीटिग्ज उनके साथ मैने की ओर उनकी समस्याओं को मैने सुना है। जो भी उन्होने कठिनाईयां रखी उनेा दूर करने की कोि ा ा की गई है।

चौधरी सतबीर सिंह कादियानः स्पीकर साहब, पानीपत में एन0 एफ0 एल0 ऐनसिलरी यूनिट श्री कमापति त्रिपाटी की बहु का लगया हुआ है लेकिन वह वहां से प्रवार कर गई। उने जिम्मे बीस लाख का कर्जा है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि ऐसी इंडस्ट्री लगाने वालों पर क्या कोई रोक लगाई जाएगी?

श्री हुक्म सिंहः स्पीकर साहब, इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट कर्जा नही देता। हम तो इंडस्ट्रीज की रजिस्ट्रे ान करते है ओर जब वह बन्द हा जाती है तो डीरजिस्ट्रे ान करते है। कर्जा तो इंडस्ट्रियलिस्ट्से बैक से लेत`है या कही और संस्था से लेते है।

श्री सीता राम सिगलाः अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि उनहोने उद्योगपतियों के साथ मीटिग्ज की। मुख्य मंत्री जी के पास उद्योग विभाग भी है ओ सी0आई0डी0 विभाग भी हैं क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि उनके पास कोई ि ाकायत आई कि फरीदाबाद और गुडगाव के उद्योगपतियों से उनकी जो टर्नआवेर थी, उस पर दो परसैन्ट इनकी पार्टी के लिएचूंकि चन्दा मांगा गया इसलिए वे वहां से जा रहे है?

डा0 रघुवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बतायाहै कि बाहर से काफी ऐप्लीके ांज इंडस्ट्री लगाने के लिए आई। क्या मुख्य मंत्री महोदय, बतान की कृपर करेगे कि हरियाणा

में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वह इंडस्ट्रियल पौलिसी के अनुरूप है? अगर उसमें कोई गैप है तो स्टेट गवर्नमेंअ ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इंडस्ट्रियल पौलिसी के अनुरूप लाने के लिए क्या स्टैप्स लिए है?

श्री हुक्म सिहः स्पीकर साहब, इसका जवाब में पहले दे चुका हूं।

श्री रण सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय जी को भाायद सवाल समझ नही आया, इसलिए मै दुबारा पूछ लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में काफी इंडस्ट्रियल यूनिट्स बन्द हुए हैं क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स बन्द हुए उनमें से कितने ऐसे है जो श्रमिक अ ाांति की वजह से बन्द हुए है ओर कितने ऐस यूनिट्स है जो एल0एम0एमस0 यानी लूटमान संगठन द्वारा जबरदस्ती चन्दा इक्ट्ठा करने की वजा से बन्द हुए?

श्री हुक्म सिंहः अध्यक्ष महोदय, रण सिंह ने कहाकि मुख्य मंत्री कीसमझ में सवाल नही आया। स्पीकर साहब, मेरी समझ में तो सब कुछ आता है। भाायद उनकी समझ में कुछ बात नही आती। स्पीकरसाह, मै उनको बताना चाहता हूं कि एक भी यूनिट लेबर आ ाांन्ति की वजह से बन्द नही हुई। एक बड़ी यूनिट जो गुडगांव में थी और जो जूस बनाती थी, उसकी बाजार में सेल नही हुई इसलिए वह बन्द हो गयी।

Ugradationof Ballabgarh Girls High School

1395 Sh. Yogesh Chand Sharma: Will the minister of state for eduction be pleased to stat whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Ballabgarh Girls High School to 10+2 system during the year 1991-92?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरे ा सिंह): जी नही।

श्री योगे ा चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, वर्श 1991–92 के अन्दर कन्या उच्च विद्यालय बल्लभगढत्र का दर्जा बढ़ाकर 10+2 प्रणली बनाने का सरकार को कोई प्रस्ताव नही है, यह इन्होने अपने जवाब में कहा है। मै इनके यह बतलाना चाहता हूं कि सत्ताधारी दल के सदस्यों के तकरीबन हरेक हल्के में स्कूलों को अपग्रेड कियागया है लेकिन हमारे हल्को मे कोई स्कूल अपग्रेड नही किए गये है? क्या सरकार इसका स्पश्टीकरण देगी कि हमारे हल्कों में स्कूल अपग्रेड न करने का क्या कारण है।

श्री सुरेन्द्र सिह: अध्यक्ष महोदय, नार्मज व डिमाड को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला कमेटी लेती है। इसके लिए जो कमेटी बनाई होती है, वह मैरिट को भी देखती है। जैसाकि इन्होने कहा कि सत्ताधारी दल के हल्कों में तो स्कूलों को अपग्रेउ किया जा रहा है लकिन हमारे हल्कों में स्कूल अपग्रेड नही किये जा रहे है, तेस ऐसी कोई बात नह है। अगर माननीय सदस्य नीचे से स्कूल अपग्रेडे ान के लिए रिकमन्ड करवा के भेजे और खुद भी उसके लिए एक लैटर सरकार को लिखे, तेा उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि हरियाणा के अन्द कुछ और विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने का संकल्प ि ाक्षा विभाग के पास विचारधीन है।

श्री सुरेन्द्र सिंह: जी हां।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, अभी मत्री जी ने बल्लभगढ़ कन्या उच्च विद्यालय के स्कूल 10+2 प्रणाली के अन्तग अपग्रेड करने के बारें में अपने जवाब में 'नही' कहाहै। मै यह जानना चाहता हूं कि क्या वह स्कूल सरकार द्वारा निर्धारित नार्मज को पूरा नही करता था, अगर नही तोवे कौन कौन से नार्मज थे? इसके इलावा हरियाणा के अन्दर और कौन कौन से स्कूल्ज है। जो अपग्रेडेश्ज्ञन के संबंध में सरकार के नार्मज पूरा नही करते?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब पौसिबल नही है।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मेरे योग्य मंत्री महोदय ने अभी अपने लिखित उत्तर में बताया है कि वर्श 1991–92 के दौरान कन्या उच्च विद्यालय बल्लभगढ का दर्जा बढ़ाकर 10+2 करने का सरकार का प्रस्ताव नही हैं क्या जिला फरीदाबाद या हथीन में भी 1991–92 में कोई स्कूल अपग्रेड नही किया जाऐगा?

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह): अध्यक्ष महोदय, यह किसी ने नही कहा कि 1991–92 में कोई स्कूल अपग्रेड नही होगा।

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस स्कूल को अपग्रेउ करने का कोई परपोजल है जो मंत्री जी ने कह दिया कि नही। मै बताना चाहता हूं कि जो भी स्कूल क्राइटेरिया को पूरा करता है। और अगर यह स्कूल भी पूरा करता है ते जब हम स्कूल अपग्रेड करेगे, तब विचार कर लिया जाएगा।

डा० रघुवीर सिंह: स्पीकरसाहब, एक सवाल के जवाब में कल स्कूलों की अपग्रेडे ान की लिस्ट दी गई थी। उससे यह पता चलता है कि सत्ताधारी लोग अपनी पावर का दुरूपयोग कर रहे है। (ाोर) उसमें बताया गया था कि गोहाना में 9 दडबां कला में 8 और दादरी में 7 स्कूल अपग्रेड हुए। ये अपनी पावरका मिसयूज कर रहे है। (ाोर)

श्री अध्यक्ष: यह कोई सप्लीमैंटरी नही है। अगला सवाल, श्री रावत।

Construction of Mandi at Hodal

1426. Sh. Bhagwan Sahai Rawat: will the Minister for agriculture be pleased to state—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Grain Market and Subji Mandi at Hodal; and

(b) If so, the time by which bteh afreasid proposal is likely to be materialised?

कृशि मंत्री (श्री कि ान सिंह सागवान):

(क) होडल में वर्तमान अनाज मंडी के विस्तार तथा नई सब्जी मंडी से संबंधित प्रस्तावों का हरियाणा राज्य कृशि विपणन मंडल द्वारा अनुमादेन किया जा चुका है।

(ख) दोनों प्रस्तावों पर कार्य प्रगति पर है। केवल उन क्षेत्र को छोड़ कर जिसका कब्जा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे किया हुआ हैं, विस्तार कार्य का विकास पूराहो चुका है। सब्जी मंउी परियोजना के कार्य को छः मास के अन्छर पूरा किये जाने की सम्भावना है।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कश्ट करेगे कि इस मंडी को बनाने का प्रस्ताव कब किया गया था? इसके अलावा जिस भूमि पर कब्जा हुआ है और हाई कोट की स्टे है, कया उस पर सत्ता पक्ष के लोगों ने दुकाने बना कर कब्जा नही किया हुआ है? (ाोर)

श्री कि ान सिंह सांगवानः स्पीकर साहब, इस मंड़ी को बनाने के लिए जमीनको एक्वीजी ान की कायर्रूवाही जनवरी, 1981 में हुई थी ओ एवार्ड 1984 में हुआ था। मेरे माननीय साथी ने जो ऐलीगे ान लगाया है, वह बिल्कुल निराधार है। उसमें अगर कोई इन्स्ट्रैस्ट होगा तो इन्ही का होगा, सत्ता पक्ष का नही है।

श्री उदय भानः स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र का माननीय उच्च न्यायालय

द्वारास्टे दिया हुआ हैं, उसकी कया स्थिति हैं और वह स्टै कब तक वैकेट कर दिया जाएगा? इसके अलावा मै यह भी जानना चाहता हूं कि वहां पर सब्जी मंडी कब तक बना दी जाएगी और अनाज मंडत्री को बनाने में कितना समय लगेगा? उसको बनाने के लिए कितना पैसा प्रस्तावित था और जितना पैसा प्रस्तावित था उसमें से कितना पैसा खर्च हो चुका हैं? (विध्न) वहां पर कब्जा रावत साहब ने किया होगा हमने नही किया। (ाोर) आप इस बारें में जांच करवा लें वहां पर हमारा कब्जा नही है, रावत साहब ने कब्जा कर रखा होगा। (ाोर)

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, वहा पर सत्ता पक्ष और प्राइवेट लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है ओर अपनी दुकानें बना रखी है। (ाोर)

श्री रघुवीर सिंहः स्पीकर साहब, अपनी पावर का मिसयूज तो सत्तापक्ष के लोग करते है। (ाोर)

Mr. Speake: I think, Mr. Rawat and you have made up your mind not to allow the business of the House to proceed smoothly. I won't tolerate it. Please take your seat. (Interuption)

श्री कि ान सिंह सांगवानः स्पीकर साहब, जहां तक सब्जी मंडी का सवाल है.....(ाोर)

श्री भगवान सहाय रावतः स्पीकर साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए। (ाोर)

Mr. Speaker: Mr. Rawat, this is not the way. Please take your seat.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकरसाहब, इनमें क्या गल्ती हो गई है? (ाोर)

श्री अध्यक्षः पता नही क्यों भाोर है? I permitted him to ask supplmentary as and when he wanted to do so but he is jumping on his seat. This is not the way. (Noise and Interruption)

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, गवर्नमैंट की तरफ से किसी भी सप्लीमैंटरी का जवाब ठीक नही दिया जाता। इनही तरफ से हरसप्लीमैटरी का इवेसिव जवाब दिया जाता है। जब तक आप इन्टरवान नही करतेगे, तब तक किसी भी सप्लीमैटरी का जवाब ठीक नही जाएगा। (ाोर)

Mr. Speaker: But that is not they way to ask a supplementry (Interruption)

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, जहां तक सब्जी मंडी का सवाल है उसका अब तक 70 फीसदी काम कम्पलीटा हो चुका है। और जो काम बाकी रहता है वह अगले 6 महीने में कम्पलीट हो जाएगा क्योंकि इसके क्षेत्र पर हाई कोर्ट का स्टे नही हैं जहां तक ग्रेन मार्किट का सवाल हैं इसके जिस क्षेत्र पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिया हुआ है, उसे लिए दो रिट पैटोशंज हुई थी। एक पैदो ान चूंकि खारिज हो चुकी हैं इसलिए उस क्षेत्र का

काम जल्दी ही टेकअप कर लिया जाएगा। दूसरी पैटी ान पर चूंकि स्टे आर्डर है इसलिए उसके क्षेत्र का अभी पोजै ान नही लिया जासकता।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, जिस जमीन पर यह अनाज मंडी प्रस्तावित थी, उस क्षेत्र पर माननीय उच्च न्यायाल ने स्टे दिया है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि उसी स्टे वाले क्षेत्र पर सत्ता पक्ष के और प्राईवेट आदमियों ने नाजायज कब्जा करके दुकाने बनाई हुई है? अगर बनाई हुई है तका क्या उसकी जांच की जाएगी?

श्री कि ान सिंह सांगवानः स्पीकरसाहब, उस क्षेत्र पर किसी को भी नाजायज कब्जा नही है। यदिकोई ऐसाी बात मननीय सदस्य के नोटिस मे है ये हमें बताएं हम जरूर कार्यवाही करेगे।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो माननीय मंत्री जी अपने लिखित जवाब में कह रहे है कि केवल उस क्षेत्र का छोड़कर, जिसका कब्जा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे किया हुआ है, विस्तार कार्य का विकास लगभग पूरा हो चुकाहै। वहां पर कब्जे की बात मंत्री जी ने लिखित रूप में मानी है और जबानी कह रहे है कि कोई कब्जा है लेकिन मंत्री जी ने इसका जवाबद दिय है कि वहां परकोइ कब्जा नही हैं फिर मंत्री जी ने कहाकि अगर माननीयसछस के नोटिस में ऐसी कोई बात है तो वह हमें बताए, हम कार्यवाही करेगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय

सदस्यों की ओर सै आपकी सेवा मेंस्पैसिफफिक सवाल दिए जो है। लेकिन सरकार की तरफ से उनकालिखित जवाब कुछ दिया जाता है और जवानी तौर पर कुछ और दिया जाता हैं हम आपके माध्यम से ही सरकार से स्पैसिफिक सवाल पूछे है ओर माननीय मंत्री जी बैठे बैठे कोमैट्स करते हैं यह ठीक है कि हम विपक्ष के सदस्य है, हम आवारा तो नही है। स्पीकर साहब आप हमरे संरक्षक है (ाोर)

श्री अध्यक्षः भार्मा जी, आज अजीब सी बात कर रहे है जिसकी कोई रैलेवैसी नही है। Please put a specific supplementary.

Sh. Ram Bilas Sharma: I am putting a supplementary and it is very much specific. माननीय मंत्री जी ने जबानी कहा है कि वहां पर कोई कब्जा नही है ओ यदि हमारे नोटिस में ऐसी बात है ता`इन्हें बताएं ये जरूर कार्यवाही करेगे। स्पीकरसाहब, लिखित जवाब में तो कब्जा माना गया है और जवानी कह रहे है। कि कोई कब्जा नही है। It is a contradiction इसे आप इनसे क्लीयर करवा दें। (ाोर)

श्री कि ान सिंह सांगवानः स्पीकर सर, ऐसा है कि अनाज मण्डी होडल के लिए टोटल जमीन 21 एकड 5 कनाल ओर 16 मरले ऐक्वायर की गई थी। जो रकबा हाई कोर्ट से स्टे हो चुका है ओर जिस पर किसी ओर का कब्जा है, वह 6 एकड 7 कनाल और 6 मरले है। बाकी की सारा एरिया कवर हो चुकाहै

ओर उस पर 70 परसैन्ट काम हो चुका हैं 6 एकड 7 कनाल और 6 मरले पर दूसरे लोगों का कब्जा है, उनकी दो पैटी ान हाईकोर्ट में थी। उनमें से एक तो खारिज हो चुकी है। और जा खारिज हो चुकी है , उस एरिया पर भी जल्दी ही काम भाुरू हो जाएगा।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, जिस लगभग 6 एकड़ जमीन पर मंत्री महोदय ने दूसरे लोगों का कब्जा बताया है, उस बारें में मै मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जमीन सारी इकटठी अधिगहरण की गई थी या पार्टस में अधिग्रहण की गई थी। दूसरे मै यह जाननाचाहता हूं कि जिस जमीन पर लोगों का कब्जा है, क्या उसमे कोई राजनीतिज्ञ वि ोश तो भाामिल नही है?

श्री कि ान सिंह सागवान: स्पीकरसाहब, इस जमीन को 1984 में इक्ट्ठा ही अधिग्रहण किया गया था परन्तु 1984–85 में हाई कोट में दो रिटे दायर हुई थी जिसकी वजह से 6 एकड़ 7 कनाल और 6 मरले जमीन ऐक्वायर नही हो सकी थी। बाकी सारी जमीन ऐक्वायर हो चुकी है। इतीन जमीन इसलिए ऐक्वायर की गइ थी कि वर्तमान अनाज मण्डी का विस्तार किया जासके और साथ में नई सब्जी मंडी बनाई जा सके।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिस 6 एकडय जमीन पर क्बजा

बताया जा रहा है, क्या वह कब्जा किन्ही लोगों का प्रारम्भ से ही है या बाद में किसी राजनीतिक दबाव की वजह से किसी ने कब्जा किया है अगर किन्ही लोगों ने जानबूझकर इस जमीन को एक्वायर करवाने में डिले करवाई है या इस पर कब्जा किया है, उसकी मौके परये खुद जा कर जांच करेगे।

श्री कि ानसिंह सागवानः स्पीकर साहब, 1984–85 में दो रिट पैटी ान्ज फाइल की गई। उनमें से एक रिट तो खारिज हो चुकी है औरउसके तहत जो एरिया आता है उस पर जल्दी ही ऐक्वीजिशन को प्रोसिडिग्ज भाुय कर रहे है। दूसरी रिटन का जब फैसला हो जाऐगा तो उस से सम्बन्धित एरिया का भी ऐक्वायर करके उस पर काम भाुरू कर देगे।

DIET Education

1417 Sh. Durgta Dutt Attri: Will the Minister of state for Education be pleased to state the distric wise number of training centres under the DIET Scheme functioning in the STate at present?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह): इस समय जिला सोनीपत तथा गुडगांवा मे दी जिला ि ाक्षा एवं प्रि ाक्षण संस्थान चल रहे है।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः अध्यक्ष महोदय, जब बहन सुशमा स्वराज जी ि ाक्षा मंत्री थी तो उनहोने डाईट स्कीम के तहत जिला जींद के इक्कस गांव मे एक ट्रेनिक सैन्टर खोलने का

आ वासन सदन में दिया थज्ञ। अब मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह ट्रेनिक सैन्टर इक्कस गांव में खोलने की योजना है अगर है, तेा कब तक खोल देगे।

श्री सुरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, 1988–89 में भारत सरकार की तरफ से डाइट स्कीम चलाने की योजना बनाई गई थी। इस स्कीम को भ्ाुय में जिला जींद, अम्बाला, महेन्द्रगढ़, भिवानी, सिरसा, ओर रोहतक में चालू करने का विचार हुआ था। स्पीकरसाहब, जहां तक इनके सवाल का सम्बन्ध है कि क्या जिला जींद के इक्कस गांव में डाईट स्कीम के तहत ट्रेनिग सैन्टर चालू किया जाऐगा, उस बारें में मै अपने साथी का बताना चाहूंगा कि वहां पर ट्रेनिग सैन्टर खोलने की बात विचारधीन है।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, डाईट योजना` तहत जहां जहां पर स्कूल खोले जाने थे, वहां के लिए रा ि ा भी ऐलोकेट कर दी गई थी। मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर इस साल काम भ्ाुरू कर देगे?

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैआपने साथी को बता देता हूं कि हमने वह रा ि ा पी0 डब्ल्यू0 डी0 को भेज दी है ओर जल्दी ही काम भ्ाुरू हो जाएगा।

चौधरी सतबरी सिंह कादियानः स्पीकर साहब, पानीपत में नोलथा गां में भी डाइट स्कीम के तहत एक ट्रेनिक सैन्टर खोलने के बारें में आ वासन दिया गया था। मै मंत्री महोदय से

जानना चाहता हूं कि क्या 1991–92 में वह सैन्टर वहां पर खोल दिया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, वहां पर भी एक ट्रेनिग सैन्टर आने वाले सालों में चालू करने की योजना हैं

श्री योगे ा चन्द भार्माः स्पीकर साहब, फरीदाबाद जिले के बंचारी गांव में भी डाईट स्कीम एक ट्रेनिक सैन्टर खोलने के बारें म ंउस समिय की ि ाक्ष मंत्री महोदय ने आ वासन दिया था। मै मंत्री महजोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर ट्रेनिग सैन्टर चालू करने की योजना है?

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर खे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

O.T. and J.B.T. Centres

1379 Sh. Udari Bhan: Will the Minister of state for Education be pleased to state—

(a)) Whether there is ny scheme under conideration of the Government to open O.T. and J.B.T. Centeres in District Faridabad under the DIET scheme; and

(b) If so, the tijme by which the siad scheme is likely to be materialised?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह):

(क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव भारत सकार को भेज दिया गया है तथा उनकी स्वीकृति अपेक्षित है।

New Buses Purchased

1238 Sh. Mohammand Aslam Khan: Will the Minister of state for Transport be pleased to state the total number of new buses purchased by the Haryana Roadways during the period from 1987 to 31 December, 1990 depot-wise, separately?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री वेद सिंह मलिक): अपेक्षित सूचना बनुबन्ध 'ए' में दी गई है, जोकि विधानसभा के पटल पर रखी जाती है।

अनुबन्ध 'ए'

क्रं सं.	डिपों का नाम	01.01.87 से 31.12. 902
1	**2**	**3**
1	अम्बाला	133
2	जींद	147
3	कैथल	107

4	सोनीपत	177
5	चण्डीगढ़	161
6	करनाल	172
7	यमुनानगर	132
8	कुरूक्षेत्र	35
9	गुडगांव	119
10	रिवाड़ी	165
11	भिवानी	163
12	फरीदाबाद	93
13	रोहतक	147
14	हिसार	179
15	सिरसार	114
16	दिल्ली	58
17	फतेहाबाद	66
	कुल बसें	2168

Bridge at Yamuna River

1384 Sh. Mahender Partap Singh: Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state—

(a) Whether there is any proposal under considerationof the Government to construct a bridge our Yamuna River as village Tigaon Majhawali (Faridabad); and

(b) If so, the time by which the aforesaid bridge is likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री जगन नाथ):

(क) जी हां, गांव मंझौली के निकट एक पुल बनाने का प्रस्ताव है। इस पुल का निर्माण उत्तर प्रदे ा सरकार द्वारा किया जाना हैं तथा केवल पहुंच माग का निर्माण हरियाणा सरकार द्वारा किया जाना है।

(ख) इस पुल के निर्माण का समय निर्धारित नही किया जा सकता, क्योकि इस पुल का निर्माण उत्तर प्रदे ा सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही किया जाना है। जिसके लिए उन्होने भूतल परिवहन मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी है।

Appointment of Punbabi Teachers

1408 Sardar Atma Singh Gill: Will the Minister of state for Education be pleased to state—

(a) Whether there is anyproposla under consideration of the Governemnt to appoint teachers to teach the Punjabi languagae in the Schools in the state; and

(b) If so, th etime by which the appointment of the teachers as referred to above are likely to be made?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह):

(क) जी हां।

(ख) नियुक्तियां भौक्षणिक सत्र 1991–92 में करने की संभावना है।

विभिन्न विशयों को उठाया जाना

श्री सुरज भानः स्पीकरसाहब, मेरे दो निवेदन है एक तो आदरणीय बहिन श्रीमती कमला वर्मा की इल लीगन डिटैन् ान के बारें में मैने परसों प्रिविलेज मो ान दिया था जिसके बारें में आपने कहा था कि 24 घण्ंट के अन्दर गवर्नमैट से जवाब मांगा है। 24 घंटे तो हो गए ह लेकिनक्या आप बताएंगे कि उसका क्या रहा? (विध्न)

Mr. Speaker: I had received the reply from the Government but that was not satisfactory. Therefore, I have referred the matter back to the Government to day an dhave asked for the reply within 24 hours.

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, मेरे कान में 21 सितम्बर 1990 की आग लगाए जाने की घटना के बारें में पिछले दिनों गृहमंत्री जी ने कहा था कि वे इसी सै ान में जवाब देगे। स्पीकर

साहब, मै आपके माध्यक से उनको केवल याद करवा रहा हूं कि कल सै ान का आखिरी दिन हैं

श्री अध्यक्षः वे जवाब अव य देंगे। आप कृपया बैठिए।

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पकर साहब, इसका जवाब में कल दूंगा।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, मैने आपकी सेवा में एक ध्यानकर्शण प्रस्ताव दिया हैं हरियाणा मे जिस तरह से हालात है और अब जत कि चुनावों की घोशणा भी हो गइ है पुलिस भर्तियों का सिलसिला अभी भी चल रहा है जो बन्द होना चहिए। हरियाणा के लोगों में यह आ ांका बनी हुई हैं कि ग्रीन ब्रिगेड के लोगों केा भर्ती किया जाएगा और ए0 के0 47 राइफलें और दूसरे हथियार उन को दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्षः भार्मा जी, आप कृपया बैठिए ओर मेरी बात सुनिए (विध्न एवं भाोर)

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, आज इनकी छवि सबको ंमालूम है ओर लोगों में एक भय बना हुआ ह। आज तो इनकी हथियारों के लिए सीधे अदजान खा ाोगी से बात चल रही हैं (विध्न)

श्री अध्यक्षः भार्मा जी, आप कृपया बैठिए ओर मेरी बात सुनिए। (विध्न)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब.....

श्री अध्यक्ष: भार्मा जी लगता है या तो मै हाई ऑफ हियरिग हूं या आप हार्ड औफ हियरिग हो गए हैं मेरे बार–बार कहने के बाजजूद भी आप मेरी बात नही सुन रहे है।

Sh. Ram Bilas Sharm: I am sorry, Sir.

श्री अध्यक्ष: आपकी कालिंग अटै ान मो ान आई है ओर वह अभी अण्डर कंसिड्रे ान है।

प्रो0 सम्पत सिंह: स्पीकर सर, यह सरकार बाकायदा डैमोक्रेसी में वि वास रखती है स्पीकर साहब, चुनावों की घोशणा तो जरूर हो गई है लेकिन इसकी तारीख के बारें में अभी नोटिफिके ान नही हुई हैं यह सरकार सिद्धांतों परचलने वाली सरकारहैं इनाहने आज का अखबार नही पढ़ा होगा? चुनावों की तारीख की नोटिफिके ान नह होने के बावजूद भी सरकार ने अनाउंस किया है कि चुनावों से पहले भर्ती नही होगी। यह बात रेडियों पर कही गई है और अखबार में भी आई है। कि भर्ती चुनावों के बाद होगी।

श्री कैला ा चन्द भार्मा: स्पीकर साहब, रिवाड़ी में 28 तारीख से सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है। उससे सम्बन्धित एक कालिग अटै ान मो ान मैने दिया था, उसका क्या बना?

श्री अध्यक्षः आपका कालिग अटै ान मो ान आया है जो कि अण्डर कंसिड्रे ान है।

श्री कैला ा चन्द भार्माः स्पीकर साहब, वह बहुत अर्जेन्ट मामला है।

श्री अध्यक्षः मुझे वह नोटिस आज ही मिला है। डिसाईड करने के लिए आप मुझे भी तो कुछ टाईम दीजिए। 28 तारीख से वहां हड़ताल चल रही हैं ओर आपको आज याद आया है। आप इसे दो–चार दिन पहले भी दे सकते थे। अब आप बैठिए।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः स्पीकरसाहब, देयोली गांव में बारें में मेरी एक कालिग अटै ान मो ान भी, उसका क्या बना?

श्री अध्यक्षः आपकी कालिग अटै ान मो ान आई है। औ वह अभी अण्डर कंसिड्र ान है।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः स्पीकर साहब 08.03.1991 को मैने आपकी सेवा में लिख कर दिया था कि एस0 पी0 जींद ने मुणे मारने की धमकी दी है। (विध्न) मुझे मारेन के लिए ाड़यंत्र रचे जा रहे है और बार–बार थ्रैट किया जा रहा है। आप चूंकि हमारे संरक्षक है ओर आप ही हमारी रखा कर सकते है, इसलिए उसका सखत नोटिस लिया जाए।

Mr. Speaker: Please take your seat and let me hear Mr. Verender Singh.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इस समय आदरणीय मुख्य मंत्री जी भी सदन में बैठे है। आपके और सदन के श्रबरू उन्होने कहा है कि उन्हें जान का खतरा है। इस सिलसिलें में इन्होने एक म्मिेदार अफसर का नाम लिया है आपको लिखकक कभी दिया हुआ हैं पिछले 6 दिनों से यही बात कर रहे है लेकिन कोई सुनता ही नही। (विध्न)

Mr. Speaker: No interruptions please.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मै आपसे गुजारिश करूंगा कि यह बड़ा सीरजिस मैटर है। एक आनरेबल मैम्बर यहां पर यह कह रहे हकि उनकी जान को खतरा है।

(इस समय कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हा गये।)

Mr. Speaker: Please take your seats. This is not the way.

श्री वीरेन्द्र सिहः अगर ये चाहे है कि सदन में विपक्ष न रहे तो मुख्य मंत्री जी हमें कह दें, हम बाहर चले जाते है अदरवईज विपक्ष का सुनना चाहिए। (व्यवधान व भाोर) एक माननीय सदस्य 6 दिनों से बार–बार यह मामला उठा रहे लेकिन कोई सुनता ही नही। आप आपनी सैटिसफै ान कीजिए ओर अपना निर्णय दीजिए (विध्न) आप सरकार से रिपोर्ट मांगिये। आखिरी इनको कुछ तो जवाब मिलना ही चाहिए।

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, मै सारी घटना को दोहराना नही चाहता लेकिन उन्होने जो यह कहा है कि उनकी जान खतरें में है, यह बड़ी ही सीरियस बात है। अगर कल को कोई मिस–हैपनिग हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा। इत्तफाक से यह वही अफसर है जिसके खिलाफ इस हाउस मे प्रिविलेज मो ान मूव हुआ था। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप इसको इम्मीजीयेटली कंसिडर करके आना फैसला दे।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, माननीय गृह मंत्री महोदय ने कहाहै कि उनकी पार्टी प्रजातात्रिक पार्टी है और प्रजातंत्रिक मूल्यों मे वे वि वास रखते हैं क्या उन प्रजातंत्रिक मूल्यों का यही नमूना है। कि प्रजा के प्रतिनिध को एस0 पी0 थ्रैट करे ओर उसे खिलाफ कार्यवाही न हो। क्या प्रजातन्त्र का यही तरीका है।

Mr. Speaker: Has anybody else to say anything more ताक मै एक दफा ही अपनी बात कहूं।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, आपने एक प्रिविलेज मो ान एडमिट किया था ओर उसकी रिपोर्ट पर काफी चर्चा यहां हुई जिसको मै दोहराना नही चाहता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस प्रिविलेज मो ान परविधिवत रिपोर्ट आने से पहले ही उस अधिकारी को उस एस0 पी0 का जिसके खिलाफ यह प्रिविलेज मो ान थी, प्रोमोट करके उसी जिले में लगा दिया गया।

श्री अध्यक्षः पंडित जी, यह सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकरसाहब, माननीय सदस्य ने आपकी सेवा में लिखकर दिया है कि 8 तारीख को उसी एस0 पी0 ने जाकर इनमें स्पैसिफिकली यह कहा है कि क्या मेरी पूंछ पड़वा ली, यह सदन तो मेरी जेब में रहता है और तूं अब संभल कर रहना।पंजाब से आंतकवादी आए है। तेरी जान को खतरा हो सकता है। माननीय सदस्य आपेस अपनी सुरक्षा के लिए मांग कर रहे है। ओर हमें भी इस मामले में बड़ी चिन्ता हैं अध्यक्ष महोदय, मंरी गुजारि ा है कि इनकी एप्लीके ान को प्रिविलेज मो ान में कन्वर्ट कर लिया जाऐ।

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, इनकी जो ऐप्लीके ान आयी थी, उसमे जो अकरैस इन्होने बतायी थी, वह 17.01.1991 को थी। अगरैंस के बादर यह ऐप्लीके ान आयी। जअ यह ऐप्लीके ान हयं पर आयी, क्या उसके बाद भी उसने थ्रैट किया है? इसके बारें में किसी भी सदस्य ने सदन में नही कहा। इन्सपाईट आफ आल दिस, मैने इनकी एप्लीके ान जैसे ही आयी, गवर्नमैंट के पास कमैट्स के लिए भेज दी। लेकिन जिस ऐप्लीके ान को ये रैफर कर रहे है, उस में जो इन्होने अकरैंस बतायी ळै, वह 17–19 को बतायी है जबकि यह मामला हाउस में इके बाद डिस्कस हो चुका है। यह बात तो इन्होने बतायी नही कि

17.01.1991 के बाद भी उनके साथ इस तरह से बिहेव किया गया हैं

श्री हीरा नन्द आर्यः क्या यहा जो 17.01.1991 को थ्रैट दी गयी, उसे लिए उसको छूट है?

श्री अध्यक्षः छूट की बात नही हैं आपने मेंरी बत सुनी नही कि उन्होने वह अकरैंसा 17.01.1991 की कही हैं

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, इनके पास अबा कोई इ ा नही रहा है। इसीलिए ये इस तरह का तमा ा हाउस में करना चाहतो है। (विध्न) अब इस तरह की बातें करके ये अपोजी ान की भूमिका निभा रहे है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मै यह जानना चाहता हूं कि जो 17.01.91 को उसकी धकमी दी थी क्या उसकी उसकी छूट है? (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः इसमें छूट की बा तनही है। आप मेरी बात सुने। मै यह कह रहा हूं कि 17.01.1991 को वह अकरैन्स हुआ थ। उसके बाद 04.03.91 को प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट डिस्कस ओ अडौप्त हुई। After the adoption of the report of Privileges committee he have applicaton on 08-03-1991. ऐप्लीके ान 04. 03.1991 के बाद आई और उसमें कहा गया है कि अकरैन्स 17.01. 1991 को हुई। मै यह नही कहता कि यह नही हुआ। मै

मैम्बरसाहेबार के साथ सहमति प्रकट करता हूं कि अगर ऐसी बात हुई है ाते बड़ी माड़ी बात है।

श्री वीरेन्द्र सिहः यह बात ठीक है कि 08.03.1991 को ऐप्लीके न आई ओर उसमें लिखा था कि 17.01.1991 को थ्रैट किया गया। लेकिन इसी दौरान जो प्रिविलेज मो ान उसके अगेन्सट थी, उसकी रिपोर्ट आ गई ओर उसक निपटारा हो गया। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः वह तो ठीक है लकिन 17.01.1991 को अकरैन्स के बाद ही किसी और अगरैन्स की कि उनकी कोई थ्रैड दी गई हैं इन्होने कोई रिपोर्ट नही की है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, आप देखिये कि 17. 01.1991 को प्रिविलज मो ान पैडिग होते हुए भी यह थ्रैट कर रहा है ओर अब उसे हौसले कितने बढ़ गये होगे जबकि वह प्रिविलेज मो ान उस एस0 पी0 की फेवर में डिस्पोज आफ हुई हैं आप इसका अन्दाजा लगा सकते है। आप तो एक लीडिंग लायर है। स्पीकर साहब, क्या यह एक कंटीन्युअस प्रोसैस नही हुआ? (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ऐसा है कि जब यहां पर प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट डिस्कस हो रही थी तो 17.01.1991 या उस बाद के मामले को कोई मैम्बर ो उठाता कि अत्री जी को यह थ्रैट दी गयी है। लेकिन किसी ने भी यह बात नही कही।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, 04.03.1991 को जब प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट पे ा हुई तो मैने इस बात का जिक्र किय था। (ाोर एवं व्यवधान)

Mr.Speaker: No, you did not raise this point. Nobody raised this point at that time, Even then I have referrd the matter to the Government.

Sh. Verender Singh: Mr. Speaker, I would like to make a humble submission in this regard.

Mr. Speaker: Chaudhari Sahib, you kinldycome to tmy Chamber along with Mr. Attri. We will discuss this matter there.

Sh. Durga Dutt Attri: Speaker Sir, I wantto sumit one thing.

Mr. Speaker: Attri ji, I have said that you kindly come alongwith Ch. Verender Singh, to my Chamber. We will sort out this matter there.

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, हम आपके धन्यवादी है मै यह मानता हूं कि हमारे पार्ट पर लैप्स हो गया। 04.03.1991 को अगर इस बारें में मैन् ान हो जाता है तो अच्छा होता। परन्तु अध्यक्ष महोदय, आप तेा इस मामले को सीरियस मान रहे है लेकिन गृह मंत्री कह रहे थे कि इनके पास कोई इ ू नही हैं इसलिए ये इस मामले को उठा रह है। (विध्न)

Mr. Speaker: Please take your seat. It is settled now.

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, सी0 आई0 डी0 के दो कर्मचारी लापता है उनके बारें में मेरा एक कालिंग अटैन् ान मो ान था। उनकी बीवियां उनको ढूंढती फिर रही है। क्या आप बताएंगे कि उसका क्या हुआ? (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, हाउस को आप ठीक ढंग से चलने दे, यह मेरी आप से विनती है।

श्री हीरा नन्द आर्यः ठीक ढंग सेकैय चल सकताहै जब ये चलने ही नही देना चाहते। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृपया आप सब बैठे। आर्य जी इस संबंध में आपने जो कालिग अटैन्शन मो ान दी थी, चह अन्डर कंसिड्रे ान है।

श्री हीरा नन्द आर्यः सै ान के दौरान क्या उसक जवाब आ जाएगा?

श्री अध्यक्षः देखेगे।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय मेरी भी इसी तरह का एक काल अटै ान मो ान था, उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्षः रावत जी, आपकानोटिस भी अन्डर कंसिड्रे ान है। (ाोर एवं व्यवधान)

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मै आपी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि असैम्बली के अन्दर सवालों के द्वारा या डिस्क ान के द्वारा कोई जानकारी अगर मिलती हैं तो वह फ्रूटफुल होसकती है ओर कई ऐसेासुझाव आसकते है जिससे ला एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक हो सकती है। स्पीकरसाहब, प्रिविलेज मो ान पर बोलते हुए मैने श्री डी0 डी0 अत्री का जिक्र किया था कि उनको थ्रैट दी गई है। स्पीकरसाहब, इस तरह का मौहाल यहांचला रहा है। (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Comrade Ji, this is not relevant. The matter i sover now, Sh. Attri and Ch. Veredner Singh are coming to my chamber an we will sort out the mater there. Now you please take your seat.

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव

विदे ाी प ाुधन फार्म, भिवानी में गायों के मरने सम्बन्धी

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received a notice of calling atention motion from Sh. Hira Nand Arya, MLA regarding deaths of cows in the Foreign Live-Stock Farm, Bhiwani, I admit it. अब श्री हीरा नन्द आर्य अपना मो ान पढ़ दें और उसे बाद कन्सर्न्ड मिनिस्टर यदि स्टेटमैंट देना चाहते तो दे दे।

श्री हीरा नन्द आर्यः मै इस समय सदन का ध्यान एक अत्याव यक लेाक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि

हाल ही की एक घटना में विदे ाी प ाु ाल, भिवानी में एक दर्जनसे अधि गऊए एक ही दिन में मर गई। इनमें से अधिकाश गाएं गर्भवती या दूध देने वाली थी। उक्त गऊओं के मरने से विभाग तथा लोगों में भारी बेचैनी व्याप्त हैं जाकि उग्र रूप धारण कर सकती हैं इसलिए मै निवेदन करता हूं किस सरकार सदन मे एक वक्तव्य देकर दोशी व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही से सदन को सूचित करें।

वक्तव्य

सहकारिता मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानकर्शण प्रस्ताव सम्बनधी

सहकारित मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): स्पीकर साहब, वर्श 1973 में हरियाणा दुग्ध विकास निगम के आप्रे ान फलड–1 के अन्तर्गत इंडियन डेरी कारपोरे ान की वित्तीय सहायता से एक आर्दया विदे ाी प ाुधन फार्म भिवानी में स्थापित किया। इसके एिल 55 एकड़ भूमि हरियाणा सरकार ने बिना किसी कीमत से दी। इस फार्म को उद्दे य उत्त जर्सी सांड उत्पन्न करता है, जिससे स्वदे ाी प ाुधन में सुधार हो सके। इस समय इस फार्म में 156 प ाु हैं जिसमें 70 गाएं, 39 बछडिया ओर 47 नर प ाु (सभी भाुद्ध जर्सी नस्त के) भाामिल हैं गऊओं को आयात किए गय भीत भाुश्क वीर्य से गर्भाधान किया जाता हैं जिससे अच्छी नस्ल पैदा हो सके।

इन सांडों को हरियाणा में तथा इसक बारह बेचा जाता हैं तथापित केवल नकारा गऊएं ही बेची जतीी है आर बाकी को नस्ल सुधार के उद्दे य से रख लिया जाताहैं इस समय प्रतिदन गऊओं के 650 लीटर दूध इस फार्म से प्राप्त हो रह हैं जाकि मार्किट में मिल्क प्लांट द्वाराबेचा जाता हैं फार्म कोचलाने के लिए 54 कर्मचारी कार्यरत है जिसमें एक फार्म मैनेज, एक कृत्रिम गर्भाधन अधिकारी (दोनो प्रि ाक्षित प ु चिकित्स), दो लाइव स्टाक असिटैट तथा एक सहायक चारा विकास अधिकारी भाामिल है।

28.02.1991 को तकरीबन 7.00बजे भााम को जब कृत्रिम गर्भाधन अधिकारी प ुओं के भौड में उनकी खुराक चैक करने हेतु अपने नियमित दौरे पर गया तो उसने देखा कि एक बछड़ी ऐंठने वाली हालत में हैं उसने लाइव स्टाक असिसटैंट जोकि उसे साथ था, को फार्म में स्थित डिस्पैसी से दवाईयां लाने कां कहा। इसी दौरान 23 और प ुओं ने भी एक दूसरे के बाद इसी प्रकार के लक्षण द र्ााने भारू कर दियं। उस समय सभी उपलब्ध 12 कर्मचारी प ु चिक्त्सिा पर लगा दिये गए। उप–निदरे ाक, प ु पालन विभाग, भिवानी से हभ तुरन्त दूरभाश द्वारा सम्पर्क किया गया जिसने अपने दो प ु चिकित्सक भेज जोकि वहां तकरीबन 8.00 बजे भााम को पहुंचे। लेकिन डेढ घंटे के अन्दर ही 10 बछड़िया, एक गाए तथा अन्य मादा बछड़ी दम तोड़ गइ। प ु चिक्त्सिक अपने सहायक कर्मचारियों के साथ समय पर प ु

चिकित्या एवं दवाईयों द्वारा 12 प ाुओं केा बचाने में समर्थ रहे। तथापि भरसक कोि ाि ों तथासभी तरह की प ाु चिक्कित्या सहायता के बावजूद बाकी के 12 प ाुओं को बचाया नही जा सकात। इन 12 मृत प ाुओं में से दो बछड़िया गर्भवती, दो फडर एवं नकारा थी तथ भोश बछड़िया गर्भवती नही थी इनमें एक 8 महीने की बछड़ी भी थी।

फार्म के सभी प ाु ओरियंटल बीमाकम्पनी तथाने ालन बीमा कम्पनी से बीमाकृत है। मृत प ाुओं का बीमा मूल्या 54960 रूपए है। बीमा कम्पनियों को इस घटना के बारे सूचित कर दिया गयाहैं ओर उन्होने फार्म पर आकर स्थिति का जायजा ले लिया हैं इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने के बाद तथ अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के उपरान्त भीघ्र ही बीमा कम्पनियों से क्लेम दायर करने जा रहे हे। 10 प ाुओं को पोस्ट–मार्टस इन्चार्ज, सिविल प ाु हस्पताल, भिवानी द्वारा किया गया तथा दो मृत प ाु हरियाण कृशि वि ववविद्यालय हिसार को उसी रात पोस्ट मार्टम के लिए भेजे गए। पानी, भूमि तथा चारे के नमून भी हरियाणा कृशि वि ववविद्यालय हिसार को वि लेशण के लिए भेज दिए गये है। इन सभी से अभी रिर्पार्ट आनी हैं

इस घटना को बड़ी गंभीरता से लिया गया हैं तथा दोशी कर्मचारियों के विरूद्ध पहले ही कार्यवाही कर ली गई हैं हमने जो डक्टर डयूटी परथा उसको भी निलम्बित कर दिया हैं हमने अन्य 6 कर्मचारियेां को भी, जो इस घटना के समय डयूटी

पर थे तथा जो प ाुओं की खुराक एवं सुरक्षा में ग्रस्त थे, निलम्बित कर दिया है। फार्म मैनेजर, भिवानी, यद्यपि इस घटना के दिन फार्म पर उपस्थित नही था, को उसकी फार्म प्रबन्धकीय ढील के कारा बदल दिया हैं

आगे की विभागीय कार्यवाही पोस्ट–मार्टम की रिपोर्ट तथा अन्य पानी, भूमि एवं चारे के नमूनों की रिपोर्ट मिलने पर की जायेगी ओर यदि द्वेशपूर्ण कार्य पाया गया तो दोशी के विरूद्ध फौजदारी मामला दर्ज करवाया जाऐगा। हमने इस घटना को बहुत ही गम्भीरता से लिया है और किसी को बख्भाा नही जाऐगा।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकरसाहब, मंत्री महोदय ने यह सारा विवरण देते हुए यह मान है कि एक दर्जन एांए मरी हैं मै कहना चाहता हूं कि जिस जानकारी है। क्या इस मामले को पुनः जांच करवाएंगे? दूसरे, मै यह जानना चाहता हूं, जेसे इन्होने कहा कि केवल नकारा गाएं बेची जाती है, क्या वे किसानों को बची जाती है या कसाईयों को?

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैने अपनी स्टेटमैंअ में यह कहा है कि मौके पर डाक्टर था। उनको जैसे लक्षण दिखाई दिए उसके मुताबिक को ि ा ा की। करीब दो घंटे के अन्दर 1100 रूपए की दवाई उपलबध करवाई गई थी। भिवानी में ट्रीटमैंट के लि जो दवाईयों चाहिए थी वह मौके पर मंगवाई गई। उन्होने प ाुओं को बचाने की को ि ा ा की ओर 12 प ाु बचाए भी हैं

जिम्मेदार अधिकारी जो वहां पर था, उसको फिर भी वहां से ट्रांसफर किया है। एक डाक्टर को आरै नीचे के कर्मचारियों को भी सस्पैड किया है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मै मत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये इस बात का ध्यान रखेगे कि इन् योरेस की रकम वसूल करने के लिए महकमें के अधिकारी उनको बचाने का प्रयत्न तो नही करेगे?

श्री धीरपाल सिंहः बिल्कुल नही करेगे।

राज्यपाल से सन्दे ा

Mr. Speaker: Hon'ble Member I have received a message from the Hon'ble Governor, which reads as under:—

"I write to acknowlege with thanks the receipts of your demi-officeial letter No. HVS-LA-28/94/4444 date March 5, 1991 for warding a copy of the Motionof Thanks passed by the Haryahna VidhanSabha on 5th March, 1991. I shall be grateffull it you could kindly conver my sincere thanks to the Hon'ble Members of the Haryana viahan Sabha."

समितियों की रिपोर्ट्स पे ा करना

(i) कमेटी औन पब्लिक अकांउट्स की 31 वी ओर 32वी रिपोर्ट्स

श्री अध्यक्ष: अब पब्लिक अंकाउंटस कमेटी के चेयरमैन, श्री उदय भान, कमेटी की ईयर 1990–91 के लिए 31वी ओर 32वी रिपोर्ट्स पे ा करेगे।

Sh. Udai Bhan (Chariman, Committee on Public Accounts): Sir, I beg to present the Thrity First and Thirty Second Reports of the Committee on Public Accounts for the year 1990-91, on—

(a) The Appropration Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the year 1985-86; and

(b) The Report of thecomptroller and Auditor General of India for the year 1985-86 (Civil and Revenuse Receipts). Respectively.

(ii) कमेटी औन सबोडिनेट लैजिस्ले ान की 22वी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब कमेटी और सबौडिनेट लैजिस्ले ान के चैयरमैन (अब डिप्टी स्पीकर) श्री वासु देव भार्मा, कमेटी की ईयर 1990–90 कि लिए 22वी रिपोर्ट पे ा करेगे।

Pandit Vasu Dev Sharma (Chairman, Committe on Subordingat Legistation): Sir, I beg to present the Twenty Second Report of the Committee on Subordiante Legislationfor the year 1990-91

गैर–सरकारी संकल्प (पुनराम्भ)

प्रेशित माल पर कर सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज अब कन्साईनमैंट टैक्स के बारें में श्री रणजीत सिंह एम0 एल0 ए0 (अब एक्स एम0एल0ए0) के रैजोल्यू ान पर जो 24.04.1988 को मूव किया गया था तथा जिस पर 07.04.1988 ओर 02.02.03.1988 को चर्चा की गई थी, डिस्क ान रिज्यूम हेागी। 02.03.1988 केा जब हाउस ऐडजर्न हुआ थ उस समय श्री रतन लाला कटारिया इस रैजोल्यू ान पर बोल रहे थे, वे कृपया अपनी स्पीच कंटीन्यू करे।

श्री सूरज भानः स्पीकर साहब, मेरी व्यवस्था का प्र न है। जब श्री रणजीत सिंह अब इस हाउस के मैम्बर नही हैं तो क्या उनके रैजोन्यू ान पर डिस्क ान हो सकती है क्योकि डिस्क ान कंक्लूड होने पर इसकी जवाब कौन देगा?

वित्त मंत्री (श्री तैयब हुसैन) मोहतरिम स्पीकर साहब, अभी लीडर ऑफ दि अपोजी ान ने कहा कि जब इस रैजोल्यू ान का मूवर इस हाउस का मैम्बरनही तो क्या इस वर डिस्क ान हो सकता है? चोधरी सूरज भान इतने तजुर्बेकार होते हुए भी ऐसी बात करें तो भाोभा नही देता। यह रैजोल्यू ान हाउस में मूव हो चुका है। Now it is the proptery of the House and desicsion can be taken by the House only.

श्री रतन लाल कटारियां (रादौर, अनुसूचित जति): स्पीकर साहब संवधिान की 46 वी अमैडमैंट जो हो चुकी है उसके तहत प्रदे ज्ञ से बाहर जाने वालों वस्तुओं पर राज्य सरकारों को कंसाइनमैंट टैक्स मिलना है। अगर केन्द्रीयसरकार द्वारा इस संबंध

में बिल पास कर दिया जाता है तो हरियाणा सरकार को उससे सालाना 50 करोड़ रूपए की आमदनी होनी थीं स्पीकर साहब, आज से लगभग डेढ साल पहले केन्द्र में दमनकारी कांग्रेस सरकार को हटाया गयाथा ओर इस दे ा की राजनीति में ऐ बहुत बड़ा बदलाव आया था। स्पीकर साहब, जो सरकारिकयो ंकमि ान की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाना था, जिसके अनुसार प्रदे ाों को कुछ अधिक अधिकार मिलने थे। जो फैडरल स्ट्रैक्चर ऑफ गवर्नमैंट हमने अपनाा है उसके मुताबिक केन्द्रीय सरकार का मजबूत होना बहुत जरूरी हैं उसके साथ साथ राज्य सरकारां को मजबूत होना भी जरूरी हैं सरकारिया कमि ान का गठन करके दे ाओर प्रदे ज्ञ की सरकारो ंको मजबूत करने की कोि ा ा की गई थी। आज आसाम के हालत, पंजाब के हालात अच्छे नही है ओर इसी तरह से जम्मू क मीर के हालात भी अच्छे नही है, इनके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है। केन्द्र की कांग्रेस सरकार में एक नौजवान था ओर उसके जितने भी साथी थे, वह सभी साधन सम्पन्न थे जिसके कारण प्रदे ाों की सरकारें बहुत कम तरक्की कर सकी। उस कांग्रेस सरकार की ऐसी भवाना रही कि स्टेट्स के जो इकोनिामिकल राइट्स थे, वे सारे अपने हाथ में ले लिया जिससे प्रदे ाों की तरक्की के रास्ते बन्द हो गए। स्पीकर साहब, यह रैजेल्यूयू ान पिछले साल भी इसी हाउस में डिस्कस हुआ था। उस समय भी सभी साथियों ने यह चाहा था कि इस रैजोल्यू ान के बारें में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई न कोई फैसला जरूर हो जाना चाहिए। लेकिन स्पीकर साहब बड़े

दु:ख के साथ कहना पडता हैं कि जहां दे ज्ञ में भ्रांति, अमर ओर आर्थिक हालात अच्छे होने चाहिए थे, केन्द्र में श्री वी0पी0 सिंह की सरकार ने बजाय लोगों को राहत देने के ऐसा मुद्दा हाथ में लिया जिसके कारण सारा दे ा हिल गया (ाोर)

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न है। कि केन्द्र में श्री वी0पी0 सिंह की सरकार कैये चली, कैये नही चली क्या इस बात का कंसाइनमैंट टैक्स से कोई संबंध है? इस बारें में मै आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः कटारिया साहब आज आप सुबह से ही लाईन से उखड़े हुए है। (हंसी)

श्री रतन लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मै लाइन पर ही आ रहा हूं।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब कल इन्होने पगड़ी बन्नी होई सी। आज जटा पगड़ी बन के नही आया। (हंसी)

श्री रतन लाल कटारियाः स्पीकर साहब, हमारे दल ने वी0पी0 सिंह की सरकार को पूरा समर्थन दिया था। इस दे ा के अन्दर मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लेकर बहुत होआ मचा। अगर यह रिपोर्ट जल्दबाजी में लागू नही की जात तो देश्ज्ञ के अन्दर ऐसेा हालात न होते। हमारी पार्टी भी वी0 पी0 सिंह के साथ थी और उस रिपोर्ट के हक में थी। हमने अपने मैनफैस्टों में भी प्रावधान किया था ओर उस में तीन क्लाजिज रखी थी। (विध्न)

अध्यक्ष महोदय, जिससमय ताऊ जी दे ा के उप प्रधान मंत्री बने तो हरियाणा के लागों को बड़ी आ ाएं थी कि जब केन्द्र मं अपनी सकरार बनी है तेा अब हरियाण के लोगों के भाग खुल जाएंगे। पहले गांवों में यह बात होती थी कि प्रदे ा का एक विधायक या मंत्री तब तक कुछ नही कर सकता जब तक उसका सेन्टर मे प्रभाव नह हो। उस समय ताऊ जी ने कहा था कि केन्दमे ंहमने जाना है ओरवहां पहुंच कर नोट छापने वली म ीन का मुंह हरियाणा की रतफ खोल दूंगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगो ंने सेन्टर में अपनी पावर होते हुए हरियाणा के लोगों के लिए कुन्द नही किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस बलबूतें पर हरियाणा के 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने इनको केन्द्र में सता सौपी थी, उस समय यहां के लोगों न यही सोचा था कि अब हरियाणा के लोगो ंको भलाई के लिए यहर सकरारकाम करेगी। ताऊ चौधरी दवी लाल जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकार को चलाने की कोि ा ा करेगे। लकिन ठीक तरीके से सरकार न चला करके आपस मे लड़ते रहे। इनकी लड़ाई से दे ा का दूसरा ही स्वरूप होता चला गया। इनकी आपसी लडझई की जवह से भार की प्रतिश्ठा को आचं आई। कहां तो भारत वर्श की अध्यक्षता में पहले 144 दे ाों का नान एलाइनमंट मीट हुआ। उपाध्यक्ष महोदय मै आपके माध्यम से हाउस के अन्दर यह बात कहनाचाहता हूं कि चुनाव के दौरान जितनी उम्मीद लोगो ने हमसे की थी, वह हम पूरी नही करपाय। अब जब मै गावों म ंजाता हूं तो गांवों के मुअजिज आदमी कहते है कि

कटारिया जी हमने तो आपसे बहुत सी उम्मदी की थी। हम यह सोचते थे कि अब हमारे हल्के में नई सड़के बनेगी, नए सकूल खोले जाएंगे, पुराने स्कूल अपग्रेड होगे ओर जे0बी0टी0 या दूसरे सेन्टर खोलेगे। लेकिन ये काम तो होने दूर रहे आप कोई भी का मनही करा पये। आप किसी मिडल स्कूल में जिसमें 20 टीचर होने चाहिए, वह भी पूरे नही करवा पाये क्योंकि हमारे हल्के मे जो मिडल स्कूल में पूरे मास्टर को प्रबंध नही करसके तो ओर हम आपसे क्या उम्मीद रख सकते हे? उपाध्यक्ष महोदय, काम तो मंत्रीमण्डल ने करना होताहैं सारी पावर मन्त्रियों के पास ही हेाती हैं या सरकार के पास होती हैं मै तो विपक्ष का एम0एल0ए0 हूं अपने हल्के की समस्याओं के बारे में कलम के माध्यम से लिख कर ओर इस महान सदन मे अपनी आवाज उठा कर सरकार का ध्यान दिलासकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को काम करने की फुर्सत ही कहा है, यह तो हर दिन तोड़ फोड के कार्यो में लगी रहती है। हर चौथे दिन मंत्रीमण्डल भापथ ग्रहण समारोहता हाता रहात है इस सरकार ने तो मंत्री मण्डल के गठन ओर भापथ ग्रहण समारोहों में ही 4 कीमती वर्श बर्बाद कर दिए हैं इन 4 वर्शो के दौरान प्रदे ा में विकास नाम की कोई चीज दिखाई नही दी। जनता तड़पती रही किप्रदे ज्ञ का विकास होगा, रो ानी आएगी और लोगों को कुछ राहत मिलेगी लेकिन ऐसा कुछ नही हुआ। (विध्न) चौधरी तैयब हुसैन जी तो कांग्रेस सकरार मे भी रहे है। इस सरकार का तो 2–4 दिन में बखेड़ा उल्टने वाला हैं अगरयह सरकार दो तीन महीन काट भी लेती है तो कोई बात नही। मै

आपकों वि वास दिलाता हूं कि केन्द्र में अगर माननीय अटल बिहारी बाजपेयी आदरणीय लाल कृश्ण अडवानी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गइ तो इस कन्साईनमैंअ बिल को ''विद इन नो टाईम'' पास कर देगी। उससे इस प्रदे ज्ञ की प्रगति होगी, गांवों का विकास होगा, सिर्फ लाल किले परभारीय जनता पार्टी का केसरिया झण्डा फहराने की देर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से दे ा की सभी समस्ओं कासमाधान हेागा। (विध्न)

डा0 रघुवीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, लाल किले पर तो केवल राश्ट्रीय झण्डा ''तिरंगा'' ही फहरा सकता है ओर कोई झण्डा नही।

श्री रतन लाल कटारियाः उपाध्यक्ष महोदय केसरिया रग का झण्डा तो बहुत पुराने समय से भारत में चला आ रहा है। केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अपने से यह दे ा प्रगति करेगा। केसरिया झण्डा सारे दे ज्ञ में लहरायेगा। राश्ट्रीय झण्डे के लिए जो कमेटी बनी थी उसने ीाी अपनी रिपोर्ट में केसरिया रंग रखा था यह भारत की पुरानी संस्कृति से जुअउ हुअ हैं महाभारत के युद्ध में जब श्री कृश्ण रथ पर एग थे तो उनके रथ पर भी भगवा झण्डा लगा थज्ञ। राम चन्द्र जी ने जब श्री लंका पर चढ़ाई की ाी तो भगवां रंग झण्डा लेकर ही चढाई की थी। (विध्न) उपाध्यक्ष महोदय, इन भाब्दों के साथ मै इस

रैजोल्यू ान कासमर्थन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं तथा अपना स्थान ग्रहण करता हूं

श्री सीता राम सिगला (गुडगावां): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोसत चौधरी रणजीत सिंह जी ने यह गैर सरकारी प्रस्ताव रखा था जिसका समर्थन करने के लिए मै खड़ा हुआ हूं। 1982 में कान्सटीचू ान में एक सं ाोधन किया गया था जिसक तहत एक राज्य में दूसरे राजय के अन्दर अगर कोई कारखानेदार सामान ले जाएगा तो जिस राज्य में उसका कारखाना हो उस राज्य को टैकस लगाने की पावर दी गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, उसे बाद प्रधान मंत्री जी ने कई बैठके बुलवाई है। मुख्य मंत्रियों की बैठक में इस बारें में चर्चा हुई लेकिन इस बलि को अमल मं लाने के लिए कुछ नही किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा एक छोटी सी स्टेट हैं अगर यह टैक्स लग जाए तो राजय मेां क 50 करोड स`अधिक का रैवेन्यू प्राप्त होगा जिससे इसस्टेट में विकास के ओर अधिक काम हो सकेगे। इसलिए यह टैक्स लगाना बहुत आव यक था लेकिन अभी तक इ बारें में फैसला नही हा सका हैं 1988 में यह यह प्रस्ताव विधान सभा में रख गया था और उस समय से ले कर सत्ता पक्ष के जितने भी सदस्य है, वे लगभग सभी इस प्रस्ताव पर बोल चुके है। इस बारें में केन्द्र से भी कई बार बात हुइ लेकिन इस पर कोई कार्यवाही अभी नही हुई। (विध्न) लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से एक ओर बात कहना चाहता हूं पिछले 15 महीने से हमारे यहां के नता भूतपूर्व

मुख्य चौधरी देवी ला जी केन्द्र में एक बडत्रे ही महत्वपूर्ण पद पर आसीन थे। उनके दिल में इस बात का बड़ा ही दद्र रहता था कि हरयाण के लिए कुछ किया जाए। हरियाणा वैसे भी उनकी होम स्टेट हैं इस स्टेट के अन्दर विकास के काम अधिक से अधिक हो, इसके लिए उनकी रूलि रहना स्वाभाविक ही है। हमें इस बात का बड़ा ही आ चर्य है कि जब से यह केन्द्र सरकार के अन्दर इतने बड़े महत्वपूर्ण पद पर बैठे है, एक दफा भी उन्होने इस मसले को नही उठाया वे तो अपने भाशण के अन्दर अकसर यह कहा करते थे कि जब कभी केन्द्र सरकार हमारे हाथ में आयी या हमार उसमे ंहिस्स होगा तो हम यह चाहेगे कि सेल्ज टैक्स डिपार्टमैंट के अन्दर भ्रश्टाचार का कारण ही दूर करेगे। उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर जिन आईटम्ज के ऊपर टैक्स कम है, उन पर हरियाणा में ज्यादा है, उन चीजों के ऊपर टैक्य कम क्यो नही होता? इसका एक मात्र कारण है। कि बड़े बडऋे व्यापारी और बड़े बड़े औद्योगिक घराने दोनों मिलकर भ्रश्टाचार करते है। आपकों पता ही हैं कि बड़े व्यापरियों को एक यामैक्सिम दा `परसैट माजिन हाता हैं उससे उनको कम बचत होताी ह जबक इस तरह से उनसेा सीध ही 8.10 परसैट बच जाता हैं जब एक कनस्टर घी के अन्दर 30 रूपये का फर्क होगा तो आप ही सोचिए बाकी की चीजों में क्या इसी तरह से नही होगा? आज के जमाने में कोई किसान, व्यापारी या सरकारी कर्मचारी लड़की की भाादी करताहै तो भाादी में कम से कम 8–10 कनस्तर घी के लग जाना स्वाभाविक बात हैं जब एक भाादी के अन्दर 8–10 कनस्तर घी के

लगते हो ता उसका यह सोचना पड़ता है कि अगर सौ रूपए मैटाडोर पर खर्च करके गुडगावा की बजाये दिल्ली से घी लो आऊ तो उसके 100–125रूपए की बचत हो जाती हैं इसलिए यह को ा ा करता है कि वह भी दिल्ली से ही घी ला आये। मेरा कहने काम मतलब यह है कि भ्रश्टाचार के फैलने का सबसे बड़ा कारण टैकस की चोरी है। में इस बारें में एक और उदाहरण देकर स्पश्ट करना चाहता हूं कि माचिस एक बहुत ही छोटी सी चीज है। 15–20–25 पैसे ही चीत है। मजदूर, किसान, और लगभग हरेक वकित इकसा इस्तेमाल करताहैं बीड़ी सुलगाने के लिए यह इस्तेमाल हाती है। बडत्रे बड़े लोगों के घरो ं तो इलैकिट्रक स्टाट्रर हाते है और लाईटर्ज होते हे लेकिन आम आदमी इसका इस्तेमाल करता हैं आम लोगों केा इसका प्रयोग बीड़ी सिगरेट सिगारआदि सुलगाने के लिए करना पड़ता हैं एक गरीब मजदूर का या एक किसान का माचिस के बिना गुजारा ही नही हैं दिल्ली के अन्दर माचिस के ऊपर कोई टैक्स नही है लेकिन हरियाणा में 8–10 परसैट टैक्स है। इतना बड़ा डिफरेस हैं इसका नतीजा क्या होगा कि वह चोरी से लयेगे। जब बौर्डर पर साठ–गांठ होती है, ट्रक के ट्रक सीधे निकलते हे। लेकिन अगर कोई दो किलो गुड या दो किलो चीनी ले आए तो उस पकड लते है ओर उस पर पांच सौ रूपया जुर्माना लगा देते हैं उपाध्यक्ष महोदय, एक दिन मै बार्डर परखड़ा था, एक कारखानेदार की गाड़ी आई। उसके पास बाकायदा वाऊचर पर टाईम न डलने के कारण उस पर दो हजार रूप्या जुर्माना करने की बात हो रही थी

वह कारखानेदार काफी गिडगिड़ा रहा था कि मेरेा पास कोई बौगस माल नही है। बाकायदा मेरे पा कै ामीमो है। किसी कारण से टाईम नही लिखा गया। यह मामला बहुत देर तक चला। मै तो वहां से चला गया लेकिन मै समझता हू कि उस अधिकारी के सथ कुन न कुछ सांठ–गांठ हो गई होगी ओर पांच सौ रूपए में फैसला हो गया होगा। उपाध्यक्षम होदय, इस तरह का भ्रश्टाचार यहां पर फला हुआ है ंउपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का भ्रश्टाचार यहा ंपर फला हुआ हैं उपाध्यक्ष महोदय, हर बार्डर पर डिपार्टमैंट ने टारगेट फिक्स किया हुआ है कि इतना रूपया उगाहर देना हेागा वरना तुम्हारा इंक्रीमैट बन्द कर दिया जाएगा। उस अधिकारी का टारगै पूरा करने के लिए गरीब लोगों से, आने जाने वलो ंसे, रहागीरों , एकि लो या दो किलो समान लाने वाले जुर्माने के रूप में पैसा इकट्ठा करना पड़ता है उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके सामन कहने जा रहा हूं कि इस पंचास कराड़ का क्या करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि नोयड़ा के अन्दर जितने भी कारखाने है, उनका किसी का भी हैड ऑफिस दिल्ली में नही है लेकिन हरियाणा में जितने भी कारखाने है, उन सब के हैड ऑफिस दिल्ली में है ओर इसका कारण यह है कि हरियाणा और दिल्ली के टैक्स के रेट में बहुत अन्तर है। यहां पर उद्योगपतियों को बहुत अधिक परे ान किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां की सी0 आई0 डी0 बड़ी योग्य है और होम मिनिस्टर बैठे है। वे भी बड़े योग्य है, बड़े काबिल है, इनके पास भी यह महकमा रहा था इनको होगा कि जब टैक्स की असैसमैंट होती है तो काइ ई0टी0ओ0 ऐसा नही

होगा जो असैसमैंट के समय पैसा न लेता हो। पैसा लेकर फिर असैसमैंट होती हैं जब टैक्स की असैसमैट होती है तो व्यापारी से पैसा ले लिया जात है। उसका खाता देख लिया जाता है ओर खाता देखकर उसको निपटा दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी एक औडिट ब्रान्च है। दो महीने के बाद उस व्यापारी की औडिट ब्रांच का एक नोटिस जाता है कि फला फाइल के खाते में कुद गड़बड़ है। इसलिए आप फाइल का खाता दुबारा दिखाइए। वह व्यापारी औडिट ब्रांच के सामन जाता हैं औडिट ब्रांच द्वारा जब दुबारा खाता देखा जाता है, अगर उसमं कुछ गड़बड़ निकलती है तेा व्यापारी के खाते की जांच की थी। उसको छोड़ना नही चाहिए। उस अधिकारी से पूछा जानाचाहिए कि उसने कितना पैसा लेकर व्यापारी को छोड़ा है? उस अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, पचास करोड़ की आमदनी का जो यह मामला है, इससे हरयिाणा के अन्दर बहुत भ्रश्टचार फैला हुआ हैं यहां पर उद्योगपतियों को बहुत अधिक परे ाान किया जात हैं उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक जन सन्दे ा अखबार है। उस अखबार द्वारा व्यापारियों से जबरदस्ती विज्ञापन मांगे जो है। एक–एक व्यापारी से पैसा इक्ट्ठा किया जाता हैं। उनसे चंदा मांगा जात हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

गृहमंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, इस रैजोल्यू ान में चंदे की बात कहां से आ गई अखबार की बात

कही से आ गई? इनकी तो अखबार का फोबिया हो गया है। ये हमे ाा जन संदे ा अखबार के बारें में बोलनते रहते है।

श्री सीता राम सिंगलाः उपाध्यक्ष महोदय, इनको सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। मै आगे बताना चाहता हूं कि गुडगांवा के अन्दर.....(ाोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंहः उपाध्यक्षम महोदय, इन्होने एक दीए पर अरबों रूपया इक्ट्ठा कर लिया। उसका हिसाबा भी तो बताएं कि वह कहा गया? (ाोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास भार्माः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर एक प्राईवेट मैम्बर्ज बिल पर डिस्क ान चल रही हैं सरकार को इस पर जवाब देने का मौका मिलेगा। (ाोर एवं व्यवधान) इनको विधान सभा में बैठकर रोब नही जमाना चाहिए। (ाोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंहः आपको कौन रोकता है? (ाोर एवं व्यवधान)

श्री सीता राम सिगलाः उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय को सूचित करनाचाहता हूं पता नही भााायद उनकी नालेज में यह बात है या नही। एम0 सी0 आर0 टी0 नाम की एक संस्था है। वहां की एक बिल्डिग है, जो टीचर्ज होस्टल है और वहां पर टीचर्ज ट्रेनिक के लिए आते है लेकि अब उस बिल्डिग पर जन सन्दे ा अखबारवाला का कब्जा है इसलिए

ठहरने वाले टीचर्ज को बड़ी परे ाानी का सामना करना पड़ता हैं वे सर्दी से मारे मारे फिर रहे है, उन लोगों के साथ बड़ी भारी ज्यादती है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात मै यह कहना चाहिए कि आज नोयड़ा में, दिल्ली के पास लोग धडाधड़ फैक्टरियां लगा रहे है। फरीदाबाद व बल्लभगढ़ से भी लोग अपने फैक्टरिया उठा उठा कर नोयडा ले जा रहे हैं क्योंकि वहां पर यू0 पी0 सरकार को प्रोर से उनाक काफी सहूलियते मुहैया की जाती हैं इसके इलावा मै बताना चाहता हूं कि फरीदाबाद, गुडगांव, बल्लभगढ़ व धारूहेड़ा में भी बड़ी बड़ी फैक्टरिया लोगों ने लगा रखी है लकिन अपने अपने हैड आफिसिज दिल्ली मे बना रखे है जिससे हरियाणा सरकार को सेल्ज टैक्स काबड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है सरकार को इस ओर वि ोश ध्यान देना चाहिये ताकि हरियाणा केा जो इस कारण से अैक्स का नुकसान हो रहा है, वह न हो ओर सारी आमदनी हरियाणा को हो। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर जतनी भी प्रोडक ान हाती है, वह हमारी बिजली के माध्यम से होती है। लेबर भी हमारी होती है, धरती भी हमारी है जहां पर ये फैक्टरिया है, लेकिन इनका सारा सेल्ज टैक्स दिल्ली को हो जाता है क्योंकि वहां इन फैक्टरियों के हैड आफिस हैं वहां दिल्ली के दफ्तरों में ही बैठकर माल ट्रांसफर होता हैं जो इन फैक्टरियों को माल बनकर तैयार हो जाता है तो उनका माल अन्य प्रदे ाों में जाकर बिकता हैं उनको फिर कम्पीटी ान के अन्दर आना पड़ता है ओर

इस कंपीटी ान में हरियाणा को टैकस का नुकसान हेता हैं इसलिए उपाध्यक्षम होदय, मेरा आपके द्वारा इस सारे सदन स `निवेदन है कि इस रैजोल्यू ान को सारी असैम्बली पास करे ओर पास करके कन्द्र सरकार को भेजा जाये। इसके ऊपर केन्द्रीय सरकार विचार करे ताकि हरियाणा के अन्दर होने वाली प्रोडक ान का हरियाणा को टैक्स मिले। इस से लगभग 200 करोड़ रूपए का सरकार को फायदा होगा।

श्री महा सिंह (राई): उपाध्यक्ष महोदय 1989 में हमारे एक माननीय साथी चौधरी रणजीत सिंह जी ने यह रैजोल्यू ान इस हाउस में पेश किया था। मै इसकी हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मै आपके माध्यम से इसरैजोल्यू ान की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपका व इस हाउस का ध्यान आकर्शित करने का प्रयास करूंगा ताकि यह हाउस इस को सर्व सम्मति से पास करके केन्द्र सरकार के पास भेज सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान को पालियामैंट में सन् 1982 में एक रैजोल्यू ान द्वारा 46 वी कांस्टीच्यू ान अमैडमैट हुई थी कि हरके स्टेट को ये अधिकार दे दिए जाए कि उनके प्रदे ा में जो इंडस्ट्रीज होगी, उनके हैड आफिस भी उसी प्रदे ा में रहेगे ओर उनकी प्रोक्क ान पर टैक्स उसी प्रांत क लोगों को मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप भली–भांति जानते है। कि हरियाणा प्रदे ा दिल्ली के चारों ओर बसा हुआ है और दिल्ली हिन्दुस्तान की राजधानी होने के कारण बड़े बड़े उद्योग हरियाणा की धरती पर

ही लगे हुए हैं उन सभी इंडस्ट्रीज का हरियाणा सरकार की ओर से बिजली पानी का प्रबन्ध करवाया जाता है। इस तरह हम अपने प्रदे ा के गरीब किसानों, मजदूरों दुकानदारों ओर छोटे उद्योगपति को बहुत बड़ी राहत दे सकते है इसलिए मै सरकार से पुरजोर अपील करने के लिए खड़ा हुआ हैं कि इसको स्पीकार करके सैट्रल गवर्नमैंट के पास भेजना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इस कन्साइनमैंट टैक्स का पैसा स्टेट को मिले ओर हम अपने आप पर लागू करसके। इसकेसाथ ाथ लागों मं इस टैक्स की एक और बड़ी अफरा–तफरी फैली हुई हैं दिल्ली में टैक्सिज के रेट कुछ है और हरियाणा में कुछ है। इस वजह से हरियाणा में टैक्स की चोरी होती है। अगर यह लागू हो जाए तो उससे वह चोरी भी मिट जाएगा। ऐसा करने से किसी कारखाना लगाने वाले को भी कोइ दिक्कत नही आएगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंअ बोर्ड ने भी पास कर रखी है मै समझता हूं कि इसके लिए सब से बड़ी दोशी पार्टी कांग्रेस रही हैं कांग्रेस पार्टी की यह आदत रही है ओर यह पावर को सैटरलाइज करती रही है।

श्री मोहम्मद असलम खांः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। पिछले डेढ़ साल से डा0 महा सिंह जी की सरकार है, अगर कांग्रेस की सरकार इस बारें में कुछ नही कर सकी तो इन्होने क्या करवा लिया?

श्री महा सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने हमे ाा सैटरलाइज्ड पावर में यकीन किया है। उसने कभी नही

चाहा चालीस साल के इतिहास में, कि पावर का डिसैटरलाईजे ान हो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत होती हैं वह सारी सत्ता अपने हाथ में रखना चाहती थी। केन्द्र में भी केवल एक आदमी के हाथ में थी। इसी कारण से 1982 के बाद यह बिल पास नही हो पाया। भाई असलम खां जी कह रहे थे कि डेढ़ साल से हामरी सरकार है। हमारी सरकार ने बहुत काम किए है, यही काम रह गया था, इसको भी अब की बार कर देगे, पहले असैम्बली से तो पा कर दे। मै इनको बिताना चाहता हूं कि राजीव गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के लोगों के साथ कितनी बे–इंसाफी की। भाायद वे वह दिन भूल गए, जब राजीव लौगोवाल समझता हुआ था ओर हरियाणा के लोगो ंको उस बारे ंमे ंपूछा तक नही गयाथा बन्दूक की नोक पर हरियाणा के हकों को छीन कर पंजाब को दे दिया गया। उसे बाद चौधरी देवी लाल जी ने मुहिम चलाई मैं तो चाहता हूं कि उस समय इन लोगों को अस्तीफा देकर मैदान में आ जाना चाहिए था। इसलिए मै कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सैटरलाइज्ड पावर में यकीन करती हैं जिसके कारण हरियाणा को इतना नुक्सान हुआ।

इसके साथ साथ एक बात और कानूनी तौर परआई। सभी स्टेटस के चीफ मिनिस्टर्ज ककी मीटिग बुलाई गई ओर सभी ने इस बता की वाजिब ठहराया थ्झा। फिर सरकारियो ंकमभ ान इब बात के लिए मुकर्रर किया गया कि सैटर और स्टेट्स के रिले ांज कैसे होने चाहिए। उस कमी ान ने अपनी रिपोर्ट दी

हम चाहते है उस की रिपोर्ट तरुन्त लागू रि दिया जाए ताकि सारी स्टेटों के रिले ान ठीहक हों और स्टेटों को उनकी पावर का हिस्स मिल सके। इसलिए मै। इसका समर्थन करता हूं। इसे साथ साथ्ज्ञ मै ंएक बाम यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी स्टेट में इंडस्ट्रीज ज्यादा पनपेगी, उनके दफ्तर यहां पर खोले जाएंगे ओरजो हमारे दे ा ओर प्रदे ा के सामने बेरोजगारी की समस्या है, वह हल होगी। इसके अलावा, टैकस के रूप में धन भी आएगा, उससे हामर पंरपज भी सर्व हो जाएगा। एक बात मै यह भी कहना चाहूंगा, हमारी सरकार बड़ी संजीदगी से उस बारें में गौर भी कर रही है ओर उसकी कांग्रेस के समय से हमारी मांग भी है। कि इस दे ा के बेरोजगारों के ''राईट–टू–वर्क'' का फण्डामैंटल राइटस में इन्कल्यूड कर दिया जाए। जब तक बैराजगारों के राइट–टू–वर्क को फण्डामैंटल राइटस मे ंइनक्ल्यूड कर दिया जाए तो बेरोजगारी की समस्या को अन्त हो सकता है मै सारे हाउस से अपील करना चाहूंगा कि हमें इस बारें में एक रैजोल्यू ान पास करना चाहिए कि हरियाणा के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, हरियाणा में चौधरी हुकम सिंह जी की सरकार, यह रैजोल्यू ान पास करती है कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए राइट–टू–वर्क का फण्डामैंटल राइट्स मे इन्ट्स में इन्कल्यूड कर रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, अंग्रेजी के टाईम में कुछ सिलैक्टिड लोगों को रोजगार देने का अधिकार था। महात्मा गांधी जी ने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए लड़ाईयों लडत्री ओर दे ा आजाद हुआ। दे ा आजाद होने के बाद जब संविधान बना तो

उसमे ंपहल कलम ये सह लिखा गया कि हर दे ाावी को रइट टू वोट दिया जाए। जिस तरह से हमारे दे ा के लोगों को वोट देने का मौलिक अधिकार है, उसी तरै से बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए राइट–टू–वर्क को फण्डामैंटल राइटस में इन्कल्यूड किया जाए। आज हिन्दूस्तान के अन्दर जितनी लेट खसूट मची हुई है, जितनी क्रप ान हो रही है। जितनी उग्रवादी घटनाए बढ़ती जा रही है, उसे पीछे मेन कारण गरीबी और बेरोजगारी है। अगर हमारे दे ा की केन्द्रीय सरकार ओर हमारे प्रदे ा की सरकार गरीबी, बेरोजगारी ओर क्रप ान की जड़ से मिटा दे तो सारी समस्याएं हल हो सकती है। इन समस्याओं का निदान जरूरी हैं डिप्टी स्पीकरसाहब इंडस्ट्रीज की जा लेबर है उसमें जो अनरेस्ट हैं उसका हल भी निकला जासकता है यदि लेबर को इंडस्ट्रीज को जो लेबर है उसमें भी अनरेस्ट है। उसका हल भी निकला जा सकता हैं यदि लेबर को इंडस्ट्रीज की मैनेजमैंअ में हिस्सा दे दिया जाए ते उनकी सारी समस्याए हल हा सकती है। जितनी भी मिले है, जितनी भी फैक्ट्रिीया है, जितने भी कारखाने है, उन सभी की मैनेजेमैंटस में यदि लेबर को हिस्सा दे दिया जाए तो उससे लेबर ओर मालिक के रिले ान बड़े मधुर हो सकते है यदि किसी फैक्ट्री, इडस्ट्री या कारखाने मे ंकोई ऐसी बात हो जाए तो वह आपस मे मिल बैठ करे उसका समाधान करसते है।

जहां तक दे ा में प्रदे ा में क्रप ान की बात है, उस बारे में हमरे सभी सदस्य चिन्तित है क्योंकि यह सभ बहुत ही

जिम्मेदार आदमी है। हम ही नही बल्कि सारा दे ा इस बारे में चिन्तित है। डिप्टी स्पीकरसाहब, करप ान को मिटाने के लिए सरकार को ऐसी पद्धति चालनी चाहिए जिससे यह मिट जाए। कांग्रेस के टाईम में थ्री टायर सिस्टम था यदि उसक तोड कर टू टायर सिसम्अ बना दिया जाए तो क्रप्शन की समस्या किसी हद तक मिट सकती है जो थ्री टायर सिस्टम है। उसमें इस तरह से है कि एक तरफ प्रोडयूसर है, एक तरह कंज्यूमर है और इनके बची मे मिडल मैन हैं प्रोड्यूसर जो चीज पैदा करता है उसको उसकी पैदावारों की जायज कीमत नही मिलती क्योकि बची में मिडलमैन है। इस कारण से आगे कंज्यूमर को नही मिलती हैं क्योकि इनके बची में मिडमैन बैठा हैं जो क्रप्शन की जड़ हैं जो मिडलैन है, वह जब प्रौड्यूसर से कोई चीज लेता है तो तोल में भी ज्यादा लेता और जायज कीमत भी नही देता ओर वही चीज कंम्मूयर को तोल में कम देता है,रेट भी ज्यादा वसूल करता है ओर मिलावट भी करता है। मिडलमैन के कारण ही मंहगाई बढती है। सारी दुनिया के अधिकां ा दे ाों के प्रोड्यूसर ओर कंज्यूमर के डायरैक्ट संबंध है। यानी उनकी डायरैक्ट एप्रोच है। इसलिए मै कहना चाहूंगा कि जो चीफ प्रोड्यूसर पैदा करता है वह डायरैक्ट कंज्यूमर के पास पहुंच जाए ताकि प्रोडयूसर को ठीक भाव मिल जाए ओर कंज्यूमर को भी वह चीज रेट पर मिल जाए।

क्रप ान का सबसे बड़ा ईलाज है टू टायर सिस्टम का लागू होना। मै दावा करता हूं कि यदि यह सिस्टम लागू हो जाए

तो दे ज्ञ से 90 प्रति ात क्र्प ान मिट सकती ळैं आज दे ा के सामने क्र्प ान एक ज्वलन्त समस्या बनी हुई है, इस पर काबू बाया जा सकता है। इसके साथ साथ मै सरकार से चाहूंगा कि जितने कड़े कदम सरकार को इस बारें में उठाने हो, वह अव य उठाए। इसके साथ्ज्ञ साथ मे ंचाहूंगा कि सरकार बेरोजारी को दूर करने के लिए नौजवानो ंका ेबजनैस की और प्रोत्साहित करने का प्रबंध करे। इस बारें में मेरी सरकार से गुजरि ा है कि प ाुओं की तरफ वि ोश ध्यान दिया जाए। वैसे सरकार पहले ही इस तफ काफी ध्यान दे रही है वह भी 5–6 महीने तक ही देती है अगर उनकी कोस ब्रोंडिग का प्रबन्ध आज के वैज्ञानिक ढंग से हो जाए तो वही देसी गाय बहुत अधिक दूर दे सकती है। सरकार अब यूज फारम युजैस का भी एक प्रोग्राम बना रही है जिसके तहत आवारा गाये जो दूध नही देती, उनको भी फ्रोजन सीमन इस्तेमाल किया जााात ळथा लेकिन वह एक जि से दूसरे जिले में ले जाते समय खबरा हो जाता था। गर्मी की वजह से ता ेबहुत ही खबरा हो जात था लेकिन अब जाता है ''फ्रोजन सीमन'' का सईटिफिक सिस्टम चला है यह बहुत अच्छा है। इसके जल्दी खराब होने की संभावना नही रहती। इस ''फ्रोजन सीमन'' के जरिए जिन देसी गायों को क्रोस ब्रीडिग की जाएगी, वे 25–30 ओर 35 किलोग्राम तक दूध दे सकती है। गायों को रखे जाने की सुविधा सरकार को हरियाणा के लड़कों को देनी चहिए। अगर सरकार इस बारे में उचित प्रबंध कर देती है तो ऐसे लड़के 1000 रूपया महीनाघर बैठे बैठाए कमासकते हैं इस क्रोस ब्रीडिग की वजह से जो गाय पैदा

होगी, वे दूध भी अधिक देगी औरवे मुि कल से दो महीने ही ड्राई रह पाएंगी। अगर सरकार ऐसा प्रबंध कर सकती ह`ते बहुत अच्छा होगा क्योंकि इससे बेरोजगारी भी काफी दूर हो सकती है ंउपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मै इस कंसाईनमेंट टैक्स कर जो गैर सरकारी संकल्प आया है, उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री बनारसी दास गुप्ता (भिवानी): उपाध्यक्ष महोदय, कन्साईनमेंट टैक्सय का मामला पिछले 15–20 सालों से चल रहा है। इस बारे में कई बैठके केन्द्रीय स्तर पर हुई है जिनमें मैं भी भागिमल होता रहा हूं कईबारमुख्य मंत्रियों के सम्मेलन हुए। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में जो जिकर है कि 1984 से सभी प्रदे ाों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें कन्साईनमेंट टैक्स लगाने की सभी मुख्य मंत्रियों की सहमति थी। उसी के प चात उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने लोक सभी ने बिक्री कर कानून में सं ाोधन करने का अधिकार प्राप्त कर लिया लेकिन उसके बावजूद उसे लागू नही किया गया। मुझ बड़ी हैरानी है कि इस मे आज तक वह सं ाोधन नही यिकागया जो किया जाना चाहिए था। जब चौधरी देवी लाल जी की सरकार बनी तो मुख्य मंत्रियों का और कराधान मंत्रियों का एक सम्मेलन दिल्ली के विज्ञान भवन में बुलाया गया था, जब राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे। उस समय बड़े विस्तार के साथ कन्साईनमेंट टैक्स पर चर्चा हुई थी ओर यह फैसला हुआ था कि यह सं ाोधन जरूर किया

जाऐगा। हमने प्रधान मंत्री जी से कहा कि यह फैसला कई बार हो चुका हैं लेकिन इस पर अमल नही हुआ। आप समय निर्धारित करके टाईम बाउंड प्रोग्राम बना दे कि कब तक यह सं ाोधित टैक्स लगा दिया जाएगा। प्रधान मंत्री जी ने सभी मुख्य मन्त्रियों को मौजूदगी में यह वायदा किया था कि अगले मौनसून अधिवे ान में इसे पास कर दिया जाएगा। उपाध्यख महोदय, यदि इस बात की पुश्टि करनी हो तो उस मीटिंग को प्रोसोडिगज को देखा जा सकता है। प्रोसीडिग्ज में हय बात जरूर लिखी मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मौनसून सत्र भी निकल गया तथा पालियामं के कई और सत्र भी निकल गए, सरकार भी बदल गई ओर नई सरकार केन्द्र मे आई। सौभाग्य से नई सरकारमें हमार हरियाणा प्रदे ा के नता चौधरी देवी लाल उप–प्रधान मंत्री बने। जब भी मै दिल्ली में 1–2 बार उनकी सेवा में उपस्थित हुआ तो इस कन्साईनमैंट टैक्स के बारें में उनकों स्मरण करवाया ओर निवेदन किया कि चौधरी साहब, अब मौक ाहै इसे पास करवा लो, इस समय सरकार आपके हाथ में हैं यदि केन्द्रीय सरकार यह कन्साईनमैंट टैक्स पास कर दे तो टैक्स लगाने से हरियाणा को 50 करोड़ से 100 करोड़ रूपये का आदमनी हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि हरियाणा में जो उद्योग फरीदाबाद, यमुना नगर सोनीपत, गुडगांव या धारूहेड़ा में लगे है, उनके लिए जमीन सरकार देती है। सोचने वाली बात यह है कि सरकार के पास जमीन है कहा सरकार गरीब किसानों को जमीन ऐक्वायर करके उद्योग लगाने के लि देता है। यह

जमीन उद्योगों को इसलिए दी ाजती हैं कि इससे राज्य सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। उद्योग लगने से ि ाक्षित ओर अि ाक्षित नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय प्रदे ज्ञ की गरीबी दूर करने के लिए ओर बेराजगारी को काम देने के लिए, प्रदे ा की प्रगति के लिए प्रदे ज्ञका सही ढंग से औद्योगिकरण किया जाए। कृशि के ऊपर तो बड़ा भारी बोझ है। उपाध्यक्ष महोदय, यू तो हरियाणा प्रदे ा ने कृशि के क्षेत्र में रिमार्केबल तरक्की की हैं ओर कृशि में बड़ा भारी विकास हुआ हैं जब हरियाणा एग्जिस्टैंस में आया तो एक जमाना था, जब हमें एक लाख टन अनाज बाहर से मंगवा कर अपने लोगों का निर्वाह करना पड़ताथा लेकिन आज लाखों टन अनाज हम बाहर भेज रहे है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा के मेहनती किसान की बदौलता 50 लाख टन अनाज हमने अपनी जरूरत से बचा कर उन राज्यों को भेजा, जहां अन्न की कमी हैं उपाध्यक्ष महोदय कृशि के क्षेत्र में बड़ा भारी विकास हुआ हैं अगर एस0 आई0 एल0 बना दी जाए तो हरियाणा के भिवानी, महेन्द्रगढ़, गुडगांवा, रोहतक, आदिजिलों केा सिचाई के लिए पूरा पानी उपलब्ध हो जाएगा और हरियाणा प्रदे ा कृशि के क्षेत्र में और आगे भी बढ़ जाएगा तथा अन्न उत्पादन में पंजाब से भी आगे निकल जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक हकीकत है कि प्रदे ा को गरीबी तो तभी दूर हो सकती है जब प्रदे ा में सभी का रोजगार मिलै। रोजगार के लिए उद्योग–धन्धों का विकास जरूरी हैं इस में भाक नही कि प्रदे ा में बहुत से उद्योग लगे भी है लेकिन इन उद्योगों

से सरकार को काई लाभ नही हो रहा है। हम जमीन दे, बिजली दे, पानी दे तथा सरकार सारे साधन उनको उपब्ध कर कर उद्योग लगवाए ओर उद्योगति अपना सेल्ज औफिसदिल्ली में खोल ले तो जो टैक्स हमें मिलना चहिए था, वह आय केन्दीय सरकार ले जाए। कस्टम डयूटी और एक्साईज भी केन्द्रीय सरकार को मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस में कोई भाक नही कि इसमें से प्रदे ा को भी हिस्सा मिलताहैं लेकिन पूरा टैक्स तो प्रदे ा को बिक्री कर से ही मिलता है ओर उसी से स्टेट का राजस्व बढ़ सकता है। सारा राजस्व तो दिल्ली को चला जाता है। क्योंकि उन्होने अपने सेल्ज आफिस दिल्ली में बना लिए है। इस तरह से हरियाणा प्रदे ा को बड़ा भारी घाटा हो रहा है। वर्शा से हम चीख चिल्ला रहे हैं केवल हरियाणा ही नही चिल्ला रहा हैं उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे सारे प्रदे ा भी चिल्ला रहे है। मगर इसके बावजूद भी वह लागू नही किया जाता इसका क्या कारा है मै तो इसका एक ही कारण समझता हू कि इस दे ा में जो मौनपली हाउसिज है, जो बडे–बड़े 10–20–30 औद्योगिक घराने है, उनके हाथ बड़े लम्बे है। वह इस प्रकार से प्रबंध कर लेते है, मैनीपुलेट करते है कि जब भी कभी इस प्रकार की मांग आती है, इसको पास करने की मांग आती है तो वह वह किसी न किसी तरह से इसको टालने में सफल हो जतो है। इसलिए मै यह समझता हूं कि हमारे लिए यह जो एक साल कावक्त आया था,उयह बए बहुत ही अच्छा मौका था। हम इस मौके में अगर उसको पास करवा देते तो हमारे वित्त मंत्री जी की समस्या हल हो जाती औरयह जो उन्होने 95 करोड

का घाटा बताया है, मुझे आ ाा है कि अकेला कन्साईनमैट टैक्स ही इस घाटे का पूरा कर देता। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी आज यह देखते है कि जब हम भिवानी से चलकर यहां पर आते है तेा कितनी सड़के टूटी हुई हैं आप भी आते है और मै भी आता हूं सड़कों को कितनी बुरी हालत है। उन पर गाड़ी चल नह ीसकती। बस चल नही सकती। आज एक–एक कतरा तेल बचाने की जरूरत है क्योंकि इसकी बहुत कमी हैं सड़के ठीक न होने की वजह से ज्यादा तेल भ जलता है। टायर भी ज्यादा घिसते हैं रोडवेज का भी नुक्सान होता है ओर कारों को भी नुक्सान हेाता है। इन सड़कों की रिपेयर कन्साईनमैंट टैक्स से मिलने वाली रकम से बड़ी आसानी से मिल सकती हैं यही नही, उनके प्रकार के दूसरे विकास के काम भी हो सकते है। इसलिए हम तो यह प्रस्ताव पास करेगे ही करेगे, इसमें कोइ सदेह नही है। यह बहुत देर तक लब्ति रह चुका हैं कोई सै ान्ज में इस प्रकार पर विचार भी हो चुका हैं इसलिए अब इसकों पास किया जाए ओर इसको लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार का पूरा प्रै ार डाला जाए। उस पर सब विचार विम र्ा कर चुके है। मेरे ख्याल से कोई भी सदस्य इससमे मतभेदनही रखता, इसलिए इसकेा सर्वसम्मति से पास यिका जाए ताकि और इससे हरियाणा को लाभ हो । इन भाब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मै अपना स्थान लेता हूं।

श्री कैला ा चन्द भार्मा (नारनौल): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सथी माननीय गुप्ता जी ने बडे ही विस्तार से यह बातया कि सन 1982में सविधान में सं ाोधन कर दिया गया था लेकिन एकट में इस बारें में अभी तक अमैडमैट नही की गयी हैं कई राज्य अपने प्रदे ाों में यह कन्साईनमैंट टैक्स लगाना चाहते है। उसे लिए केन्द्रीय बिक्री कर में सं ाोधन करने का अधिकार केन्द्र सरकार को दिया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण मामला था कि इसके लिए हमें संविधान के अन्द सं ाोधन करना पड़ा। 1982 से लेक रआज तक उस बिक्री कर अधिनियम में सं ाोधन नही किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है। कि वह दिल्ली के तीन तरफ लगा हुआ है ओर जो हरियाणा के औद्योगिक नगर है, वे भी लगभग दिल्ली के लगते हुए है ओर उसका आर्थिक दृश्टि से सब से अधिक नुक्सान जो हो रहा हैं वह हरियाणा को ही हो रहा हैं इस नुक्सान के बारें में मेरे स`पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि यह सरकार इस काम मे ंभी राजनीति की सेच रखती रही हैं हमने हरियाणा की जनता से जो वायदे किए थे क्या हमने कभी सोचा है कि उन वायदों को कभी पूरा करने का प्रयत किया जाए? उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गावों में कहावत है कि और सांग भर जासकते है, सांग भर कर जनता को बकहा सकते है लेकिन बोरह का सांग नही भरा जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होने तो यह सांग भी भरा लिया। इन लोगों ने य कहना भाुय किया था जिब हमें दिल्ली में जो नोट छापने वाली म ाीन है, मिल जाएगी तो विकास के कार्य हरियाणा

मे ंखूब होगे। उपाध्यक्ष मोद नोट छापने की म ीन तो हमें वास्तव में मिली लेकिन हमने उस म ीन की ओर ध्यान नही दिया। हरियाणा के पास तीन म ीने थी। एक कंसाईनमैंट टैक्स की म ीन दूसरी म ीन थी करनाल कातेल भाोधक कारखाना और तीसरी म ीन थी एस0 वाई0 एल0 लहर। उपाध्यक्ष महोदय, हम जनता के समने वायदाकरके आए थे लकिन हम केवल रैल और भाशणों से ह लोगों के बहकाते रहे। रैलियों और भाशणों से तो कोई विकास कार्य हो नही सकता। वायदों को पूरा करने के लिए तो धन चाहिए। रैलियों और भाशणों ने तेा हमें दिल्ली में भिजवा दिया था लेकिन उसे बाद हमोर साथियों ने काई ान नही दिया कि हम जनता से क्या वायदा करके आस थे हमें बैठकर विचार करना चाहिए था धन कैसे मिल सकता हैं, जिससे हरियाणा का विकास हो। उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी हम उनको गालियां निकालते रहते थे कि हरियाणा का विकास इन कांग्रेस वालो के कारण नही होता। वे लोग हरियाणा का धन नहीदते ह लकिन सौभाग्य की बात है कि जनता ने उनकासफाया कर दिया। उनकी सजा दे दी। उपाध्यक्ष मोदय, हमारी सरकार को आए हुए डेढ़ साल हो गया लेकिन इन महत्वपूर्ण विशय पर हमने कभी नही सोचा। डा0 महासिंह ने कहा कि दो सौ करोड़ रूपए सालाना इस टैक्स से आमदनी होगी। सात सौ करोड़ रूपए का अगर बजट हो और उससात सौ करोड़ रूपए में दो सौ करोड़ रूपया कंसाईनमैंट टैक्स से आ जाए तेा इससे बढ़कर अच्छी बात और क्या हेा सकती है? यह बात सरकारी

पक्ष के लोग कह रहे है लेकिनहमने इस तरफ कभी सेचा ही नही। अफसोस की बात है कि जिस व्यक्ति ने इन सारी चीजों के लिए, मतलबय यह है कि तीन नोट छापने वाली म ीनों के लिए आंदोलन किया और जनता ने उस आदमी को चुनकर दिल्ली भेजा और उप प्रधानमंत्री बना दिया लेकिन उसने इस तरफ कोई ध्यान नही दिया। वह वहां जाकर सब कुद भूल गया। उपाध्यक्ष महोदय, कंसाइनमैंट टैक्स का विशय बहुत ही महत्वपूर्ण विशय है। लेकिन पन्द्रह महीने में इस सरकार ने, जिसमें हरियाणा का उप प्रधान मंत्री हो, कोई ध्यान नही दिया। यह विशय तीन सै ाज से हमारे पास पैडिग है। गुप्ता जी अभी कह रहे थे हमने अपना समय बर्बाद करदिया। उपाध्यक्ष महोदय, मै तो यह कहना चाहता हू कि हर चीज का राजनीति की तराजू मे ंनही तोलना चाहिए हमें गम्भीर होकर विचार करना चाहिए था। मै हरियाणा के विधायक साथियों को कहना चाहता हू कि हम हर बात में जनता को मूर्ख नही बना सकते। हमने पहले बहुत रैलियां की बहुत भाशण दिए और उसे परिणामस्वरूप हरियाण की जनता ने हमें सरकार दे दी। रैलियों के द्वारा नोट छापने का म ाोन मांगे थे, वह अधिकार भी जनता ने हमें दे दिया लेकिन हमने उन म ीनों का प्रयोग नही किया। उपाध्यक्ष महोदय हमें तेल भाोधक कारखाने से मिल सकते थे, लेकिन उसको बनाने की तरफ हमने कोई ध्यान नही दिया। उपाध्यक्ष महोदय, एस0 वाई0 एल0 की तरह अगर हमने ध्यान दिया होता तो हमारे हरियाणा की हमारे किसानों को बहुत उन्नति हो सकती थी हमार आय बढ़ सकती थी लकिन हमने अपनी जनता

को रैली करके और भाशण देकर टाल दिया। हरियणा के मुख्यि के हाथ में सरकार आई थी। लेकिन उसने इन बातों की ओर कोई ध्यान नही दिया। एस0 वाई0 एल0 का मामला भी बहुत महत्वपूर्ण हैं इस बात का भी बहुत भाोर मचाया जाता था और कहा जाता था कि कांग्रेस सरकार इस नहर को नही बनने देती, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, पन्द्रह महीने से तो हमारी अपनी सरकार थी, हमने कुछ नही किया। केन्द्र सरकार पर ईमानदारी से दवाब डालकर और सेना तैनात करवाकर एस0 वाई0 एल0 का निम्रण करने का प्रयत्न करते तो यह नहर अव यय बन सकती थी लेकिन हमने कुछ नही किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इस सारे सदन से प्रार्थना है कि इस सारे मैटर को लम्बा न करके मिलकर सरकार के पास करवा के केन्द्र सरकार के पास भेजे, जैसे गुप्ता जी ने बताया कि इसके लिए प्रयत्न तो बहुत हुए लेकिन हर प्रयत्न पीछे एक दिक्कत हुआ करती थी कि केन्द्रीय सरकार ने मुख्य मंत्रियों की बैठक होने के बाद विकास बोर्डो की बैठके होने के बाद, योजना आयोग की बैठक होने के बाद इसकी सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करते हुए व्यवहारिक रूप नही दिया। दूसरी ओर मै यह बताना चाहता हूं कि सरकारने बुढापा पैन् ान इत्यादि के कारण अपने बजट में 105 करोड़ रूपया बुढापा पैन्शन के लिए रखा लिया तो स्वाभाविक ही है कि पैसा न होने की वजह से राज्य की सड़कों की हालत दयनीय होगी रोडज की रिपेयर नही होगी, विद्यालय अपग्रेड नही

होगे। अगर अपग्रेड नही होगे तो स्कूलों कालेजों में अध्यापक नही मिलेगे। इसलिए मेरी आपसे व इस हाउस से प्रार्थना है कि यह जो कन्साईनमैंट का मामला है, यह साकरा पैसे से जुडा हुआ हैं इसलिए हर और से चिंता करके कारण हरियाणा राज्य की आय बढ़ेगी। अगर ऐसा न किया गया तो जैसा कि सिंगला साहब ने कहा कि इससे भ्रश्टाचार को बढ़ावा मिलेगा क्योकि सरकार आफिसर्ज को, पूंजीपतियों को जानबूझ कर लाभ देने के लिए ऐसा अवसर देगी तो स्वाभाविक ही हैं कि सरकार के ऐसा न करने से अधिकारी लोग, पूंजीपति लोग भ्रश्टाचार को बढ़ावा देगे ओर वह कन्साईनमैंट टैक्स का पैसा भ्रश्टाचार के रूप में, सरकार को न जा करे अधिकारियें व पूजीपतियों की तिजोरियों में जाता है। और पूंजीपतियों को और पूजी बनाने के काम आता है। इसलिए हरियाणा की भोगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह अत्यन्त आव यक है कि हरियाणा के लिए कन्याईनमैंट टैक्स लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार हरियाणा को दे। मै ज्यादा न कहते हुए उपाध्यक्ष महोदय, केवल यही कहूंगा कि यह एक मूलभूत विशय है कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। हम सब को अपने नेताओं व दल से यह कहना चाहिए कि यह जो आर्थिक विशय है, यांग करने का विशय नही है, यह तालिया बजवाने का विशय नही हैं इसको लागू करनवाने के लिए हमारी सरकार को दिल से चिन्ता करनी चाहिए, दिल से प्रयत्न करना चाहिए। ताकि हरियाणा की आमदनी बढ़ सके। इन भाब्दों के साथ

मै, उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं। जय हिन्द।

पु ापालन राज्या मंत्री (श्री कुलबरी सिंह मलिक): उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का सम दिया, उसके लिए मै आपका धन्यवाद करता हूं। 24 मार्च, 1988 हो कहारम `इस सदनके सम्ममानित सदस्य श्री रणजीत सिंह सिंह जी ने जो कन्साईनमैट टैक्स के बारें में रेजोल्यू ान मूव किया था। मैं उसका समर्थन करने ` लिए खड़ा हुआ हूं। जब 1982 में पालियामैंट के न्दर 46 वी अमैडमैंअ की गई थी तो उसे बाद आज तक लगभग 9 साल का समय व्यतीन हो चुका है। केन्द्र सरकार ने इस अमैन्डमैंट को लागू करने के लिए, एक्साईज एण्ड टै ो ार विभाग द्वारा, गवर्नमैन्ट के एक्अ में तरमीम करने की ओर कोई ध्यान नही दिया। इसका कारण मै समझता हूं कि पिछले तीन सालों को छोड़कर कांग्रेस की और व्यापारियों की आपसी मिलीभगत के कारण यह नही हो सका है जब चुनाव आते है तो कांग्रस सरकार फरीदाबाद के अन्छर जाती है और लोगों से फण्डज के रू॰ मं, चन्इद्र के रू॰ मे ंपैसे इकट्ठे करती रती है लेकिन हरियाणा की तरक्की की बात को भूल जाते रहे है। उपाध्यक्ष महोदय, मै अभी पी0ए0सी0 की 1985–86 की रिपोर्ट को पढ़रहा था। उसको पढ़ने यह ज्ञता हुआ है कि 31 मार्च 1986 को कितने कितने ऐरियर्ज बकाया थे। सेल्ज टैक्स क 33.2 करोड सेल्ज ऐक्साईज के 3.12 करोड, टैक्से ान आनु गुडज एण्ड

पैसिजर्ज 92 करोड़ व ऐन्टरटनमैंट एण्ड भाो टैक्स के .29 करोड। तो इस प्रकार 7.35 करोड की राि ा एरियर्ज के रूप में बकाया थी इसका मेन कारण कांग्रेस सरकार और व्यापरियों की आपसी मिलीभगत ही था जिसके कारण सरकार ने कभी हरियाणा की तरक्की की ओर ध्या नही नही दिया। आज ये लोगं यहां पर नोट छापने वाली म ीन का जिकर करते है। ये नोट छापन`वाली म ीनें किसी की रि वत के रूप में पैस नही देना है, देते हैं उपाध्यक्ष होदय जो गरीब लोग है, महनती लोगं अपने खून पसीने की कर्मी से सारे दे ा का पेट भरते है,सवेरे 4 बजे उठकर धरती माता को सीना चीरते है, उनको अनजा के रू॰ में अच्छे दाम दिए।। चाहे गेहूं थ्याा, चाहे चासल थे और चाहे गन्ना था, हर एक चीज के दाम बढ़ा चढा कर दिए है। इसी तरह से हमारे आदरणीय नेता चौधरी देवी लाल जी ने चुनाव से पहले जो आ वासन दिए, उनको पूरा करने की पूरी पूर कोि ा ा की है। इसी तरह से इस टैक्स से जो हमें 50 करोड़ रूपया सालाना मिलना चाहिए था, अगर वह मिल जाता हाते आज हरियाणा बहुत ज्यादा तरक्की करता। हमारे जींद जिले में एक कहावत है। वहां पर दो गांव है। भोंगरा ओर बुडान वहां परएक कुतिया रहती थी। वह भोंगरा में तो खाती थी ओर जुगाली बुडान में करती थी। इसलिए यह कहावत म ाहूर थी कि खावे पीवे भोंगरे, जा भौसे बुडान। यानी कारखाने तो सारे हरियाणा में लगे हुए है और टैक्स देते है दिल्ली को। इस तरह अगर यह टैक्स हरियाणा को ही मिलता तो हरियाणा की आज दूसरी ही हालत होती। तो मै कहना

चाहूंगा कि आज हरियाणा परबड़ा भारी बोझ हैं कल जब बजट की मांगे पास हुई थी तो उस समय ये सारी बातें आई थी कि किस तरह से सौ करोड़ रूपए से ऊपर वृद्धावस्था पैन् ान के ऊपर खर्च किया जा रहा हैं हमारे बादरणीय नेता चोधरी देवी लाल ने यह नई मिसाल कायम की है। ये लोग कहते है कि इस सरकार ने अपने वायदे पूरे नही किए है। पैन् ान वाला वायदा कोई मामूली वायदा नही था। इससे हमारे बुजुगों को सम्मान मिला हैं आज वे महसूस करते है कि यह उनकी अपनी सरकार है ओर उनका अपना ही राज हैं इसी तरह से पिछले सप्ताह इन्होने मगरमच्छ के आसूं बहाए थे कि सरकार ने मुलाजिमों की डिमांड पूरी नही कही। हमने उनसे बातचीत करके उनकी डिमांडज को माना है ओरउससे तीस करोड़ रूपए से ज्यादा हमारे स्टेट के एक्सचैकर परबोझ पड़ा है। इसी तरह से बसां के नुक्सान से भी बोझ बढ़ा है। इसी तरह से जो हमारी बसे फूी गई, उनकी जगह हमें नई बसें खरीदनी पड़ी उस वजह से भी हमारा नुक्सान हुआ है। यह सरकार किसानों ओर मजदूरों की है लकिन आज पैसे के अभ्ज्ञवव की वजह से कई जगह हम पूरे माइनर नही बान सके है। कई जगह बाढ का पानी ज्यादा है,वहां पर ड्रेन्ज खोदनी चाहिए लकिन पैसे की कमी की वजह से ऐसा नही कर पा रहे है। इस तरह से हस्पताल चाहे वे आदमियों के हो या प ाुओं के हो,उने लिए भी सरकार बहुत चिन्तित है। वहां पर जितनी दवई होनी चाहिए उतनी नही दे पार रहे है। हम प ाुओं के हस्पतालों में बहुत कम दवाई भेज पाते है। सरकार की अपनी मजबूरी है। जिसकी वजह से पूरी

दवई वहां नही पहुंच पा रही है। इसी तरह से आदमियों के लिए ओर प ाुओं के लिए नई डिस्पैसरीज खोली जाने चाहिए। इसके लिए भी काफी पैसे की जरूरत हैं दे ा को आजाद हुए आज 44 साल हो गए है लेकिन हमारे गांवों की हालत अब भी बहुत खराब है। भाहरों मे ंतो हर रोज अच्छे से अच्छा काम हो रहा है ओर भज्ञहर रात को भी दुलहन की तह चमकते है लेकिन देहात में कीचड़ ही कीचड़ हैं देहात की गलियां आज भी कच्ची है। सरकार इनकी हालत सुधारने के लिए बहुत कोि ा ा करती है। उनकों डिमांड के मुताबिक बहुत सी ग्रांटस भा दी गई है। मैचिग ग्रांट के रूप में भी सरकार ने काफी पैसा दिया है। 43 साल का गंद तीनसाल में धुलने वाला नही है। क्योंकि पैसे की बहजुत कमी है, इसीलिए आज देहात भाहरों से बहुत पीछ है। कुछ लोग कहते है कि यह सरकार भाहरों और देहातात के बची में लड़ाई करवा रही हैं भाहरों ओ देहातों के बची में कोई लड़ाई नही करवा रही, देहात ओर भाहर का तो चोलल दामन का साथ है। जब देहात अनाज की पैदावार करता है तो मंड़ी वाले बहुत क्षु ाहाल होते है। लेकिन जब ओले पड़ते है याबढ़ आती है या सूखा पड़ जात है तो भाहर वाले उस समय मक्खी मातर है क्योंि किसी मंडी वाले को कोई काम नही मिलता। भाहर वालों को मुनाफा भी देहात से ही मिलता हैं इसलिए भाहर वाले देहात पर ही निर्भर करते हैं भाहर ते क्या देहात पर तो सारा दे ा निर्भर करता है। देहात के लोगों बड़े सीधे सादे और भोले होते है। इन की नयीत बिल्कुल साफ हाती हैं वह भाहर वालों पर पूरा वि वास करते है। लकिन

भाहर वाले देहात वालों की हर बात की अनदेक्षी करते है और ज्यादासे ज्यादा बजट का हिस्सा भाहरों में लगवाने की कोि ा ा करते है। हमारे इससदन में जो विधायक भाहरेां से चुनकर आए है, उनको देहातों के बारें में कुछ पता नही है। वह यह नही जाते कि दे ा की रीढ़ की हड्डी किसान हैं इसलिए मै कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस बजट का 71 परसैन्ट पसा ग्रामीण क्षेत्र के विाकस के लिए खर्च करने जा रही है। यह हमारी सरकार के लिए बड़े गर्व की बात है, गर्व की ही बता नही है बल्कि दे ाभक्ति की बात है। यदि हरियाणा खु ाहाल हेाता है तो सारा दैहात खु ाहाल होता है, यदि सारा देहात खु ाहाल होता होता है तो सारा राश्ट्र खु ाहाल होता है। इसी तरह से सड़कों का जिकर आया। मै यह भी कहूंगाकि आज सड़कों को कुछ कमी भी जरूरी हैं कुछसड़के टूटी फुटी हुई हैं और अधूरी पड़ी है, उनेा पूरा किया जाएगा इसी तरह से हमारी सरकार ने मैचिग ग्रांट भी दी हैं यदि किसी कन्या स्कूल के लिए ग्रांट की जरूरत है तेा सरकार तीन गुणा पैसा देती हे, पहले ऐसी मिसाल नही थी कि लड़कियों के स्कूलों को तीनगुणा ग्रांट मिलती हो। हमार फाइनैस मिनिस्टर साहब ने हाउस में कह है कि ग्रांट की कोई कमी नही रहेगी। (ाोर)

श्री राम बिलास भार्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे है कि क्नया विद्यालयों को तीन गुणा ग्रांट दी जाती है वह तो बहुत पहले बन्द कर दी गइ थी अब नही दी जा रही है।

श्री कुलबीर सिंह मलिकः भार्मा जी आप तो वैसे ही कर रहे है। हमारी सरकार ने अपने प्रदे ज्ञ में कुछ कालेज ओर स्कूल भी खोलने है उने लिए पैसक की जरूरत है। इसके अलावा किसानों को सचिाई के पानी की कमी है, जैसे मैने पहले बताया है कि उसे लिए हामर सरकार नके कुछ माईनर्ज भी खोदनी है। इसी तरह से कुछ टयूबवैल्ज की बिजली के कनैक ान भी देने है, ट्रांसफारमर भी लगाने है जिसके कारण हमार सरकार का`पैसे की बहत ज्यदा जरूरत है। हरियाणा स्टेट एक प्रोग्रैसिव स्टेट हैं और इस बात को सारी दूनिया मानती है। कि हरियाणा स्टेट एक प्रोग्रसिव स्टेट है। हरियाणा प्रदे ा के सामने हरसमय चेलेंज रहता है क्योक पंजाब स्टैट जो हमारी पड़ोसी स्टेट है, वहा टरेरिस्ट ऐक्टिविटीज हर रोज हाती है। पजाब में हररोज 20–30 आदमी मार दिए जात`है। यदि इस किस्म की वारदातें पडौसी स्टेट में होती हों तेा हरियाण ों भी उसका असर हो सकता है लकिन मै यह बात बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने हमें उन एक्टिविटीज से ही नही बचाया बल्कि दिल्ली की सरकार को भी बचाया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस कन्साइनमैंट टैक्स के बारे ंमें मै एक दो बाते और कहना चाहूंगा। जो कारखाने हरियाणा में लगते है।, वह हरियाणा की जमीन परलकते है उनको बिजली व पानी हरियाणा से मिलता हैं जब कांग्रेस का राज था, उस समय कारखानेदारों को व दूसरे लोगों का बिजली के लिए तरसना पड़ता था लेकिन आज दिन राम कारखानेदारों को बिजली मिल रही है। इस बारे में मै यह भी कहना चाहूंगा कि जो

हरियाणा के न्दर कारखाने लगे तो हरियाणा में, हरियाणा में ही धुआं ओर प्रदूशण फैलाये ओर इनमें काम करने वाले हड़ताल भी हरियाणा में ही करें लेकिन जो लोग लगाये जाये वे हरियाणा से बाहर के लगाये जाये, यहा कहा की उचित बात है? मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जितने भी हरियाणा में कारखाने लगे, उन सभी में हरियाणा के लोगों को ही रोजगार मिलना चाहिए। जो भी कर्मचारी लगाये जाए, उनसे हरियाणा का डोमीसाइल लिय जाए। हरियाणा क लोग बड़े बहादुर हाते है। यदि उनको हयां पर रोजगार उन कारखानों मे ंमिलेगातो दे ा ओर प्रदे ा खु ाहाल होगा। इन भाब्दों के साथ मै आपका धन्यवाद रकत हुए इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मै आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुण्े इस गैर–सरकारी संकल्प पर बोलने का समय दियाहैं इस के साथ ही अपने एक घनि ट मित्र श्री रणजीत सिंह का भी धन्यवाद करता कि जिन्होने 24, मार्च 1988 को एक गैर सरकारी संकल्प हरियाणा की असैम्बली में प्रस्तुत किया। उन्होने यह बहुत ही अच्छा संकल्प प्रस्तु किया था लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब वे इस सदन के सदस्य नही हैं उन्होने उस समय बोले हुए बहुत ही मूल्यावान सुझाव दिए थे। सन 1982 में 46वे सं ाोधन के जारिए इस कंसाइनमैंट टैक्स को लगाने की बात आई थीं जब यह गैर सरकार संकल्प यहां पर अया तोउस समय पहले ही 6 साल निकल

चुके थे। उसे बाद भी तीन साल और निकल गए है। यादिन कहां तो 1982 में ही लागू हो जाना चाहिए था और कहा अब 1991 आ गण। इतने सालों के बाद भी अब तक यह रैजोल्यू ान यहां से पास करके नही भेजा गया। इस पुनीत कार्य में यदि एक जैसी राय हो तो फिर यह मेरी समझ में नही आता कि इसे क्या लटकाया जा रहा है? इसलिए मेरी सभी सदस्यों से यही रायह ै कि इसे जितना जल्दी हो सकते पास करा दिया जाए। यह जितनी जल्दी पास होगा उतना ही राज्य के लिए अच्छा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इय बारें में मै पूर्व उपाध्यक्ष की भी प्र ांसा किए बगैरनही रह सकता जिन्होने अपनी बात खत्म करते हुए एक बहुी ही अच्छी बात कही यहां लगने वाले कारखानों में हरियाणा के लोगों की ही रोजगार मिलना चाहिए। जब कारखने यहां पर लगते है, बिजली यहां से मिलती है तेा लोगों को रोजगार क्यों नही मिले? इन कारखानों का प्रदूशण ता हरियाणा मैं हाों ओर रोजगार बाहर के प्रांतों के लोगों को दिया जाए, यह अच्छी बात नही है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस बारे ंमें ध्यान दे। सरकार को यही के लोगों को राजगार दिलाये जाने का प्रबंध करना चाहिए। जब इस बारे में सभी विपक्ष के साथी और दूसरे साथियों की एक राय हो तो फिर इसको अधिक देर तक ल लटाया जाए। इस बारे में मैं मै बसत की स्थिति स्पश्ट रकते हुए बताना चाहूंगा कि जब 28 मार्च, 1984 को सभी मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में, सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित कया गया हो और दूसरी सभी पाटियों की एक राय हो तो फिर इसे लागू क्यों नही किया जाता? इतना ही नही,

योजना आयोग जो सारे दे ा की आर्थिक व्यवस्था का देखता है, उसकी भी यही राजय है। इसी प्रकार से क्षेत्रीय कौसिल ओर नै ानल डिवैल्पमैंट कौसिल ने भी इसका समर्थन किया हैं इतना ही नही, गत वर्शो में संसद में भी यह मसला बार बार उठाया गया और जितने भी मुख्य मंत्री यहां पर रहे है, चाहे वे किसी भी पार्टी के रहे हो, उन्होने इस मसले को बार बार उठाया है। लेकिन फिर भी संविधान में स ाोधन नही किया गया हैं उपाध्यक्ष महोदय, कानून प्रक्रिया को देखते हुए आप स्वयं भी यह महसूस करेगे कि इस मामले में राज्य सरकारे असमर्थ है। जब तक केन्दीय सरकार इस बिल को पास नही कर देती, तब तक राज्य सरकारे इसेलागू करने में असमर्थ है और जो इस बिल को ध्येय है, वह पूरा नही हेागा। उपध्यक्ष महोदय, मै एक और बात कहनाचाहूंगा कि इस बिल का हरियाणा के लिए अन्य प्रदे ाों की अपेक्षा अधिक महत्व हैं उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि पूर्व वक्ता श्री भार्मा जी ने कहा है कि दिल्ली के आस–पास हरियाणा बसता है। हरियाणा प्रदे ा दिल्ली को 3 सईडों से घेरे हुए है तथा अधिकातर उद्योग दिल्ली के आस–पास के क्षेत्रों में लगे हुए है। इसलिए कन्साईनमैंट टैक्स का हरियाणा के लिए बहुत अधिक महत्व हैं उपाध्यक्ष महोदय, अन्य प्रदे ाों के मुकाबे इस टैक्स से हरियाणा को ज्यादा लाभ होगा। जितने उद्योग गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ आदि मे लगे हुए है, ये सभी क्षेत्र दिल्ली से 10–15 किलोमीटर की दूरी पर है इसलिए वहां पर जो उत्पादन होताहै, वह बड़े आराम से दिल्ली पहुंच जाता है। ओर हरियाणा को नुक्सान होता है। राज्य को इस

नुक्सान से बचाने के लिए यह जरूरी है। कि कन्साईनमैंट टैक्स लगाने पर गहराई से विचार किया जाए। इण्डस्ट्रीज में जेा उत्पादन होताहै, उस पर सेल्ज टैक्स वगैरा तो लगता ही है। यह टैक्स भी निि चत रूप से सेल्ज टैक्स की ही अमैडमैंट हैं जिस में राज्यों में हुएउत्पादन पर कन्साईनमैंट टैक्स लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक बौर की जाने वाली बात यह भी है कि व्यापारियों और उद्योगपतियों में सांठ–गांठ तो नही है। यह विधेयक इतने लम्बे समय से पैडिग पड़ा है, कही इसका कारण यह तो नही कि जिन लेागो ंके आर्थिक हित इससे जुडे हुए है, वे अपने लाभ के लिए इसका पास नही होने दे रहे ओर इसके पास होने में अड़चने डाल रहे है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों के बार–बार अनुरोध करने पर भी इस बिल को पास नही किया जा रहा है क्योंकि जिनके आर्थिक हित इससे जुड़े है, उनकी पहुंत बहुत ही ऊंची है, उन का करोड़ों अरबों का उत्पादन औद्योगिक क्षेत्र में होता है। हरियाणा में लगे उद्योगों में उद्योगपति उत्पादन तो करते है लेकिन उसे बचेने के लिए दिल्ली भेज देते हैं उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ जुडा हुआ एक और प्वायंअ भी है। हरियाण के मुकाबले मे ंदूसरे राज्यों में सेल्ज टैक्स की दरें निि चत रूप से कम है, इसलिए उद्योगतियों को हरियाणा से बाहर माल बेचने परदोहरा और तिहारा लाभ होता है। वह विधेयक ओर संकल्प परबोलते हुए अपने क्षेत्र की कुद इररैलेवैन्ट डिमाण्डज भी रखी हैं और क्रिटिसिज्म भी किया है लकिन मै इस मामले मे नही जाना चाहूंगा। आदरणीय चौधरी देवी लाल जी जब फरीदाबाद ओर

गुडगांवा जिलों में चुनाव सभाओं को संबोधित कर रहे थे, तो कन्साईमैंट टैक्स की बात कई बार उठाई। चौधरी देवी ला जी ने नूंह में एक जनसभा मेंकहा था–मेवात के लोगों, दक्षिणी हरियाणा के लोगों में आपको वि वास दिलाता हूं कि केन्द्र सरकार में कन्साईनमैंट टैक्स पास होने से हरियाणा को जो आया होगी,उससे हम मेवात नहर निकालेगे। मै चाहूंगा कि चौधरी देवी ला के उस वायदे का पूरा कया जाने के बारें मे ंभी विचार किया जाए। इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि इसके पास होने से प्रदे ा को 50 करोड़ रूपए की आमदन ीोगी। इस बिल के पास न होने से इस प्रदे ज्ञ का 50 करोड़ रूपए की हानि ही नही हो रही है बल्कि यदि आज की कीमतों के मुताबिक इसको देखा जाए तो हरियाणा प्रदे ा को 100 करोड़ से ले कर 200 करोड़ रूपए की हानि हर वर्श हो रही हैं हरियाणा प्रदे ा का टोटल बजट करीब 766 करोड़ का है।, यदि 100या 200 करोड़ रूपए इसमें कन्साईनमैंट टैक्स के और जोड़ किद जाए तो इससे प्रदे ा का आर्थिक विकास करने के लिए एक ओर सुनहार अवसर प्रदे ा को प्रापत होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मै इसे लिए आपका धन्यवाद करता हूं तथा इस रैजोल्यू ान का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सुशमा स्वराज, राज्य सभा सदस्या, का स्वागत

श्री वीरेन्द्र सिहः उपाध्यक्ष महोदय, मै आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हू कि इस सदन में स्पीकर्ज गैलरी में हामरी

इसी विधान सभा की पूर्व सदस्या श्रीमती सुशमा स्वराज विराजमान हैं हम विपक्ष की तरफ से उनका स्वागत करते है। (तालिया)

गृहमंत्री (प्रो सम्पत सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, हम सारे हाउस की तरफ से ही उनका स्वागत करते है। (तालियां)

श्री राम बिलास भार्मा: उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आदरणीय बहिन जी, हमारे दल की नेता है इलिए मै कहूंगा कि यह अच्छा ही हुआ जो सम्पत सिंह जी ने भी चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया है उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक हैं कि वे दिल्ली को सरकार तुड़वाकर आयी है और अब इस सकरार की बारी है। (विध्न) परन्तु में ज्यान न हते हुए अपनी पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं (तालियां)

श्री उपाध्यक्ष: सारे हाउस की तरफ से ही हम बहिन जी का स्वागत करते है।

गैर सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

श्री राम बिलास भार्मा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अधिवे ान चल रहा हैं पहले इसमें दो दिन तक नौन–औफि ायल बिजनैस यानी प्राईवेजट मैम्बर्ज बिल डिस्क ान होने थे लेकिनउसेा इन्होने काट कर एक दिन को कर दिय। अब इस प्रस्ताव पर उसतरफ से हमारे जो साथी बोल रहे है, उससे ऐसा लगता है। कि वे भी इसकासमर्थन करते है। लेकिन इसको पास करने में इनको कठिनाई क्या है? मंत्री महोदय

भी इसमें इस तरह से हिस्सा लेना चाहत रहे है जैसे उन्होने डिबेट का जवाब देना हो। अगर तो ये इस प्रस्ताव का विरोध करते है, तब तो दूसरी बात है, लेकिन अगर नही ता मै इससे यह दरख्वास्त करूंगा कि वह हरियाणा के हितो ंका एक मुद्दा है। यह कोई चुनावी मुद्दा नही है। इसलिए इस पर ज्यादा समय न लिया जाऐ और इसे पास कर दिया जाए।

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, अभी माननीय सदस्य श्री राम बिलास भार्मा यह कह रहे थे कि हमने नौन–औफि ाियल डे का पीरियड दो दिन की बजाए एक दिन कर दिया। मै इनको यह बतानाचाहता हू कि हमने ऐसा नही कियां जिस ढंग से इन्हाने एक दिन खराब किया, यह सब जानते है। उसके बाद बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिग में खुद इनके नेता चौधरी सूरज भान भी मौजूद थे। उस मीटिग में गवनमैट की तरफ से यह प्रस्ताव आया था कि पहला नान–आफी ीियले–डे अब नही हो सकता इसलि दूसरे नान–आफो ीियल डे को हम डबल सिटिग कर लेते है। गवर्नमैंट की तरफ से बाकायदा यह प्रस्ताव था औरहम इसके लिए तैयार थे, लेकिन इनके नेता इसके लिए नही माने। (विध्न) आप अपने लीडर से तो बतियाते नही हो। इन्होने खुद हमारे उस प्रस्ताव को नही माना। (व्यवधान व भाोर)

विकास मंत्री (श्री सुभाश कटियाल): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो कंसाईनमैंट टैक्स के लिए नान–आफ ीियल रैजोल्यू ान अया हुआ है, मै इसका समर्थन करने के लिए खड़ा

हुआ हूं। 1982 के अन्दर संविधान सं ाोधन ुआ था। इस संदर्भ में उद्योग में होनेवलो उतपदनो ंककी इस पकार से व्यवस्था की जाए जिससे एक राज्य ओर दूसरे राज्य के अन्दर कर का ढांचा युक्तिसंगत होगा। ऐसी मं ाा थीं हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने बार–बार प्रधान मंत्री महोदय से यहा कहा कि इस बारें मं कार्यवाही की जाए। बार–बार यह दोहराया है लेकिन अभी तक यह जांग मानी जा सकी हैं हरियाणा के लिए इस टैक्स कालगना बहुत ही जरूरी हैं कन्साइर्नमैंट टैक्स न लगाने की वजह से बहुत ही जरूरी हैं क्नसाईनमैंट टैक्स ने लगने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि फैक्ट्रीज तो हमारे हरियाणा में है, लेकिन टैक्स दिल्ली का जाता है। आपका पता है कि हरियाणा दिल्ली के तीनों तरफ लगता है। सारी फैक्ट्रीज तो हरियाणा मं काम कर रही है, प्रोड्यूस हरियणा में हो रही है, लेकिन फिरउस माल को दिल्ली ले जाकर वितरण किया जाता है। इससेस्टेट के के एक्सचैकरको जो नुकसान हो रहा है, अगर वह आमदनी हरियाणा सरकारे आये तो उससे कितने ही काम हो सकते है। हरियाणा प्रदे ा की सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, पूर तरह से जागरूक है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए। इसके लिए कितनी ही कल्याणकारी योजनाएं बनाकार लागू की गयी हैं चाहे बूढ़ों को पै ान देने की बात हो, चाहत वह कर्जा माफी की बात हो, चाहे सड़कों की रिपेयर की बात हो नई सड़के बनाने की बात हो, चाहे रूरल डिवैल्पमैट के लिए गावों की गलियों को पक्का करने की बात हो, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि

ग्रामीण विकास के लिए, अर्बन डिवैल्पमैंट के लिए और भाहरों के सौन्र्यकरण के लिए हमारी सरकार पूर तरह संकल्पित हैं उपाध्यक्ष महोदय, इसे अलावा, हमारी सरकार ने कोि ा ा की है कि हर परिवार में से कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिया जाए। यह बहुत ही अच्छी स्कीम हैं टैक्स की वजह से जिन इंडस्ट्रीयलिस्टस के हैड औफिसिज दिल्ली में है, जब वे सारे हरियाणा मे ंआएगे तो हरियणा की इंकम बढ़ेगी। हरियाणा सरकार अब भी अपने सीमित साधनों से रोजगार दिलाने की और डिवैल्पमैंट के काम करने का पूरा प्रयत्न कर रही है। जब हरियाणा सरकार का पचास करोड़ रूपया और मिलेगा तो वह और भी ज्यादा तरक्की के काम कर सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जित तरह से इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, मै समझता हूं यह रा ि ा सौ करोड़ और दो सौ करोड़ रूपए से भी ज्यादा हो जाएगी और तब हरियाणा में बहुित अधिक खु ाहाली आएगी। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सेल्ज टैक्स की बात कही गई। हरियाणा सरकार की यक कोि ा ा है कि किसी भी व्यापारी को कोई कश्ट न हो। बहुत सारीचीजे जैसे बर्तन, स्टील औरचले आदि परसेल्ज टैक्स कम किया गया हैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निराधाराबात है कि उद्योगपति यहो से भाग रहे है ओर वे इसलिए बाहर जा रहे है कि हरियाणा में टैक्स ज्यादा है। यह बात ठीक नही हैं हरियाणा सरकार की कोि ा ज्ञ है कि हर आदमी चाहे, वह भाहर में रहताहै या गांव मे ंरहता है, सरकार उसकी तरफ ध्यान दे। उद्योगपतियों का पूरी बिजली दे ओर उनका पूरा पानी दे। इस सरकार का सब के प्रति हैलपिग

ऐटीच्यूड है। उपाध्यक्ष महोदय, मै यह भ कहना चाहता हूं कि यह सदन केन्द्रीय सरकार से सिफारि ा करे कि केन्द्रीय सरकार कंसाइमैंट टैक्स लगाने की जल्दी से जल्दी अनुमति दे ताकि हरियाणा सरकार का अपनी जतना का जीवर स्तर ऊंचा उठाने और लोगों को सुविधा पहुचाने का जो संकल्प है। वह पूराहो सके। अन्त में मै आपका धन्यवाद करत हूं।

श्रीमती कमला भार्मा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय कह रहे थे कि बिजली इंडस्ट्रीज को दी जा रह ीहैं मै उनकी जानकारी के लिए कहना चाहती हूं कि यमुनानगर में पूर इंडट्रियल कीम्पलैक्स में तीन दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को बिजली बन्द रहती है ये गल्त बात न कहे। यहां पर सच्चाई आनी चाहिए।

श्री राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव सदन में 24 मार्च, 1988 को रखा गया था। जिस माननीय साथी ने यह प्रस्ताव रखा था, वे संयोग से आज इस सदन में नही है वे दिल्ली में है। लेकिन उस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही हैं उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इस पर काफी चर्चा कर चुके हैं हरियाणा के हितों के साथ यह प्रस्ताव जुडा हुआ हैं अगर दिल्ली की सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो हरियाणा जैसे छोट प्रातं में, जहां मेहनत करने वाले आदमी रहते है जाहे पांच एकड़, सात एकड़ और दस एकड़ का छोटा किसान रहता हैं, जो धरती मां कापेट चीरकर सारे दे ज्ञ को अनाज

देताहै,वह भी आ ा करता है कि उसके यहां रास्ते पक्के हो, गलिया साफाहो, उसे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हो ओर उनको पढ़ने लिखने की अचछी सुविधा मिले और अगर उसे घर मे ंाकेइ बीमार हो तो वह किसी अच्छे अस्पताल के न होने के कारया मर न जाए, उसका इलाज कही नजदीक हो जाए। यह हरियाणा का किसान औ रहरियाणा का आम ादमी आ ाा करता हैं उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव से दो सौ करोड़ रूपए का जो लाभ होने वाला था, उसको दिल्ली में बैठने वाले हुक्मरानी ने नही होने दिया। अगर वे 1982 मे ंही एक्ट में स ाोधन कर दते तो सौभाग्य से हरियाणा को दो सौ करोड़ का लाभ हो जाता। यह प्रस्ताव इस सदन मेंं पिछले दो साल से है ओर सभी भाई हरियाणा के भुभ चिन्तक हे।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार में जो बैठै है, वे ज्यादा भुभ चिन्तक है। परन्तु भुभ चिन्तक होने का प्रमाण यह है कि दोनो जगहों पर इनकी अपन ीसरकारहैं इने घर का राज ळै बाबू बेटों काराज ळै लकिन फिर भी ये अपने प्रस्ताव का पास न करवा सके और न ही कभी दिल्ली में ही इसब ारें में चर्चा हुई है, परन्तु इस सदन में जब हय इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव आया ह जिससे हरियाणा के हित जुड़े हुए है, उस और इन भाईयों का कोई ध्यान ही नही जा रहा हैं पहले ये लोग गांवों में लोगों को सामने जाकर उपदे ा देते है ओर उन से यह मांग करते है कि हमें कुर्सी दे दीीं हरियणा की कुर्सी छोटी है, हमे दिल्ली की कुर्सी दे दो। फिर

हमारी चाल देखना। (ाोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मे हरियाणा हितों को बात कर रहा हूं। इन द्वारा रखे गए प्रस्ताव को ही बात कर हा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, विधिवत् तौर पर चौपालों में यह बात कही गयी थी कि नोट छापने वाल म ाीन हमारे पास आ जाएतो देखना उनका मुह हम हरियाणा की ओर कर देगे लेकिन हुआ क्या? बैसी, मदीना व मेहम के अन्दर नोटों की म ाीनों को जगह लोगो ंपर बड़ी बेरहमी के साथ गोलिया बरसाई गई। (ोम भोम की आवाजे) (ाोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष महोदयः भार्मा साहब, आप सेल्ज टैक्स की बात कहे। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास भार्माः उपाध्यक्ष महोदय, मै तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि–

रात का न जिकर कर, रात तो गुजर गई

है दिन अब रो ान किधर गई? (ाोर एवं व्यवधान)

आवाजेः 80 और 84 के चुनावों में क्या हुआ था? (ाोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास भार्माः उपाध्यक्ष महोदय, 1980 व 1984 के पालियामैंट के इलैक ान में मै भी कैन्डीडेट थ। मै इनका बताना ाहता हूं कि इन इलैक ानों में इनके दोनों कैन्डीडेट्स की जमानते जब्त करवाई गयी थी। (ाोर) लेकिन मै यह बता देता हूं

कि आने वाले इलैक ान में इनको पता लग ही जाएगा। यह तो नाई के बालों वाली बात है, उपाध्यक्ष महोदय, मै बताना चाहा हूं कि इनका हरियाणा क हितों को पहल देनी चाहिए थी लेकिन इन्हौन हरियाणा क हितों को ताक पर रख दिया और इस कन्साईनमैंट टैक्स वाले बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर कोई ध्यान नही दिया, जिसके कारण आज हरियाण की आर्थिक स्थिति काफी पिछड़ गई है उपाध्यक्ष महोदय, 1966 में हम पंजाब से अलग हुए थे। हमारे साथ जब पंजाब राज्य अलग हुआ तो उस समय भ पंजाब की आर्थिक हालत ठीक नही थी, परन्तु फिर भी आज आप देखिए पांजब प्रगति पर हैं हालांकि काफ देर से वहां पर राज्यपाल का भाासन ही चल रह है, लेकिन फिर भी पंजाब की जनतापंजाब के नेतागण अपने राजय की बहबूदी के लिए सदा ही सजग रहे है, जागरूक नहे हैं लेकिन हमारे पास सारे साधन होते हुए भी, हमार `पास कुछ नही हैं हमारी आर्थिक नीति बुरी तरह से उथल–पुथल हुई पड़ी है। हरियाणा में इनका राज है, दिल्ली में भी इनका राज है, इतना होते हुए भी उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग इस कन्साईनमैंट टैक्स वाले बिल को पास नही करवा पाए। हरियाण की जनता बड़ी मेहनती है, जागरूक है, भारीफ है, यहां के लोग बहुत ही भले है। लेकिन यह सरकार यूं ही वायदे करके इस भोलीभाली जनता को गुमराह कर रही है। गरीब लोगों केसथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही हैं उपाध्यक्ष महोदय, हमारी हरियाणा की धरती बड़ी पवित्र है लेकिन इन्होने अब अपने राज्य के कारण इस धरती को बदनाम रि दिया हैं इनके कुकर्मो के कारण आज यह धरती अपवित्र हो गई

हैं पांडवों ने भी धर्म युद्ध के लिए इस हरियाणा की पवित्र धरती कुरूक्षेत्र को चुना था। उन्होने भी यह कहा था कि यहां के लोग वे लोग है जोकि पुण्य के काम करने वाले है।

उपाध्यक्ष महोदय, भाायद से सरकार इसी हरियाणा की भोलीभाली जनता से पूरी तरह से परिचित नही है। भाायद इस सरकार को यह गल्तफहमी हो है कि हम लाठी गोली से लोगों की आवाज को दबा देगे। लेकिन इनकी यह भूल है कि इस हरियाणा की भोलीभाली जनता इनके दवाब के नी आ जाएगी। इसलिए मेरी इस सरकार से प्रार्थना है कि हरियाणा की जनता को गुमराह न किया जाए। ओर इस कन्साईनमैंट टैक्स जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को हरियाणा की बहबूदी लाभ हरियाणा को हो सके। इस महत्वपूर्ण विशय को ज्यादा देरतक लटकाना कोई अकलमन्दी की बात नही है। जब कुछ अपने हाथ में था तब इस प्रस्ताव को मंजूर करवा लेते तो उससे हरियाण के गरीब आदमियों का फायदा होता। (विध्न) मै निवेदन कर रहा था कि अच्छा होता कि ये अपने समय में इस प्रस्ताव पर दिल्ली में कुछ कारगुजारी करके दिखाते परन्तु ये ऐसा नही कर सके। परन्तु आज यह सदन इसको पास कर दे ताकि हमने केन्द्र की सरकार से जो इस टैक्स का मांगा की है, वह मनवाई जा सके और हरियाणा के लोगों के सिर से यह बोझा हट सके। धन्यवाद।

श्री आत्मा राम गोदारा (धिराय): उपाध्यक्ष महोदय, मै आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

एक नौन–औफि ियल रैजोन्यू ान हमारे पूर्व एम0 एल0 ए0 साथी श्री रणजीत सिंह, जो अब राज्य सभा के मैम्बर है, ने पे ा किया था। यह रैजोल्यू ान एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर है है जेा मै समझता हूं कि हरियाणा की जीवन रेखा से संबंधित है और बड़ा जरूरी है। इसलिए पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि जिस मुद्दे पर हम वास्तविक रूप में चर्चा कर रहे है,यह कन्साईनमैंट टैक्स क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, हर प्रांत में फैक्ट्रीज लगती है ओर माल पैदा करती हैं यह फैक्टरी उस प्रांत से हर सेवाएं हासिल करती है लेकिन उस बने हुए माल पर टैक्स लगता है, वह कही औरचला जाता हैं कन्साईनमैंट टैक्स का मामला यही है कि जो प्रोडक ान पर टैक्स लगता है, वह उसी राज्य को मिले जिस राज्य में माल बनता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए भारत के संविधान में सं ाोधन किया गया था ओर उस द्वारा सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स ऐक्ट के अन्दर अमैंडमैंट करके यह अधिकार लिया था कि हम कन्साईनमैंट टैक्स लागू कर दे और जिस राजय में प्रोडक ान होती है तथा उस परजो टैक्स लगताहै, उसका फायदा उसी राज्य को के लोगों को हो।

उपाध्यक्ष महोदय, अब देखने की बात यह है कि ये सारी चीजे हासिल होने के बाद, सारे अधिकार लेने के बाद, 1982 से लेकर आज तक कन्साईनमैंट टैक्स से जो फायदा होना चाहिए था, वह नही हो पाया है। इस बारे में लगातार यह प्रयास किए गए है कि किसी प्राकर से यह कन्साईनमैंट अैक्स को लागू करने

मामला ठीक हो ताकि हरियाणा को उसका लाभ मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसबात के लिए भिन्न भिन्न स्तर परप्रयास किए गए। न्दिुस्तान के सभी प्रदे ाों के मुख्य मंत्रियों ने इस बात का समर्थन भी किया था कि कन्साईनमैंट टैक्स लागू किया जाए उसे बावजूद भी आज तक वहा लागू नही हुआ है। जो सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स एक्ट है, उसमें भी अमैडमैंट की जानी थी, वह भी अब तक नही हुई हैं देखना यह ह कि इस टैक्स के न मिलने से हमारी स्टेट को कितना नुक्सान हुआ हैं मेरे साथियों ने मोटे तौर पर बताया कि लगभग 200 करोड़ रूपए साल को नुक्सान हो रहा है। यदियह कन्साईनमैंट टैक्स लागू कर दिया जाए तो उससे होने वाली आमदनी से हरियाणा में हर प्रकार की डिवैल्पमैंट होगी, बेरोजगारी को रोजगार के साधन मिलेगे, कृशकों को सहूलियते मिलेगी और कर्मचारी जो अपनी मांगों केा मनवाने के लिए ऐजीटे ान करते है, उनकेा भी राहत मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, कन्साईनमैंट टैक्स का लागू करने से केवल हरियाणा प्रदे ा को ही उसका फायदा नही होगा बल्कि हिन्दुस्तान केसभ सूबों को उसको फायदा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, विशे ज्ञरूप स हरियाणा की स्थिति ऐसी है दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा लगता हे, इसलिए हरियाणा के अन्दर जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हे, उनके हैड औफिस दिल्ली में बना करके इंडस्ट्रीयलिस्टस एक ऐसा तरीक अपनाए हुए है जिससे हरियाणा स्टेट को टैक्स का बहुत ज्यादा नुक्सान हो रहा हैं वह अपना हैड औफिस दिल्ली में बना कर बैठे हुए हैं अपनी प्रोडक ान से हरियाणा केा जो लाभ

मिलाना चाहिए था वह लाभ नही दिया जा रहा है। इसलि कंसाइनमैंट टैक्स लागू नह होने से हरियाणा प्रदे ज्ञ को बहत ज्यादा नुक्सान हैं उपाध्यक्ष महोदय, मै यह निवेदन करूंगाकि यह बहुत ही जरूरी रैजोल्यू ान है। इस को पास करके केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जाए और कन्साईनमैंट टैक्स को लागू करने के लिए जितने प्रासा किये जा सकते हैं वह किए जाए। इन्ही भाबदों के साथ मै इसका समर्थन करते हुए आपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उदय भान (हसनपुर–अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, 24 मार्च 1988 को इस सदन के एक बहुत समानित सदस्य चौधरी रणजीत सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा था जो कन्साईनमैंट टैक्स से संबंधित था। मै उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय,कंसाइनमैंट अैक्स को लागू किय जाना हमारे प्रदे ा की जानता कक लिए बहुत ही जरूरी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कन्साईनमैंट टैक्स लागू न होने के कारण हरिाणा प्रदे ा को 50 करोड़ रूपए की हानि हो रही हैं मै अपने हिसाब से कहूंगा कि 50 करोड़ नही बल्कि 100 करोड़ रूपए का आर्थिक नुक्सान हरियाणा प्रदे ा की जानता को उठाना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1984 मं 46वे संविधान के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को यह अध्किार दियागयाथा कि वह सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स में अमैडमैंट करके एक नया एक्ट बनाये, जिससे राज्यों को कन्साईनमैंट टैक्स का लाभ मिल सके। भाुरू में यह

मामला 1982 में उठाया गया था। इसको आज 9 साल हो गए है लेकिन अभी तक केन्द्रीय सरकार ने सेल्ज टैक्स में सं ाोधन नही किया है। 1984 में तमाम मुख्य मन्त्रियों की इस बारे में एक कांफ्रेस भी हुई थी, जिसमें प्रधान मंत्री भी थे ओर यनियन टैरेटरी के नुमाइन्दे भी थे। इतना ही नही, ने ालन डिवैल्पमैंट कौसलि और रीजनल कौसिल ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था लेकिन आज तक सेन्ट्रल सेल्ज अैक्स मं अमैडमैंट नही की गई है। हरियाणा प्रदे ा दिल्ली के तीन तरफ लगताहैं दिल्ली के आसपास फरीदाबाद, गुडगांवा, रोहतक, बहादुरगढ़ और सोनीपत जैसे भाहर, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी है, बसे हुए है। इसी प्रकार से चण्डीगढ़ के आसपास जगाधारी, यमुनानगर और अम्बाला में कई बड़े–बडे कारखाने लगे हुए है। इन कारखानेदारों के आफिसिज या तो दिल्ली में है या चण्डीगढ में है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, ये कारखाने हरियाणा में लगे हुए है। यही से इनकी पानी, बिजली ओर दूसरी सुविधाए दी जा रही है। ये सुविधा तो यहां से प्राप्त कर रहे है लेकिन रोजगार बाहर के राज्य के लोागें को दे रहे है। इनकारखानों से हरियाणा को देने की बजाये केन्द्र को दे रहे है जबकि सारी सहूलियतें इन्हें हरियाणा का `देने की बजाये केन्द्र को दे रहे है। जबकि सारी सहूलियतें इन्हें हरियाणा प्रदे ा प्रदान करता हैं अगर यह टैक्स, जो सेन्टर ले जाती है, हमें पूरी तरह से मिल जाए तो हमारे हरियाणा प्रदे ा की आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुधर सकती हैं अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो उससे सड़कों की

द ाा ठीक होगी और सीवरेज व स्वास्थ्य की तरफ भी सरकार ध्यान देत हुए अच्छा काम करेगी। यदि कन्साइनमैंट टैक्स लगाने का अधिकार हमें मिल जाता है तो हमें अपने बजट में 100 करोड़ रूपये विकास के कार्यो के लिए और मिल सकते है। मै फिर कहता हूं कि इन कारखानों में जो रोजगार दिया जाता है, उस में हरियाणा क लोगों के साथ भेद भाव बरता जा रहा हैं इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहो पर जो भी लोग लगे, उनके लिए हरियाणा कडोमिसाइल सटिफिकेट होना जरूरी किया जाना चाहिए। अगर सरकार ऐसा कर देती है तो सरकार की जो एक परिवार को एक नौकरी देने की स्कीम है,वह भी पूरी हो जाएगी ओर एम्पलाइमेंट एक्सचेजिज में जितने बच्चो के नाम दर्ज है, उन सभी को नौकरी मिल जाएगी इस बारे में मेरा सरकारको सुझाव है कि इस कंसाइनमैंट टैक्स को लेने के लिए केन्द्रीय सरकार पर अधिक से अधिक दबाव डाला जाए ताकि इस कंसाइनमैंट टैक्स से हरियाणा को जो आर्थिक नुक्सान हो रहा है, वह न हो। इसके अतिरिक्त मै अपनी सरकार पर अधिक से अधिक दबाव डाला जाये ताकि इस कंसाइनमैंट टैक्स से हरियाणा को जो आर्थिक नुक्सान हो रहा है। वह न हो। इसे अतिरिक्त मै अपनी सरार की प्र ांसा किए बगैर नही रह सकता क्योकि हमारीसरकार ने कर नीति को पहले ही काफी सरल बना दिया है। हमारी सरकार ने तकरीबन 74 आईटम्ज परसेल्ज टैक्स कम किया है। इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि कर नीति को और सरल बनाया जाये। इस के साथ ही साथ यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो इन कारखानों के

आफिस दिल्ली और चण्डीगढ़ में हैं उनकों हरियाणा में ि ाफ्ट करने ककको कहा जाये ताकि कन्साईनमेंट टैक्स लगाने का दबाव केन्द्रीय सरकार पर अच्छी तरह से बिना सकै। इन भाब्दों के साथ मैं इस गौर सरकारी संकल्प का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री दुर्गा दत्त अत्री (राजौद): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। इस रैजोल्यू ान पर बहुत लम्बे समय से चर्चा चली आ रही हैं। इस महान सदन के लगभग तमात साथियों ने इस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं जिस वक्त हमारे माननीय भूतपूर्व एम0एल0एल0 चौधरी रणजीत सिंह जी ने यह प्रस्ताव रखाथ उस वक्त य अनुमान लगायाथा कि 50 करोड़ रूपये का घाटा यह कर न आने के कारण हरियाणा को प्रतिवर्श हो रहा हैं इस प्रस्ताव को आए हुए करीब अढ़ाई–तीन वर्श का समय बीता गया है। मै समझता हूं कि इस समय 200 करोड़ रूपये का घाटा हरियाणा प्रदे ा का रहा है। इस समय में कीमतें बढ़ी है और प्रोडक ान भी बढ़ा है, अगर इस लिहाज से इस टैक्स को लगाया जाता तो प्रदे ा में खु ाहाली होती। मौजूदा सरकार की पोलिसी है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, इसका आम जनता से प्रचार भी है। यदि यह टैक्स लग जाए तो बहुत ही लाभदायक हो सकता हैं स्पीकर ाहब, यह नीति बड़ी ही बढ़िया और सरहाहनीय है। जब यह प्रस्ताव इस महान सदन मे ंअया था,

उस वक्त मौजूदा सरकार केन्द्र में अपना हाथ नही रखती थी। यह 46वां संविधान सं ाोधन था जिस में कन्साईनमैंट टैक्स के लिए विधान सभा द्वारा प्रस्ताव पास करे सिफारि ा करनी थी कि कन्साईनमैंट टैक्स लगाने के लिए राज्यों को अधिकार मिले। पिछले करीब 14 महीने से इस पार्टी की सरकार रही और इकसे समर्थक साथियों की सरकार रही, इस समय में भी यह बिल टस से मस नही हुआ। मै समझता हूं कि जो लोग उस वक्त तक सत्ता में थे, उन्होने इसकी जिम्मेदारी को ठीक तरह से न समझते हुए गम्भीरता से नही लिया क्योंकि सत्ता में आने के बाद हमारे राजनेता मूल समस्यओं को भूल जाता है। और सिर्फ कुर्सी की बात ही रह जाती है राजनेता छोटी कुसी से बड़ी कुर्सी प्राप्त करने के प्रयासें में लगे रहते है। स्पीकर साहब, मै इस रैजो ल्यू ान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं मै समझता कि यह महानसदनतो इसकी फिारि ा करेगा ही, लेकिन जो लोग केयर टेकर सरकारचला रहे है, उन्हें इसेबड़ी गम्भीरता से लेना चाहिए। स्पीकर साहब, हम मानते है किकेन्द्र में हमारीवर्तमान सरकार इसेा पास नही कर सकती लेकिन जिस तरह के दाव किये जा रहे है, जिन लोगों के हाथ मं सत्ता आएगी, अगर उसमें हरियाणा के लोग भीा सांझीदार हो तेा वे इस बात का भूले नही। आने वाले समय में इसको जरूर पास किया जाना चाहिए। तमाम पाटियां इस रैजोल्यू ान का समर्थन कर रही है क्योंकि हरियाणा के हित की बात इससे जुड़ी हुई हैं अध्यक्ष महोदय, बड़ा अच्छा प्रस्ताव हमारे साथी चौधरी रणजीत सिंह लाए थे औरसभी ने

इसका समर्थन किय ाहैं मै भी अपनी तरफ से इसका समर्थन करता हूं तथा यह अनुरोध करता हूं कि इसको आपके माध्यम से एक ओर बात सरकार के नोटिस में लाना चाहूंगा। हमारे तीन सम्मानित साथियों श्री उदय भान, श्री रिसाल सिंह तथा श्री मनी राम जी ने बहुत ही अच्छे तीन नो–औफि ियल प्रस्ताव रखे है। मै यह निवेदन करूंगा कि इस रैजोल्यू ान परऔर ज्यादा डिस्क ान न करके जो अन्य नौ–औफि ियल प्रस्ताव थे उन पर चर्चा की जाए। कन्साईनमैंट रैजोरूयू ान पर काफी चर्चा हो चकी है ओर इस पर और ज्यादार चर्चा करना समय की बर्बाद करना है, जिस कारण और बहुत से जरूरी काम रहे जाएंगे। इस रैजोल्यू ान को तो हम पहले तो हम पहले भी पास कर चुके है। और अब भी पास करने की सिफारि ा करते है। मै यह भी कहना चाहता हूं कि उन 3 प्रस्तावों को भी इसे साथ जोड़ा जाए। पर्ची से या लाटरी से, जो भी सिस्टम बनता हो, उन प्रस्तावों को भी भाामिल कर लिया जाए। वे मसले भी बहुत जरूरी है। इसलिए उन पर चर्च होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसक लिए मै आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान करता हूं।

चुनाव राज्य मंत्री (इं0 जगपात सिंह चौधरी): स्पीकर सर, चौधरी रणजीत सिंह, जो पहले इस महान सदन के सदस्य थे और अब एम0 पी0 है, ने जो नान औफि ारूल रैजोल्यू ान रखा था, मै उसे समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्पीकर

साहब, वैसे तो कांस्टीच्यू ान में अमैंडमैंट हो चुकी हैं यह अमैडमैंट होने के बाद भी हाईऐस्ट अथोरिटीज है, उन्होने भी सिफारि ा की है कि इस कन्साईनमैंअ टैक्स लागू किया जाए। 28.05.1984 केा मुख्य मंत्रियों की बैठक में भी सिफारिश की गई थी कि यह अमैडमैंट करके सैट्रल सेल्ज टैक्स एक्ट को अमैड किया जाए। इसके लिए कोर्ठ नया लैजिस्ले ान इस बारे में पास किया जाए। जो जोनल कौसिल है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदे ा चण्डीगढ़ ओर जम्मू का मीर भाामिल है, वहां पर भी यह सिफारि ा की गयी थी। कहने का मतलब यह है कि नौदर्न जोनल कौसिल ने यह भी सिफारि ा की है कि इस कन्साईनमैंट टैक्स को लागू होना चाहिए। लेकिन पता नही इतनी हाईऐस्ट अथारिटी के सिफारि ा के बावजूद भी यह कन्साईनमैंट टैक्स क्यों नही लगाया जा रहा है? यह आमदनी का साधन तो है ही, लेकिन इसके ने लगने से एक नुक्सान भी है। (व्यवधान व भाोर) यह ठीक है कि इससे 50–60 करोड रूपया सालाना कानुक्सान है लेकिन यह जो फैक्ट्रीज यहा पर उत्पादन करती है, यह यहां पर प्रदूशण भी करती है। फरीदाबाद जो हमारे यहां पर एक नया भाहर बसा था, वह लोगों ने अपने लिए रैजीडैन्ा ीलय सईट्स बनाने के लिए बनाया था। लेकिन इन्ही इंडस्ट्रीज के लगने की वजह से एयर पौल्यू ान और वाटर पौल्यू ान बहुत ज्यादा हो रही है ऐयर पौल्यू ान की वजह से लोगों का वहा पररहना दु वार हो गया हैं फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज का गन्छा पानी अल्टीमेंटली जमुना मे ंपहुंचता है और वही पानीआगे जगार

वाटरसप्लाई स्कीम क तहत ड्रिकिंग परपजिज के लिए इस्तेमान हेताहै। इसी तरह से सोनीपत के अन्दर है। वहां पर भी ड्रेन नं0 8 के द्वारा सारे का सारा गन्दा पानी जमुना नदी में जाता है। जमुना से उसी गन्दे पानी को दिल्ली के अन्दर वाटर सप्लाई स्कीम के तहत सप्लाई किया जाता हैं इस पर भी बहुत खर्चा आता हैं मेरा कहने का मतलब यह है कि इन इंडस्ट्रीज की वजह से सिवरेज और वाटर सप्लाई के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। खासतौर पर जो दिल्ली के आस पास के इलाके है, उनमें यह बहुत समस्या है। दिल्ली के आस पास के जितने भी क्षेत्र है, चाहे वह फरीदाबाद है, बहादुरगढ़ है या सोनीपत है, वहां पर जो अन्डर ग्राउन्ड पानी है, वहा खारा हैं खारा पानी होने के नाते वाटर सप्लाई स्कीम्ज कैनाल वेस्ड है। कैनाल बेस्ट स्कीम्ज पर टयूबवैल बेस्ट स्कीम के मुकाबले में, कम से कम तीन गुना या चार गुना खर्च ज्यादा आता। इस तरह से इस प्रदू ाण को दूर कारेन के लिए, चाहे वह सिवरेज का हो या गन्दे पानी का हो, हमारी सरकार को खर्चा करना पड़ता है लेकिन जो कुछभी इंडस्ट्रीज वहां पर उत्पादन करती है, उसका फायदा दूसरे उठाते है। अब ये दखा गया है कि तकरीबन 100 मीडिय और लार्ज स्केल यूनिट्स 1987 के बाद लगे है। इनके लगने से कितन पौल्यू ान हुआ होगा, इस बात को आप अन्छाजा लगा सकते हैं इस समय वहां पर इतना प्रदूशण हो रहा है। कि आम आदमियों के लिए रहना मु कल हो रहा हैं एयर पौल्यू ान भी बहुत ज्यादा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन कम होती जा रही है।

जमीन भी इन लार्ज इंडस्ट्रीज की वजह से और अर्बेनाइजे ान की वजह से बहुत कम होती जा रही है किसान के पास अब जमीन बहुत कम होती जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के आस–पास जमीन बहुत कीतती है जो जमीन किसानों की थी, अब वह इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गइ है। इंडस्ट्रीज लगने से बहुत सी जमीन उनक बब्जे में चली गयी ह। इस तरह से उसकस जो फायदा था, व किसानों को बिलकुल ळाी नही हो रहा है। और न ही सकरार को हो रहा है। यह बात ठीक है कि उस समय का नुक्सान 50 करोड़ रूपए का अन्दाजा लगाया गया हो। आज कांस्टीच्यू ान अमेडमैंट को हुए भी 9 साल हो चुके है। अगर कम सके कम नुक्सान यानी 50 करोड़ रूपये सालाना के हिसाब से भी अन्दाज लगाया जाए तो 9 सालों में 450 करोड़ रूपये सीधा ही नुक्सानहेा चुका हैं इसके अलावा, प्राईस एस्काले ान का अगर अन्छाज लगाया जाए, क्येकि 1982 से लेकर अब तक बहुत ज्यादा प्राईस राईज हो चुकी है, अब तक कम से कम 1500 करोड़ रूपये का नुक्सान हरियाणा को हो चुका है। इसलिए मै कहता हूं कि हरियाण इसएिल ज्यादा महसूस कर रहा है क्योंकि दिल्ली के आस पास चारो ंतरफ हरियाणा के अन्छर इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं धारूहेडा, बल्लम्भगढ, रोहतक, पलवल, सोनीपत और पानीपत सभी जगह पर इंडस्ट्रीज लगी हुइ है। लेकिन इन सब के हैड आफिस दिल्ली में बने हुए है। यहां पर जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है उनसे प्रदूशण तो मिले हमें लेकिन उसका फायदा हो दिल्ली का यह कोई अच्छी बात नही हैं। कसाईनमैंट अैक्स न लगने के कारण बहुत स कल्याणकारी काम

रूके पड़े हे। जैसा कि इस बजट में कहा गया है, 71 पैसा हमे मिल जाए तो हम और भी अधिक पैया देहाती क्षेत्र पर खर्च कर सकते है। यमुनागर में पावर हाउस बनाया जा रहा है। उस पर एक हजार करोड़ रूपया लगेगा और हरियाणा सरकार ने भी अपना भोयर देना हैं यह पावन प्लांट जो लग रहा है, उसके खर्चे के लिएपैसे का साधन जरूरी हैं अध्यक्ष महोदय, मै इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं हम सब को इस प्रस्ताव का यूनानिमसली समर्थन करना चाएि ओर पर्सनल लैवल परकोि ा ा करें कि यह कंसाइनमैंट टैक्स लगे। मै दुबारा इसका समर्थन करता हूं क्योंकि यह हरियाणा की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है।

श्री महेन्द्र सिंह (रोहट): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में हमारी एक साथी ने यह प्रस्ताव रखा थ। कंसाइनमैंट टैक्स के बारें में चर्चा चल रही हैं सन् 1982 में इसबात पर चर्चा उठाई गई थी कि जो चीज जिस प्रदे ा मे बने, जिस प्रदे ा मे किसी चीज का उतादन हो उसका टैक्स उसी प्रदे ा को मिलना चाहिए। इस बात से उस प्रदे ा की तरक्की जुड़ी हुई होती है, लोगों का विकास जुडा हुआहोता है अगर किसी प्रदे ा की इन्कम नही होगी तो वह अपनी नीतियों पर कैसे अमल कर सकता हैं? फैडरल सिस्ट आफ गवर्नमैंट में तीन प्रकार की की लिस्ट है। एक सेन्ट्रल लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कंकरैन्ट लिस्ट। सेन्ट्रल लिस्ट में वे सबजैक्ट्स आर्ति है। जिस पर सैन्ट्रल गवर्नमैंअ भी और स्टेट

गवर्नमैंट भी टैक्स लगा सकती है। अगर किसी बात परसेन्टर और स्टेट में सहमति न हो तेा सन्टर की चलती है। मै कहना चाहता हूं कि कंसाइनमैंट टैक्स न लगने से हरियाणा प्रदे ा को दो सौ करोड़ रूपए का नुकसान हो रहा है।, इसलिए केन्द्रीय सरकार को यह बात लेनी चाहिए। न मानने के कारण ही हम सभी साथी इस पर चर्चा कर रहे है। पिछले साल भी यह ात आई थी। उस वक्त भी हमने इसके समर्थन मे ंहयही बात कही थी जो आज कह रहे है। मै यह कहना चाहता हूं कि चालीस बयालीस साल पहले, हिन्दुस्तान आजाद हुआ था, उस क्क्त जो लोग सत्ता में थे, वे विकास के प्रति सजग थे लेकिन उसे बादहालता बदलते रहे है। 1966 में हरियाणा प्रदे ा अलग बन गया। हरियाणा ने अपनी जिम्मेदारी आप संभाली उसे बाद यह जरूरी थी कि कुछ पैसा हरियाणा सरकार अपने ढंग से जुटा पाए, लेकिन साधनों की कमी के कारण वह नही हो पाया। चौधरी देवी लाल ने अनेक वायदे किए ओर चौधरी साहब ने उनवायदों को पूरा किया। अध्यक्ष महोदय, इस सदन मे ंएम्पलाइज की बात आई और सदस्यों ने यह कहा कि एम्पलाईज की मांगों को पूरा नही किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मै सदन को बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने 115 करोड़ रूपए का फायदा गवर्नमैंट एम्पलाईज की सहायता की लेकिन फिर भी प्रद ान होते रहे। अध्यक्ष महोदय, अगर यह कंसाइनमैंट टैक्स हरियाणा को मिले तो हरियाणा की आमदनी बढ़ सकती है और सरकार अपने ऐम्पलाइज की ओर ज्यादा ध्यान दे सकती हैं आमदनी कम होने के कारण ऐसी प्रोब्लम खड़ी हो

जाती है अगर पूरी आमदन हो तेा काफी समस्याएं हल हो सकती है ंअध्यक्ष महोदय, मै इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ओर मांग करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि हरियाणा प्रदे ा की जो दो सौ करोड़ की आमदनी का नुक्सान होता है, व न हो। अध्यक्ष्य महोदय, मै दुबारा इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

खाद्य एवं आपूति मंत्री (श्री नर सिंह ढांडा): अध्यक्ष महोदय, 1988 में हमारे इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री रणजीत सिज जी ने कंसाईनमैंट टैकस के बारें में एक रैजोल्यू ान इस सदन में प्रस्तुत किया था कि हरियाणा के अन्दर जो सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई है। उनकाफायदा सिर्फ दिल्ली याचण्डी में ही उठाया जा रहा है। क्योकि फैक्ट्रीज के हैड आफिस इन्ही जगहो पर है। इस कारण हरियाणा प्रदे ा को 200 करोड का सालाना नुक्सान हो रहा है। अभी मरे भाई कैला ा जी कह रहे थे हरियाणा मे ंबुढापा पैन् ान के कारण 105 करोड़ रूपए का अतिरिक्तभार पड़ा है। यह उनकी बात सत्य है ंहरियाणा में बूढे लोगों को मान सम्मान देने के लिए सरकार के लिए ऐसा करना जरूरी था। सरकार की यह इन्टैन् न अच्छी थी कि हरियाणा के अन्दर बूऐ लोगों को मान बढ़ाया जाए। यह कोई बुरा काम नही था लेकिन उनको बोलने का लहजा कुछ ऐसा था जिसस ऐस लगता था कि हरियाणा के न्दा बुढापा पैन् ान नही दी जानी चाहिएं थी।

श्री कैला ा भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था क प्र न है। मेरी यह बिल्कुल मन् ाा नही हथी। मेरा कहने का मतलबकेवल इतनाथा कि हम जब बुढापा पैन् ान कर रहे है, उस पर 105करोड़ रूपऐ का अतिरिक्त व्यय होना है तेा इसके साथ साथ हमें कन्साईनमैंट टैक्स लगाकर हरियाणा प्रांत की आय की भी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हरियाणा की आर्थिक हालत बरकरार रहे। जो धन हम खर्च कर रहे है, उसको जुटाने का भी हमे प्रावधान करना चाहिए।

श्री नर सिंह ढांडा: हरियाणा में फरीदाबाद, धारूहेड़ा, कालका, यमुनानगर जैसे ऐसे भाहर है जहां पर बडत्री मात्रा मैं फैक्ट्रीज लगी हुई हैं लेकिन इनकी आमदनी हरियाणा को न जाकर, केवल दिल्ली व चण्डीगढ़ को ही जा रही है जैसा कि मेने पहले बताया है कि हरियाणा इन फैक्ट्रीज से होने वाली आमदन से इसलिए वंचित रह रहा है। क्योंकि इन फैक्ट्रीज के अपने हैड आफिसिज दिल्ली या चण्डीगढ़ में हैं जो वे फैक्ट्रीज है, उनमें हरियाणा के मजदूर होने की जाय बाहर के बजबदूर काम कर रहे है। ऐसा होने से हरियाणा का दोहरा नुक्सान हो रहा हैं एम्पलायमैंट भी हमारे हरियाणा के लोगों को नही मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, यह बडी दुख की बात है प्लांट्स हमारे लगते है, हमारी धरती पर फैक्ट्रीज चलाई जा रही है। दिल्ली और पानी हरियाणा दे रहा है लेकिन उसकी कमाई कन्साईनमैंट टैकस के रूप में हमें नही मिल रही है। हरियाणा को इसका फायदा होने

की बजाये नुकसान हो रहा है। यहां हाउस में यह भी कहा गया कि चौधरी देवी लाल जी ने जनता के साथ यह वादा किया था कि हमें दिल्ली जाने दो, हम पैसों की बोरियों का मुंह हरियाणा की तरफ कर देगे। मै तो बड़े फख्र के साथ यह कह सकता हूं कि चौधरी देवी लाल जी ने जनता केसाथ जो वायदे किये थे, किसानो के साथ जो वायदे किए थे, गरीबों के साथ जो वायदे किए थे,उनको पूरा कर के भी दिखाया है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री कैला ा चन्द्र भार्मा: कौन से वायदे पूरे किये है? (ाोर) कोई स्कूल अपग्रेड नही हुआ हैं लोगों को कोई कर्जा माफ नही हुआ है।

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, ऐसी बात नही है। स्कूल भी अपग्रेड किए गये है। कैला ा जी, आपकी ओर से कोई इस बारे में रैजोल्यू ा नही पहुंचा होगा। आप भाायद भारत द र्ान वाले दिनों को देख रहे होगों आपको पता नही है। आपने इस बारे में कोई मांग नही भेजी होगी। जिन सदस्यों की जो जो मांगे आई है, वे सभी पूरी हुई हैं अगर स्कूलों की अपग्रेड के बारे में कोई मांग आती है तो अव य ही आपके हल्के के स्कूल अपग्रेर्ड होते हैं अध्यक्ष महोदय, मै बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं कि मेरे ये भाई भारतभ्रमण पर थे। कभी सम्राट होटल में तो कभी किसी ओर जगह पर आते जाते है ओर साजि ो करते रहते थे। अगर इनको अपने इलाके की कार्ई चिन्ता हेाती तो सरकार के ऊपर बार बाद दबाव डालते लेकिन इनको तो केवल अपने स्वार्थो

की ही पड़ी थी। भाायद इनको यह भी नही मालूम होरहा होगा कि चौधरी देवी ला लजी पैसे की बोरिया का मुह हमारी तरफ कैसे खाल रहे है। भाई कैला ा जी, आप तो अपने हल्कों में ही नही जाते। अगर आप वहां जाए तो आपको पता चले कि सरकार ने क्या कुछ नही किया। चौधरी देवी लाल जी का राज तो राम राज था और आज भी राम राज है। चाहे बुढापा पैन् ान हो, चाहे किसानो किसानो की फसलों का मुआवजा हो, सभी को सरकार ने रहात दी है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदे ा, महाराश्ट्र और दूसरे अन्य प्रदे ाों में एक बात सोची जाती है। कि अगर चौधरी देवी लाल जी हरियाणा में बुढापा पैन् ान लगा सकते है, चौधरी देवी लाल जी किसानों का कर्जा माफ कर सकते है। तो उनकी स्टेट क्यो नही कर सकती। विपक्ष के भाई और कांग्रेस के लोग जिनमें खासतौर पर श्री भजन लाला और श्री बसी लाल की सरकार ने भी हरियाणा का आइडिया लेकर किसानों के कर्ज माफ किए है। इसके अलावा कई किसानों के खेतों में स नहर निकाली गई हैं नहर के दोनों किनारों पर जो दरख्त लगे हो है, वे किसानों की फसल का नुक्सान करते है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि उनमें से आधे दरख्तों का मालिक उस किसान को बनाया जाए जिसकी जमीन में वे दरख्त पड़ते है। (विध्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि हरियाणा के हर अदारे में बहुत प्रोगैस हा सकती थी। अगर यह कनसाइनमैंट टैक्स हमें मिल जाता, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्टस के दफ्तर दिल्ली में होने की वजा से हरियाणा को आमदन नही हो

रही है। और व`हरियाणा का विकास नही होने दे रहे है। मै चाहता हूं कि इस रैजोल्यू ान को पास करके जल्दी केन्द्र की सरकार को भेजा जाए। यह मामला बहुत लम्बित हो रहा है। ऐसा होने के कई कारण है। हमारे साथी कह रहे थे कि आपकी सरकार को भी डेढ़ साल हो गया है। आपने क्या किया? स्पीकर साहब, आज तक किसी भी अपोजी ान के भाई ने ऐसा रेजोल्यू ान मूव नही किया। हरियाणा ने सबसे पहले राइट टू वर्क को रैजोल्यू ान मूव नही किया। हरियाणा ने सब से पहले राइट टू वर्क का रैजोल्यू ान पास करके भेजा औ उसे बाद यह रैजाल्यू ान मूव करवाया।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, इन्होने यह प्रस्ताव पास करने मे ंही अढ़ाई साल लगा दिए है और इनमे ंक्या उम्मीद हो सकती है?

श्री नर सिंह ढांडाः स्पीकरसाहब, हम इस परबहस तो पूरी कर लै तभी पास करके भेजगे। मेरा तो एक ही अनुराध है कि इस रैजोलू ान को जल्द पास करके केन्द्र से कहा जाए कि इस टैक्स को लागू किया जाए।

स्थानीय भाासन राज्य मंत्री (श्री काान्ति प्रका ा भल्ला): अध्यक्ष महोदय, आज से तीनसाल पहले हमारी साथी श्री रणजीत सिंह ने यह रैजोल्यू ान पे ा किया थ। इस पर काफी देर से चर्चा हो रही है। हमारे सामन`भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे

है। वे जब भी कोई बात करते है तेा सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थोप देते है। (विध्न) स्पीकर साहब, 1987 से पहले चौधरी देवी लाल ने हरियाणा की जनता से कुछ वायदे किए थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथी भी हमारे साथ थे। उस समयलोक दल सरकार इनके सहयोग से बनी थी। चौधरी देवी लाल जी ने जनतासे जितने वायदे किए थे वह सारे पूरे कर दिए। अध्यक्षम होदय, दिल्ली में जो सकरार बनी, उसमे ंहमारे ये साथी भी थे। मै इनसे कहना चाहूंगा कि आप उस समय इकसी पास करते। 11 महीने केन्द्र में जो सरकार रही, उसमे आपकी पार्टी भी भागीदारी थी। उस वक्त आपने इस बारें में कोई बात नही की। (ाोर)

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, इस समय इस डिस्क ान के लिए विशय नही है। माननीय मंत्री जी को इस समय इसका जवाब थोड़े ही देना है। यह तो इस तरह से बोल रहे है। जैसे इसका जवाब दे रहे हो। इस समय तो यह विशय है कि हम इस रैजोल्यू ानक का समर्थन करें।

श्री अध्यक्षः भार्मा जी, आप बैठिए।

श्री कााांन्ति प्रका ा भल्लाः अध्यक्ष महोदय, तीन साढ़े तीन साल के अर्से में हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदे ा की जनता के लिए बहुत ही जन कल्याण के काम किए है। हरियाणा दे ा की सीमाएं दिल्ली के तीन तरफ लगती हैं दिल्ली के नजदीक हरियाणा की सीमा में जितनी भी फैक्ट्रीज है उने मालिकों को

जमीन हरियाणा ने दी है, बिजली हरियाणा देता है, जितनी भी सुविधाए दी गई हैं वह सारी हरियाणा सरकार ने दी है, लेकिन उन लोगों ने अपने हैड ऑफिस दिल्ली में बनाए हुए है, इसलिएउन सभी फैक्ट्रियों का सारा माल दिल्ली में ले जा कर बेच देते है, जिसके कारण हरियाणा प्रदे ा को जो टैक्स मिलना चाहिए वह नही मिल पाता हैं वह टैक्स दिल्ली की सरकार को मिलताहै। मै समझता हूं कि जितने इंडस्ट्रीयलिस्टस को हरियाणा सरकार न`सुविधाए दी है, उनकी प्रोडक्ान पर टैक्स का फायदा हरियाणा प्रदे ा को मिलना चाहिएक्योकि हरियाणा के अन्दर दिलली के नजदीक जितनी भी फैक्ट्रीज है, उनके लिए हरियाणा सरकार ने जमीन दी, बिजली दी और लोन दिया तथा दूसरी सुविधाए दी, इसलिए उनकी प्रोडक ान पर टैकस का फायदा हरियाणा प्रदे ा का होना चाहिस। इन भाब्दों के साथ मै इस रैजोल्यू ान का समर्थन करता हूं और यह सिफाारि ा करता हूं कि यह रैजोल्यू ान पास किया जाए जिससे कंसाइनमैंट टैक्स लागू हो सके ओर हमरे प्रदे ा की आमदनी बढ़े ताकि जो अधूरे कार्य है, जैसे कैला ा चन्द भार्मा कह रहे थे कि स्कूल नही बनते, उन स्कूलों को बनाया जा सके।

श्री मोहम्मद असलम खा (छछरौली): अध्यक्ष महोदय, मै इस रैजोल्यू ान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह ठीक बात है कि दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा की सीमाएं लगती है ओर सीमा में जितनी भी फैक्ट्रीज का माल वह अपने हैड

ओफिस में ले जा करबेचते है। लकिन अध्यक्षमहोदय, बडे अफसोस की बात है कि यह रैजोल्यू ान 1988 से पे ा हुआ ओर आज 1991 आ गया यानी चार साल हो गए, हम इसकें अभी तक पास नही कर पाए हैं इसको तो आज से दो तीन साल पहले ही पास करके केन्द्रीय सरकार के पास भेज देना चाहिए था।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, यदि इस रैजोल्यू ान परसभी माननीय सदस्य बोलेगे तो इसको पास करने मे ंटाईम तो लगेगा ही। सभी माननी सदस्य इस रैजोल्यू ान पर बोलना चाहते है।

श्री मोहम्मद असलम खाः स्पीकर साहब, इस तो दो चार घंटे बहस करके इसे पास किया जसकात था और केन्द्रीय सरकार को भेजा जा सकता था, लेकिन चार साल तक बहस होती रहे ओर फिरभी पास न हो जबकि सभी माननीय सदस्य इसकासमर्थ कर रहे है, यह बडत्रे अफसोस की बात है। यदि आप लोग हरियाणा की जनता को कंसाइनमैंट टैक्स लागू करके फायदा पहुंचाना चाहत है तो यह आज से दो साल पहले ही पास करके केन्द्रीय सरकार को भेज दिया जाना चाहिए था। डेढ साल तक केन्द्र में जो आपकी सरकार रही, उससे पास करवा लेते। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आपने इस ओर तवज्जो ही नही दी। इन भाब्दों के साथ मै इसका समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री ि ाव प्रसाद (अम्बाला): अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव है, इस परसभ साथियों ने अपने विचार व्यक्त किए है। इस पर बोले हुए किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध नही किया। जब से इस पर बहस होती रही तब से इसका किसी ने विरोध नही किया? बलिक समर्थन किया है। फिर भी इसे पास न किया जाये मुझे यह समझ नही आत। इस कन्साईनमैंट अैक्स ` आने से हरयिाणा प्रदे ा को काफी आमदनी होगी और उस आमदनी से प्रदे ा के विकास के काम होगे, लेकिन हर बार इस प्रस्ताव पर बोलते हुए डेढ़ बज जाता है। ओर इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। कई बार गैर सरकारी दिन को सरकार सरकारी काम में बदल लेती है, जिसकी वजह से इस पर बहस नही हो सकती। स्वयं सरकार ही नही चाहती ककि यह प्रस्ताव पास हो जाए। (ाोर एवं व्यवधान) सरकार की यह एक साजि ा है। साजि ा यह है कि जिन लोगों की यहां पर फैक्टीज लगी हुई है ओर जिनका माल यहां पर तैयार होता है, जिनके दफ्तर दिल्ली में है या बारह है, उनमें मिल जाते है ओर उनहें कहते हे कि देखो, हम सदन में तो इस प्रस्ताव के हक में बोलेगे, लेकिन इसे पास नही होने देगे। (ाोर) पास इसलिए नही होने देते क्योंकि उनसे इन्हे गाहे–बगाहें चुनाव के लिए या किसी और काम के लिए पैसा मिलता है। (विध्न एव भाोर) इनकी उनके साथ मासिक बंधी हुई है।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मास्टर जी भी सुबह उनसे मिलकर आये है कि देखो हम इसे हम में बोलेगे लेकिन इसे पास नही होने देगे।

श्री ि ाव प्रसादः अगर यह संकल्प पास हो गया तो इनकी वह रा ि ा मिलनी बंदहो जायंगी। ये जानबूझ कर इसको पास नही होने देना चाहते क्योकि उनसे ये भारी रा ि ा लेना चाहते है। (ाोर) अगर यह पैसा हरियाणा को आ जाये तो उससे हरियाणा का विकास होगा। (ाोर) आपको चुराव के लिए पैसा मिलता है। इसलिए जानबूझ कर पास नही होने देना चाहते। (ाोर) अब मै कहना चाहता हूं कि अब से पहल जा दिन निक चुके है, सो निकल चुके, इससंकल्प को जल्दीसे ज्दली पास किया जाए ताकि आने वाले समय में हरियाणा के हितों का फायदा हो सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस संकल्प को आज ही पास कर देना चाहिए। धन्यवाद।

तकनीकी ि ाक्षा राजय मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, जो नोन–औफिकि ायल रैजोल्यू ान इस सदन के पूर्व विधायक चौधरी रणजीत सिंह ने रखा था, मै इसके समर्थन मं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्पीकर साहब, मरे भाई असलम खा जी ने इस पर बोलनते हुए बड़ा ऐतराज किय कि इस नौन–औफि ायल रैजोल्यू ान को लटकाया जा रहा है। मै इनकी इस बात से सहमत नही हूं और उनसे पूछता हूं कि 1982 मे जब केन्द्र में इनकी पार्टी की सरकार थी ओर वह जनता दल

की सरकार बनने के तक सत्ता में रही तो इन्होने इसे क्यों लटकाया रखा? चौधरी असलम खा जी को यह बा कहते हुए कुछ सोचना चाहिए था। (विध्न) जब 1982 में कांग्रेस पार्टी केहाथ में सत्ता थी तो इस कन्साईनमैंट टैक्स लागू न करके केन्द्र सरकार ने हिन्दूस्तान के सभी प्रदे ाों के साथ अन्या किया ओरउनके हम को छीना (विध्न एवं भाोर)

Mr. Speaker: You please take your seat. Now the Leader of th Opposition wants to say something.

वाक आउट

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, इस रैजोल्यू ान पर बहुत डिस्क ान हेा चुकी है। अण्डर रूल 89 मैं मूव करता हू।

That the questo be now put.

और इस डिस्क ान को बन्द करके इस रैजोल्यू ान को पास कर दिया जाए।

श्री अध्यक्षः यह स्टेज नही है। अभी तो मंत्री जी बोल रहे है। आप कृपया बैठे।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, ऐसा लगता है कि सरकार इस डिस्क ान को लम्बा खीचना चाहती हैं ओर इ रैजोल्यू ान केापास नही करवानाचाहती हैं हम चहाते है कि इस को आज ही पास किया जाए। (विध्न एवं भाोर) स्पीकर सर, अगर सरकार आज

इस रैजोन्यू ान को पास नही करना चाहती तो हम इसे प्रोटैस्ट में सदन से वाट आउट करते है। (ाोर)

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, यह सारे हरियाणा के हित का मामला है। इसलिए इसे आज ही पास करवा जाए। सारे सदन की इच्छा है कि इसे आज ही पास किया जाए। (विध्न एवं भाोर) स्पीकर साहब, यह प्रजातन्त्र की हत्या है, इसे दो साल से अधिक समय हो गया हैं हरियाणा के हित की बात होते हुए भी अगर सरकार इसे पास करने क लिए तैयार नही है तो हम भी वाक आउट करते है। (ाोर)

(इस समय भारतीय जनता पाटी और जनता दल पार्टी के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)

गैर–सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्षः मिस्टर मदान आप कन्टीन्यू करे।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर साहब, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहे है कि जनता दल (एस) के लोग इस रैजोल्यू ान को पास नही होने देते लेकिन ये लोग इसे लिए कितना सहयोग दे रहे है? (विध्न) ये मैदान छोड़ कर भाग रहे है। (ाोर) मास्टर ि ाव प्रसाद जी जब बोले थे तो उनहोने कहा था कि सत्ता दल के लोग इस नौन आफि ियल रैजोल्यू ान को पास नही होने दे रहे है लेकिन अब खुद ही मैदान छोड़ कर भाग रहे है। (विध्न)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, सरकार की नीयत इस रैजोल्यू ान को पास करने की थी। सरकार की यह मन ाा थी सारी पाटिया मिल कर इसके पास करती तो बहुत अच्छी बात होती। पता नही इन लोगों ने अपने मन में क्या योजना बना रखी है हाउस का एक मिनट का समय हरता है और ये वाक आउट कर गए। इन्होने सोचा होग कि वाक आउट कर लो और इसके सांझीदार न बनो। स्पीकर साहब, ये लोग अन्दरखाने समझौता करके आए थे ताकि यह रैजोल्यू ान पास न हो सके।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर साहब, मै यह कह रहा था था 1982 मे केन्द्र में कांग्रेस पाटी की सरकारथी।

श्री अध्यक्षः अब आप बैठे। आप कटिन्यू करेगे। अब हाउस कल सुबह 9.30 बजे तक ऐडजर्न किया जाता है।

13.30 बजे

(तत्प चात सदन भाुक्रवार दिनांक 15 मार्च, 1991 प्रातः 9.30 बजे तक स्थगित हुआ।)